

• बीमा योजना का लाभ नहीं • कलंक मिटाने की कोशिश

In Pursuit of Truth

आक्षर

पाक्षिक

www.akshnews.com



पार्षद से राज्यपाल तक का राफर

वर्ष 18, अंक-21

1 से 15 अगस्त 2020

पृष्ठ-48

मूल्य 25 रुपये

R.N.I. NO.HIN/2002/8718 M.P. BPL/642/2018-20



नए भारत का भूमिपूजन



मानवीय प्रधानमन्त्री श्री निरेन्द्र दामोदर दास मोदी ज
के कर कमलों द्वारा
जय श्री राम

शुद्ध सौंदी वजन 22600 ग्राम

दिनांक 5 अगस्त 2020 समय दोपहर 12:15:15



Anu Sales Corporation



We Deal in Pathology & Medical Equipments

Ground Floor, 17/1, Shanti Niketan, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023

☎ M. : 9329556524, 9329556530, ✉ E-mail : ascbhopal@gmail.com

● इस अंक में

मप्र कांग्रेस

9

में चिंतित नहीं हूँ...

रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था। ऐसा ही कुछ हाल मप्र कांग्रेस का है। पार्टी के एक-एक कर 25 विधायक भाजपा में शामिल हो चुके हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष कमलनाथ कहते हैं कि...

राजकाज

14-15

मजबूती या मजबूरी

पार्टी विश्व डिफरेंस वाली भाजपा इन दिनों खिचड़ी पार्टी बन गई है। मप्र सहित देशभर में दूसरी पार्टियों के नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। इस संदर्भ में भाजपा नेताओं का कहना है कि यह हमारी पार्टी की मजबूती का प्रमाण है।

चौसर

16

किसान भरोसे

जिस किसान कर्जमाफी को मुद्दा बनाकर कांग्रेस ने करीब डेढ़ साल पहले अपने डेढ़ दशक के राजनीतिक वनवास को समाप्त किया था, उसके सहारे ही अब एक बार फिर कांग्रेस उपचुनाव में जीत की राह तैयार करने की जुगत में है। भाजपा भी इसी मुद्दे...

योजना

18

आत्मनिर्भर मप्र का प्लान

केंद्र की मोदी सरकार की ओर से शुरू किए गए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप शिवराज सरकार तैयार कर रही है। मध्य प्रदेश के आत्मनिर्भर बनने के रोडमैप को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जनता के सामने...

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28



5 अगस्त 2020 का दिन भारत की संस्कृति, संस्कार और आध्यात्मिक विरासत का एक बहुत ही पावन और ऐतिहासिक पड़ाव होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम के जन्म स्थान अयोध्या में उनके भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य का भूमिपूजन इसी दिन होगा। करीब 500 वर्षों बाद यह पावन दिन आया है। इसकी खुशी और भावुकता हम सभी समझ सकते हैं। कभी-कभी घोर आश्चर्य होता है कि प्रभु श्रीराम के जन्म स्थान पर उनका एक भव्य मंदिर बनाने में आजाद भारत को 70 साल लग गए।



19



21



36



44

राजनीति

30-31

दीदी का दम

कई बड़े और छोटे राज्यों को भाजपा ने फतह कर लिया है, लेकिन पश्चिम बंगाल को फतह करने की उसकी मंशा अभी तक अधूरी है। पार्टी को उम्मीद है कि 2021 के विधानसभा चुनाव में वह पश्चिम बंगाल में भगवा झंडा फहरा सकती है। लेकिन दीदी यानी ममता बनर्जी को मात...

राजस्थान

35

महारानी मौन क्यों?

राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच चल रही तनातनी और उसकी वजह से पैदा हुई सियासी उथल-पुथल के बीच प्रदेश की एक कद्दावर नेता की खामोशी तमाम नेताओं की बयानबाजी से भी ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई है।

उत्तरप्रदेश

37

मिशन 2022

उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का सियासी संग्राम दिन पर दिन तेज होता जा रहा है। दरअसल, प्रियंका गांधी की नजर 2022 पर है। टारगेट है विधानसभा चुनाव और वहां की 403 सीटें। बचपन से राजनीति देखती, सुनती, समझती प्रियंका गांधी अब खुद राजनीति के...

6-7 अंदर की बात

41 महिला जगत

42 अध्यात्म

43 कहानी

44 फिल्म

45 खेल

46 व्यंग्य



जिंदा रहने के खातिर एक-दूसरे से दूरी बहुत जरूरी है...

पी रजादा काश्मि का एक शेर याद आ रहा है...

अपने खिलाफ फैसला खुद ही लिखा है आपने।
हाथ भी मल रहे हैं आप, आप बहुत अजीब हैं!!

दरअसल, ये पक्तियां हमारे माननीयों पर सटीक बैठ रही हैं। देश में कोरोनावायरस का संक्रमण शुरू होते ही माननीयों ने आम जनता से अपील की कि वे इस संक्रमण से बचने के लिए एक-दूसरे से दूरी रखें। लेकिन वे खुद इसका पालन नहीं कर पाए। इसका परिणाम यह हुआ है कि क्या आम क्या ब्रास, वायरस सभी पर हमला कर रहा है। माननीय भी इस महामारी की चपेट में आ रहे हैं। ऐसा कोई देश या प्रदेश नहीं है जहां कोरोना ने माननीयों को चपेट में न लिया हो। मप्र में तो सरकार के मुखिया के साथ ही उनके मंत्रिमंडल के कई सदस्य भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। दरअसल, पहले मंत्रिमंडल गठन, फिर विभागों के लिए मार्गदर्शी और उसके बाद उपचुनाव के लिए भागमभाग के चलते माननीय कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी की गई गाइडलाइन का पालन नहीं कर पाए। कोरोना का प्रसार देखकर यह तो साफ है कि यह एक संक्रमित व्यक्ति से कईयों को प्रभावित कर रहा है। सरकार में बैठे माननीयों ने इसके लिए गाइडलाइन बनाई और आम जनता को इसका पालन करने के लिए कठोरता भी दिखाई। इसके लिए चालानी कार्रवाई भी की गई, एफआईआर किया गया, कुछ को जेल भेजा गया। लेकिन माननीय खुद इसका पालन नहीं कर रहे हैं। जब माननीयों में संक्रमण फैलने लगा तो भाजपा संगठन ने निर्देश जारी किया कि कोई भी नेता सामाजिक राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल न हो। दरअसल, माननीयों का कोरोना से पीड़ित होना इस बात की अनिवार्यता को एक बार फिर स्थापित कर रहा है कि क्यों इस वायरस को जरा भी हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कदम-कदम पर सावधानी बरती। वे पूरे प्रदेश से इस रोग से बचाव के उपाय अपनाने के लिए अपील करते रहे। मंत्रिमंडल की बैठक हो या कोई और अवसर, मुख्यमंत्री मास्क के बिना नहीं दिखे। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन उन्होंने किया। ऐसे में यकीनन उनसे कोई बहुत ही मामूली चूक हुई होगी, जिसके चलते वह खुद ही इस रोग की चपेट में आ गए हैं। तो जरा सोचिए कि हम तो छोटी नहीं, बल्कि बहुत बड़ी चूक को खुद ही अंजाम देने पर तुले रहते हैं। मास्क लगाने में हिचकते हैं। किसी से दूरी बनाए रखने से पहले यह सोचते हैं कि कहीं अगला हमें डरपोक न समझ ले। तो हम यह बता दें कि आप इस खतरे को खुद के साथ ही साथ पूरे समाज के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। आज लगभग संपूर्ण विश्व कोरोना महामारी से पीड़ित है। इस महामारी से बचने का इस समय एकमात्र ही उपाय है कि हम सरकार की गाइडलाइन का पालन करें। यह राजनीति चमकाने का समय नहीं, बल्कि अनुशासन का मंत्र जपने का समय है। आम हो या ब्रास जिसने भी अनुशासन का उल्लंघन किया उसे कोरोना अपनी चपेट में लेने से तनिक भी नहीं चूकेगा। इसलिए हम सभी को मिलकर यह प्रण लेना पड़ेगा कि जब तक इस महामारी से मुक्ति का मार्ग नहीं मिल जाता, तब तक हमें धैर्य धारण करके रहना होगा। क्योंकि...

**इंसानों को इंसानों से जो दूर करे ये कैसी मजबूरी है।
जिंदा रहने के खातिर एक-दूसरे से दूरी बहुत जरूरी है।।**

-राजेन्द्र आगाल

आक्षिप्त
अक्षर

वर्ष 18, अंक 21, पृष्ठ-48, 1 से 15 अगस्त, 2020

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :

प्लॉट नम्बर 150, जौन-1 मनोरमा कॉम्प्लेक्स,

एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर

भोपाल- 462011 (म.प्र.),

फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788

email : akshmagazine@gmail.com

Website : www.akshnews.com

RNI NO. HIN/2002/8718 MPEPL/642/2018-20

ब्यूरो

मुंबई :- ऋतुन्द्र माथुर, कोलकाता:- इंद्रकुमार,

जयपुर:- आर.के. बिनानी, छत्तीसगढ़:- संजय

शुक्ला, मार्केण्डेय तिवारी, टी.पी. सिंह,

लखनऊ :- मधु आलोक निगम।

प्रदेश संवाददाता

094251 25096 (इंदौर) विकास दुबे

098276 18400 (जबलपुर) धर्मेन्द्र कथुरिया

094259 85070, (उज्जैन) श्यामसिंह सिकरवार

094259 85070, (मंदसौर) धर्मवीर रत्नावत

098934 77156, (विदिशा) ज्योत्सना अनूप यादव

देशीय कार्यालय

नई दिल्ली : ईसी 294 माया इन्वेल्वे मायापुरी-

फोन : 011 25495021, 011 25494676

मुंबई : बी-1, 41 शिव पार्वती चेंबर प्लॉट नंबर 106-110 सेक्टर-21

नेरूल, नवी मुंबई-400706 मो.-093211 54411

कोलकाता : 70/2 हजरा रोड कोलकाता

फोन-033 24763787, मोबाइल: 09331 033446

जयपुर : सी-37, शांतिपथ, रयाम नगर (राजस्थान)

फोन- 0141 2295805, मोबाइल-09829 010331

रायपुर : एमआईजी 1 सेक्टर-3 शंकर नगर, फोन : 0771 2282517

भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर, भिलाई,

मोबाइल 094241 08015

इंदौर : 39 बुद्धि सिल्टर निगानिया, इंदौर

मोबाइल - 094251 25096

स्वातंत्रिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटेड, प्लॉट नं. 150, जौन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा कॉम्प्लेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।



जल्द बने कोरोना की दवा

कोरोनावायरस ने दुनियाभर में पैर पसार लिए हैं। देश सहित दुनियाभर में कोरोनावायरस की दवा (वैक्सीन) बनाने के प्रयास चल रहे हैं। भारत में भी वैक्सीन बनाने के प्रयास तेजी से जारी हैं। आशा है जल्द ही वैक्सीन तैयार कर ली जाएगी, जिससे लोगों को बचाया जा सकेगा।

● **कुणाल शर्मा**, भोपाल (म.प्र.)



कुपोषण की समस्या से मिलकर लड़ना होगा

प्रदेश सहित देशभर में कुपोषण एक बड़ी समस्या है। सरकार द्वारा प्रदेशभर में पोषण अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन कई क्षेत्रों में बच्चे अब भी कुपोषण से उभर नहीं पा रहे हैं। इसको लेकर प्रदेश सरकार को और अधिक सजग होने की जरूरत है। सरकार के साथ-साथ लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। कुपोषण जैसी समस्या को खत्म करने के लिए सभी को जागरूक होने की जरूरत है। तभी इस समस्या से लड़ा जा सकता है। मप्र में कुपोषण किसी आपदा से कम नहीं है। सरकार आंकड़ों के मुताबिक यहां हर दिन करीब 92 बच्चे कुपोषण के कारण काल के गाल में समा रहे हैं। हम सभी को इस समस्या से मिलकर लड़ना होगा।

● **श्यामू वर्मा**, रायसेन (म.प्र.)

कोरोना में ऑनलाइन क्लास ही बेहतर

कोरोना के कारण बच्चों के स्कूल नहीं खुले हैं, लेकिन वे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। जिससे बच्चे और अभिभावक दोनों खुश हैं। हाल की स्थिति को देखते हुए बच्चों की पढ़ाई के लिए यह कदम सबसे सही है। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए उठाए गए उपायों के तहत देशभर में 16 मार्च से 1.5 लाख स्कूल बंद हैं और करीब 25 करोड़ बच्चे स्कूल बंद होने से प्रभावित हैं। जब तक इस महामारी का पूरी तरह सफाया नहीं हो जाता तब तक बच्चों को स्कूल भेजना उचित नहीं होगा।

● **अकित राठी**, नई दिल्ली

मनरेगा में भ्रष्टाचार

लॉकडाउन के बाद दूसरे प्रदेशों और शहरों से बेरोजगार होकर गांव पहुंचे श्रमिकों के लिए मनरेगा बड़ा संबल बना है। लेकिन मनरेगा में भ्रष्टाचार की बात को भी नकारा नहीं जा सकता। प्रदेशों में पूर्व में स्वर्गवासी हो चुके लोगों को भी मनरेगा में काम करते दर्शाया जा चुका है।

● **वर्षा तिवारी**, इंदौर (म.प्र.)

बिजली की समस्या का हल

मध्यप्रदेश सौर ऊर्जा उत्पादन के मामले में बिरमौर बन गया है। सौर ऊर्जा उत्पादन में मध्यप्रदेश देश में अग्रणी स्थान पर है। विश्व की सबसे बड़ी परियोजना में भी सौर परियोजना शामिल है। इससे देशभर के हजारों गांवों में बिजली की समस्या को हल किया जा सकेगा।

● **गायत्री पांडे**, जबलपुर (म.प्र.)



सिंधिया को मिला सम्मान

भाजपा में ज्योतिरादित्य सिंधिया को वो सम्मान मिल रहा है, जो कांग्रेस में रहते हुए शायद उन्हें नहीं मिल पाया। मप्र सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर विभागों के बंटवारे तक सिंधिया ने के बागी विधायकों को महत्व दिया गया है। भाजपा में ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिल रहे इस सम्मान से कई भाजपाई नेता नाराज हैं।

● **राहुल सिंह**, सागर (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल



फिर आमने-सामने एलजी और दिल्ली सरकार

दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच एक बार फिर से तलवारें खिंच चुकी हैं। इस बार दिल्ली में पिछले दिनों हुए कौमी दंगों की अदालत में चल रही सुनवाई के लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से पैरवी करने वाले वकीलों का मुद्दा दोनों के मध्य बड़ी टकराहट बनता जा रहा है। एलजी चाहते हैं कि इस मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा सुझाए गए वकीलों को नियुक्त किया जाए तो दूसरी तरफ राज्य सरकार अपने पैनल के वकीलों की नियुक्ति पर अड़ी हुई है। सरकार का कहना है कि सरकारी मामलों में पैरवी करने के लिए वकील नियुक्त करना उसके अधिकार क्षेत्र में आता है इसलिए एलजी को इसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार कतई नहीं है। सरकार का यह भी कहना है कि दिल्ली पुलिस इन दंगों की सही तरह से जांच नहीं कर रही है जिसके चलते अदालतों में कई बार पुलिस की कार्यशैली पर प्रश्न उठाए हैं। ऐसे में पुलिस की पसंद के वकील नियुक्त करना जायज नहीं होगा। लेकिन एलजी अपने स्टैंड पर अड़ गए हैं। दिल्ली सरकार ने एक बार फिर कैबिनेट मीटिंग में अपने प्रस्ताव पर चर्चा कर पुलिस द्वारा सुझाए पैनल को टुकरा दिया है। जानकारों की मानें तो अब यह मामला राष्ट्रपति को भेजा जा सकता है। अगर ऐसी स्थिति आती है तो यह निश्चित है कि टकराव और बढ़ेगा।

माया का बढ़ता भाजपा प्रेम

उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती अपने 'सुर' समय अनुसार बदलने के लिए कुख्यात हैं। अपनी सुविधानुसार कभी वे धर्मनिरपेक्ष ताकतों के साथ जुगलबंदी कर लेती हैं तो कभी भगवामयी हो जाती हैं। भ्रष्टाचार के जरिए अकूत संपत्ति कमाने के आरोपों का भी मायावती संग चोली-दामन का रिश्ता है। ऐसे में लंबे अर्से से सत्ता सुख वंचित बहनजी एक बार फिर से भगवा खेमे की तरफ झुकती नजर आ रही हैं। राजस्थान में गहलोट सरकार पर मंडरा रहे संकट के दौरान मायावती का स्टैंड भाजपा के पक्ष में स्पष्ट नजर आ रहा है। खबर है कि बसपा प्रमुख ने अपनी पार्टी के नेताओं को भी भाजपा के खिलाफ बयानबाजी न करने की सख्त हिदायत दे रखी है। जानकारों का कहना है कि मायावती भाजपा पर सीधे आक्रामक रुख अपनाने से इसलिए बच रही हैं क्योंकि उन्हें डर है कि केंद्र सरकार आय से अधिक संपत्ति के मामले में केंद्रीय जांच एजेंसियों की जांच का आदेश दे सकती है। गौरतलब है कि यदि ऐसा हुआ तो मायावती शासनकाल में हुए कई घोटालों की जद में उनके भाई आनंद की भूमिका का पर्दाफाश उनके लिए बड़ी मुसीबत बन जाएगा। पार्टी सूत्रों का यह भी कहना है कि समाजवादी पार्टी संग बसपा का चुनावी गठबंधन बेहद निराशानजर रहा इसलिए बहनजी 2022 के विधानसभा चुनावों में भाजपा संग गठजोड़ का रास्ता बंद नहीं करना चाहती हैं।



नादानी ने फंसाया

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोट पुराने और अनुभवी नेता हैं। अशोक गहलोट राजनीति में आने से पहले अपने पिता की तरह ही पेशेवर जादूगर थे। पायलट उनके बिछाए जाल में उलझ गए। प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे को बदलने की मांग हो या उसी सरकार की गाहे-बगाहे आलोचना की जिसमें उनकी हैसियत दूसरे नंबर की थी, पायलट युवा होने के कारण अपेक्षित परिपक्वता और धैर्य नहीं दिखा पाए। बेशक सरकार में उनकी और उनके मंत्रियों की ज्यादा नहीं चल रही होगी पर वे सब रखते तो आने वाले वक्त में हालात उनके अनुकूल हो सकते थे। विधायक दल की बैठक में न आकर, सिंधिया से मुलाकात कर और हरियाणा के होटल में पनाह लेकर उन्होंने आलाकमान की नजर में अशोक गहलोट के इस आरोप को पुख्ता कर दिया कि वे मुख्यमंत्री पद की चाह में भाजपा के हाथों में खेल रहे हैं। जबकि भाजपा ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का कभी भरोसा नहीं दिया होगा क्योंकि पार्टी के 72 विधायकों को इस बात के लिए रजामंद करने से पहले वसुंधरा राजे को मनाना पड़ेगा। पायलट ने कह जरूर दिया कि वे कभी भाजपा में नहीं जाएंगे पर जिस सीमा तक वे आगे बढ़ चुके हैं, वहां से कांग्रेस में भी उनकी वापसी अब आसान कहां बची है।

चौतरफा विरोध

देवस्थानम बोर्ड बनाकर जैसे बर्क के छत्ते में हाथ डाल दिया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने। सूबे के चार धामों की विश्वव्यापी मान्यता, प्रतिष्ठा और महत्व प्राचीनकाल से चला आ रहा है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन से सनातन धर्म में मोक्ष की प्राप्ति का द्वार खुलने की धारणा चली आ रही है। पार्टी के धुरंधर नेता सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने तो सरकार के खिलाफ उत्तराखंड हाईकोर्ट में ही याचिका दायर कर रखी है। स्वामी इस फैसले के मुखर आलाचकों में हैं। उनके सुर में सुर मिलाने वालों की संख्या बढ़ रही है। पार्टी के पूर्व सूबेदार और नैनीताल के सांसद अजय भट्ट ने भी मुख्यमंत्री को चेताया है कि एक तरफ तो विपक्ष इसे मुद्दा बना रहा है दूसरी तरफ समाज में भी इसे लेकर गुस्सा है। नुकसान दो साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ सकता है। भट्ट ने मुख्यमंत्री को सलाह दे डाली है कि जनभावनाओं का आदर करते हुए वे इस अध्यादेश को या तो वापस ले लें या इसमें संशोधन करें।

प्रियंका को खाने का न्यौता

राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी द्वारा रात्रिभोज के निमंत्रण का लाजवाब जवाब दे राजनीतिक शिष्टता का पालन भी कर डाला है और इस न्यौते से बचने का रास्ता भी तलाश लिया। खबर है कि बलूनी ने प्रियंका गांधी को उन्हें सपरिवार डिनर पर बुलाने का न्यौता भेजने पर धन्यवाद देते हुए कोरोना महामारी के चलते हाल-फिलहाल इस निमंत्रण को स्वीकार न कर पाने की विवशता की बात कही है। उन्होंने पत्र में पिछले दिनों कैसर जैसी गंधीर बीमारी से खुद के ग्रसित होने का हवाला देते हुए प्रियंका को सपरिवार उत्तराखंडी भोज पर आने का आग्रह भी किया है। बलूनी ने प्रियंका गांधी को लिखे अपने पत्र में कहा है कि जब वे नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे तो आप और आपके परिवार को उत्तराखंडी भोजन पर आमंत्रित करना चाहेंगे। इस बीच 35 लोधी रोड खाली करने जा रही प्रियंका ने बलूनी और उनकी पत्नी से फोन पर बात कर उनके लंबे जीवन की कामना करते हुए उन्हें नए घर की बधाई दे डाली है।

जुगत नहीं आई काम

सत्ता का सानिध्य पाना हर किसी का सपना होता है। चाहे आमजन हो या नेता या फिर ब्यूरोक्रेट्स या कोई और, हर किसी की यह कोशिश रहती है कि उसे किसी भी तरह सत्ता की छत्रछाया मिले। ऐसी ही लालसा से पिछले दिनों एक जिले के शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों की पत्नियों ने सरकार के मुखिया की पत्नी का सानिध्य पाने के लिए कोशिश की, लेकिन उनकी जुगत काम नहीं आई। गौरतलब है कि सरकार के मुखिया की धर्मपत्नी शिव साधना में लीन रहती हैं। राजधानी ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में उनकी भक्ति भावना ख्यात है। सावन में तो वे नियमानुसार हर सोमवार को महाकाल की पूजा-अर्चना करती हैं। बिना सरकारी तामझाम के वे एक भक्त की तरह मंदिर जाती हैं। एक सोमवार को जब वे महाकाल की शरण में पहुंची तो यह खबर पाकर वहां के दोनों शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों की पत्नियों ने भी मंदिर का रुख किया। उनकी प्लानिंग थी कि वे शिव साधना में जुटी सरकार के मुखिया की धर्मपत्नी से जैसे भी हो दोस्ती की जाए। उन्होंने मंदिर में उनकी परिक्रमा भी की ताकि वे उनसे मुखातिब हों लेकिन उन्होंने दोनों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। अब इसे कोरोना संक्रमण का इफेक्ट कहें या फिर कुछ और... लेकिन दोनों अधिकारियों की पत्नियां अपनी दाल गलती न देखकर मायूस होकर घर लौट आईं।

आईएम बैक...

शासन और प्रशासन के गलियारों में सक्रिय रहने वाले अधिकांश लोग शीर्षक पढ़कर ही समझ गए होंगे कि हम यहां किसकी बात कर रहे हैं। जिस तरह 'मैं हूँ न' सुनते ही लोगों के जहन में शिवराज सिंह चौहान की छवि घूम जाती है, वैसे ही आईएम बैक का तकिया कलाम भी लोगों ने खूब सुना है। दरअसल, इस तकिया कलाम को गाहे-बगाहे बोलने वाली मैडम की शासन में वापसी हुई है। उनमें मीटिंग-मीटिंग खेलने का जुनून रहता है। रहे भी क्यूं नहीं, उनका खेलों के प्रति रुझान जो रहता है। मैडम खेल के साथ ही राजनीति की भी माहिर खिलाड़ी हैं। इसलिए उनमें कुछ गुरुर भी भरा हुआ है। इसकी वजह पारिवारिक पृष्ठभूमि भी है। मैडम कुछ विराम के बाद सत्ता में वापस आई हैं तो उनमें फिर से पहले वाला गुरुर भर गया है। विभाग के अधिकारी जब भी किसी समस्या को उनके सामने उठाते हैं तो वे कहती हैं- आईएम बैक, चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन मैडम का यह तकिया कलाम सुन-सुनकर अधिकारी भी पक गए हैं। काम हो या न हो, फाइल आगे बढ़े या न बढ़े, लेकिन हर बात में मैडम आईएम बैक बोल देती हैं। दरअसल, मैडम के आईएम बैक में उनका गुरुर झलकता है। इस गुरुर के कारण ही वे शासन-प्रशासन की प्रिय नहीं बन पाई हैं।



महामारी से कैसे मिले निजात

कोरोना संक्रमण प्रदेश में विकराल रूप लेता जा रहा है। लेकिन जिस विभाग के ऊपर इसको नियंत्रित करने की जिम्मेदारी है, उसके जिम्मेदार साहेबानों में सामंजस्य ही नहीं है। कहने को तो विभाग में एक आयुक्त, दो-दो प्रमुख सचिव और एक एसीएस भी पदस्थ हैं। लेकिन आयुक्त महोदय और एसीएस में पटरी ही नहीं बैठती है। एसीएस अपनी प्लानिंग में जुटे रहते हैं तो आयुक्त महोदय अपना राग अलापते रहते हैं। आलम यह है कि आयुक्त न तो प्रमुख सचिवों और न ही एसीएस से मिलते हैं। इससे विभाग में अपनी डफली-अपना राग वाली स्थिति हो गई है। इससे सरकार की नीतियों का भी ठीक से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। सूत्रों की मानें तो विभागीय अधिकारियों के बीच अबोला की स्थिति और सामंजस्य नहीं होने के कारण कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ाई ठीक से नहीं हो पा रही है। इसका खामियाजा विभाग को उठाना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार ने कोरोना संक्रमण को किल करने का जो संकल्प लिया है वह कैसे पूरा होगा, यह सवाल उठने लगा है। यहां बता दें कि पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में कोरोना के संक्रमण के मामले में बेतहाशा वृद्धि हुई है। खासकर राजधानी में सबसे अधिक मामले आए हैं।

विधायकी की जुगाड़

इस कोरोनाकाल को परिवर्तनकारी माना जा रहा है। इस कोरोनाकाल के समापन के बाद राजनीतिक, सामाजिक स्तर पर कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे। इसको देखते हुए कुछ लोग अभी से अपना जुगाड़ लगाने में जुट गए हैं। ऐसा ही जुगाड़ इन दिनों एक चिकित्सक लगा रहे हैं। ये महाशय प्रदेश की राजधानी के सबसे बड़े कोविड-19 अस्पताल में सेवाएं दे रहे हैं। संघ से जुड़े इन जनाब के हाथ अपना नंबर बढ़ाने का मौका भी मिल गया है। दरअसल, ये महाशय सत्ता के शीर्ष की सेवा में लगे हुए हैं। गाहे-बगाहे इनकी कोशिश रहती है कि किसी भी तरह वे सरकार के मुखिया के सामने जाएं और उनकी सेवा में लगे रहें। उनके इस सेवाभाव को देखकर जब लोगों ने पड़ताल की तो पता चला कि वे शाजापुर से विधायक का चुनाव लड़ने की मंशा पाले हुए हैं। इस कारण वे सरकार के मुखिया की सेवा कर मेवा पाने का प्रयत्न कर रहे हैं। यहां बता दें कि ये जनाब प्रदेश के एक स्वनामधन्य संत के भाई हैं, जो दिवंगत हो गए हैं। अब देखना यह है कि डॉक्टर साहब की मेहनत रंग लाती है या फिर उनकी कोशिश बेकार जाती है।

भाग्य हो तो ऐसा

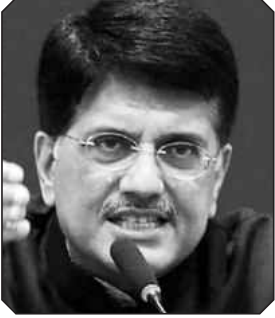
राजनीति में भाग्य का भी बड़ा खेल होता है। कई नेता ऐसे होते हैं, जिनकी जनता के बीच पकड़ मजबूत होती है। उनकी लोकप्रियता के आगे अच्छे-अच्छे फीके नजर आते हैं। लेकिन उनका भाग्य ऐसा होता है कि उन्हें न तो चुनाव लड़ने का मौका मिलता है और न ही कोई बड़ा पद। वहीं कुछ नेता ऐसे होते हैं जो भाग्य के भरोसे अच्छे से अच्छा मुकाम पा लेते हैं। मप्र की राजनीति में इन दिनों ऐसे ही एक नेता खूब चर्चा में हैं। वैसे तो राजधानी भोपाल की एक विधानसभा सीट से दूसरी बार विधायक बने माननीय मंत्री बनने का सपना देख रहे थे, लेकिन उनका नंबर नहीं लग पाया। फिर भी वे धैर्य धारण किए रहे। इसका फायदा यह हुआ कि उन्हें वह पद मिल गया जिसके नीचे सभी मंत्रियों और विधायकों को आना पड़ा है। कल तक मंत्रियों के पीछे-पीछे रहने वाले इन विधायक महोदय का जलवा अब इस कदर छा गया है कि उनका इंतजार अब मुख्यमंत्री तक को करना पड़ता है। विधायक महोदय के भाग्य से कई लोग जलने लगे हैं और कहने लगे हैं भाग्य हो तो ऐसा हो।

अक्स का आईना



चीन चाहता तो आराम से कोरोनावायरस रोक सकता था, उसने जानबूझकर इसे फैलने दिया। इसमें कोई शक नहीं कि कोरोनावायरस चीन से ही निकला है। उन्हें इसे बाहर नहीं निकलने देना चाहिए था। लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाए, जिसका नतीजा दुनिया देख रही है।

● डोनाल्ड ट्रम्प



रेलगाड़ियों के निजीकरण के लिए बोली मंगाई जा रही है और इसके लिए अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। सरकार भारतीय रेल के स्टेशन को आधुनिक बनाने जा रही है। उसके बाद उन्हें नीलामी के जरिए निजी क्षेत्र के हाथ सौंपा जाएगा। सरकार यह कदम इसलिए उठा रही है, ताकि रेलवे में बड़ा निवेश हो सके। इसका फायदा देश के साथ ही आमजन को भी होगा।

● पीयूष गोयल



ओडिशा सरकार मेरे साथ हमेशा खड़ी रही है। सरकार की ओर से मुझे 2015 से आर्थिक मदद की जा रही है। मैं इस बात को गर्व के साथ कह रही हूँ, लेकिन मैंने फेसबुक में अपनी बीएमडब्ल्यू कार बेचने की बात क्या कही, लोगों ने उसे मेरी आर्थिक तंगी से जोड़ दिया। इससे मैं दुखी हूँ। बेवजह लोग ओडिशा सरकार को भी टारगेट कर रहे हैं।

● दुतीचंद



दिल्ली में लोगों को घर-घर राशन पहुंचाने के लिए हमने योजना को मंजूरी दी है। अब सरकार एफसीआई के गोदाम से गेहूं उठाकर पिसवाएगी और चावल व चीनी आदि की भी पैकिंग की जाएगी। इसके बाद लोगों के घर राशन पहुंचाया जाएगा।

● अरविंद केजरीवाल



बॉलीवुड में नेपोटिज्म है यह बात सब स्वीकारते हैं। मैं जब इसकी बात करती हूँ तो न जाने क्यों लोगों को मिर्ची लगती है। इनसाइडर को मिर्ची लगती है तो यह सही है, लेकिन कई आउटसाइडर भी हैं, जिन्हें मेरी बात अच्छी नहीं लगती है। इनमें तापसी पन्नू, स्वरा भास्कर और ऋचा चड्ढा भी शामिल हैं। यह दुखद है। मैं नहीं जानती कि मुझे क्या कहना चाहिए, लेकिन मैं उनकी जगह पर रह चुकी हूँ जो लोग बाहर से बॉलीवुड में आते हैं। हम आउटसाइडर्स को अपने पैरेंट्स के घर का कंफर्ट नहीं मिलता है। मैं अनिल कपूर या महेश भट्ट की बेटी नहीं हूँ। जब बात तापसी पन्नू, स्वरा भास्कर और ऋचा चड्ढा की होती है तो मैं समझ सकती हूँ कि उन पर अपने घर के बिल भरने का प्रेशर है। हर कोई जैसे नहीं जीना चाहता जैसे मैं जीती हूँ। इसलिए मैं समझ सकती हूँ कि उन पर कितना प्रेशर है।

● कंगना रनौत

वाक्युद्ध



कोरोना काल में सरकार की उपलब्धियां- फरवरी में नमस्ते ट्रम्प, मार्च में मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, अप्रैल में मोमबत्ती जलवाई, मई में सरकार की 6वीं सालगिरह, जून में बिहार में वर्चुअल रैली और जुलाई में राजस्थान सरकार गिराने की कोशिश। इसीलिए देश कोरोना की लड़ाई में 'आत्मनिर्भर' है।

● राहुल गांधी

पिछले 6 महीनों में राहुल गांधी की उपलब्धियां यह हैं- मार्च में शाहीन बाग और दंगे, मार्च में ही ज्योतिरादित्य सिंधिया और मप्र सरकार की हार, अप्रैल में मजदूरों को उकसाने, मई में ऐतिहासिक चुनावी हार की 6वीं वर्षगांठ, जून में चीन की वकालत और जुलाई में राजस्थान में पार्टी का विनाश।

● प्रकाश जावड़ेकर





मैं चिंतित नहीं हूँ...

रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था। ऐसा ही कुछ हाल मप्र कांग्रेस का है। पार्टी के एक-एक कर 25 विधायक भाजपा में शामिल हो चुके हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष कमलनाथ कहते हैं कि मैं चिंतित नहीं हूँ। उनके इस कथन के बाद अब कांग्रेस में ही सवाल उठने लगे हैं कि आखिर वे कब चिंतित होंगे? पार्टी खत्म हो जाएगी तब?

इस साल होली के दौरान कांग्रेस में शुरू हुई भगदड़ इस कदर जारी है कि अब तक 25 कांग्रेस विधायक भाजपा की सदस्यता ले चुके हैं। होली के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके साथ 22 विधायकों ने बगावत करके कांग्रेस से इस्तीफे दे दिया था और कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ गई और गिर गई थी। इसके बाद भाजपा ने सरकार बना ली थी। अब जुलाई में प्रद्युम्न सिंह लोधी, सुमित्रा देवी कासेडकर और नारायण पटेल के पार्टी छोड़ने के बाद मप्र में कांग्रेस विधायकों की संख्या 89 रह गई है। वहीं भाजपा विधायकों की संख्या 107 है, अब 24 की जगह 27 सीटों पर उपचुनाव होंगे। यही चुनाव तय करेंगे कि कांग्रेस मप्र में वापसी करेगी या फिर भाजपा सरकार बचाने में कामयाब होगी।

एक पखवाड़े में तीन विधायकों के इस्तीफे के बाद भी प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ कह रहे हैं, 'मैं चिंतित नहीं हूँ।' करेला और नीम चढ़ा की बात यह कि कांग्रेस एक सर्वे के आधार पर दावा कर रही है कि उपचुनावों में भाजपा केवल एक सीट जीत सकेगी। कमल का आत्मविश्वास। लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार यह दावा कांग्रेस किस दम पर कर रही है। भाजपा के प्रत्याशी तो लगभग तय हैं, लेकिन कांग्रेस अभी भी हवाहवाई दावे कर रही है। दरअसल, प्रदेश में सत्ता जाते ही कांग्रेस छिन्न-भिन्न हो गई है। संगठन पूरी तरह चरमरा गया है।

इस सबके चलते हो यह रहा है कि कांग्रेस अपने विधायकों को संतुष्ट और भरोसा नहीं दिला पा रही है, जिसके कारण विधायकों का कांग्रेस से मोह भंग हो रहा है। कांग्रेस के नेतृत्व पर वे नेता भी सवाल उठाने लगे हैं जो कुछ महीने पहले तक कमलनाथ मंत्रिमंडल का हिस्सा थे। कमलनाथ सरकार के सबसे वरिष्ठ मंत्रियों में गिने जाने वाले गोविंद सिंह का धैर्य भी लगता है चुकने लगा है। बकौल गोविंद सिंह- कांग्रेस का संगठन कमजोर है। हमें संगठन की मजबूती पर

हाथ छोड़ सकते हैं और 10 विधायक

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री ऐंदल सिंह कंधाना और भाजपा नेताओं की मानें तो कांग्रेस के कम से कम 10 और विधायक उपचुनाव से पहले भाजपा में आ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से यह कांग्रेस के लिए जोर का झटका लगने वाली बात हो जाएगी। बताया जाता है कि भाजपा के रणनीतिकार 30 से 35 सीटों पर उपचुनाव के लिए रणनीति बनाने में जुट गए हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में पहले 2 विधानसभा सीटों जौरा और आगर में विधायकों के निधन के बाद उपचुनाव होने थे। इसी दौरान 22 कांग्रेसी विधायकों ने त्यागपत्र देकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। इस कारण 24 सीटों पर उपचुनाव की तैयारी हो गई है। लेकिन इसी बीच बड़ामलहरा के कांग्रेसी विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी, नेपालगर विधायक सुनीता देवी कासेडकर और मांधाता के नारायण पटेल भी भाजपा में शामिल हो गए और अपनी विधायकी से इस्तीफा दे दिया। इस तरह अभी तक 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। भाजपा सूत्रों का कहना है कि पार्टी जिन 10 विधायकों को भाजपा में लाने की तैयारी कर रही है, उनमें से 7 विधायक पहले से ही संपर्क में हैं।

ध्यान देना चाहिए। अगर संगठन मजबूत होता तो विधायक कांग्रेस छोड़कर नहीं जाते। जिन गांधी परिवार के खिलाफ बोलना कांग्रेस में प्रतिबंधित है, उस गांधी परिवार के चश्मों-चिराग राहुल गांधी के बारे में भी वे बोले। गोविंद सिंह ने कहा कि कांग्रेस में एकल नहीं सामूहिक नेतृत्व होना चाहिए कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे ब्रजेंद्र सिंह की माने तो कांग्रेस के संगठन में कोई कमी नहीं है। वे कहते हैं, अतिमहत्वाकांक्षी लोगों पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। ऐसे लोग जो

जीत कर आए, लोगों ने उन्हें कांग्रेस की नीतियों पर भरोसा कर वोट दिया ऐसे विधायकों का ध्यान अब जनता को भी रखना चाहिए। जाहिर है कि राठौर भी नैतिक शिक्षाओं की कहानियों जैसे संवाद अदा कर रहे हैं। बिखराव को रोकने का उनके पास भी कोई फार्मूला नहीं है। चर्चा में तो उमंग सिंधार भी हैं। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से कमलनाथ पर भी निशाना साधा है, और केंद्रीय नेतृत्व को प्रदेश की स्थिति पर फोकस करने की नसीहत दी है।

पूर्व मंत्री उमंग सिंधार का कहना है कि वाकई में जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, उसको देखते हुए मध्य प्रदेश और राजस्थान में केंद्रीय नेतृत्व को फोकस जरूर करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा है कि आज कुछ लोग खुद नेता बनना चाह रहे हैं, जबकि पार्टी उन्हें नेता बनाती है। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस उपाध्यक्ष संजय मसानी को लेकर किए गए ट्वीट पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि एक समय मसानी ने कहा था कि मैं धर्म और अधर्म की लड़ाई के चलते कांग्रेस के साथ धर्म की लड़ाई में हूँ, इसलिए वह अपने जीजा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी धर्म के बारे में कुछ ज्ञान दे दें। तो साफ है कि प्रदेश में जो कमलनाथ पहले सरकार और संगठन के मुखिया थे, अब वे केवल संगठन के मुखिया बने हुए हैं। जो पहले उनके सुर में मिलाने वाले अब उन पर उंगली उठाने लगे हैं। ये भी याद रखिए ये वो लोग हैं जो पार्टी में बने हुए हैं। अब इनकी नहीं सुनी तो मान लीजिए जैसे केंद्रीय नेतृत्व ने संगठन को उसकी नियति पर छोड़ दिया है। वैसे ही किसी दिन नियति नेतृत्व को भी अकेला ही छोड़ देगी। वैसे कांग्रेस का भला अब शायद तब ही हो। मप्र के राजनीतिक इतिहास में यह पहला अवसर है जब किसी एक राजनीतिक दल के विधायकों ने इतनी बड़ी संख्या में अपनी पार्टी नेतृत्व के प्रति अविश्वास दिखाया है।

● अरविंद नारद

मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमेशा सक्रिय रहते हैं और अपने मंत्रियों तथा अधिकारियों को भी सक्रिय रखते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने अपनी चौथी पारी में मंत्रियों को विभाग देने के बाद उन्हें काम पर भी लगा दिया है। मुख्यमंत्री ने दो दिनों तक मंत्रियों से वन-टू-वन चर्चा कर उन्हें उनके विभाग से संबंधित कार्यों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए होमवर्क दे दिया है।

मंत्रियों को होमवर्क

मंत्रिमंडल गठन और विभागों के बंटवारे के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पूरा फोकस अब विकास कार्यों पर है। इसलिए उन्होंने गत दिनों मंत्रियों के साथ वन-टू-वन चर्चा कर उन्हें सरकार और संगठन की मंशा से अवगत कराया तथा उन्हें होमवर्क भी दे दिया। इस दौरान उन्होंने न केवल मंत्रियों से उनके विभागों का रोडमैप जाना बल्कि उन्हें ये भी बताया कि उनके विभागों की प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए। उन्होंने जुलाई का पूरा वक्त मंत्रियों को अपने विभाग को समझने और उनके टारगेट फिक्स करने के लिए दिया है और यह कहा है कि अगस्त से वह सभी विभागों की समीक्षा खुद करेंगे।

दरअसल, मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को होमवर्क के साथ फ्री हैंड भी दिया है। उन्होंने ओम प्रकाश सकलेचा, मंत्री, लघु सूक्ष्म मध्यम उद्यम विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को प्रदेश में सिंगल सिटीजन डेटाबेस तैयार करने, प्रदेश में सभी नागरिकों उद्योगों को दी जा रही सेवाओं के लिए एकीकृत पोर्टल विकसित करने, उद्योग केंद्र की व्यवस्थाओं को विश्वस्तरीय बनाना, साइबर सिक्योरिटी की रणनीति बनाना, एमएसएमई के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की समीक्षा करने का होमवर्क दिया है। इसी तरह विश्वास सारंग, मंत्री, चिकित्सा शिक्षा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग को मेडिकल कॉलेजों की अधोसंरचनाओं एवं सेवाओं को उच्च स्तर पर बनाए रखना और इन्हें और बेहतर बनाने का होमवर्क दिया है।

गिरराज दंडोतिया, राज्यमंत्री, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग को मंडी अधिनियम के संशोधित प्रावधानों को लागू करने, बीमा योजना का एंड टू एंड कम्प्यूटराइजेशन, मोटे अनाज फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने, एफपीओ को बढ़ावा देना, मार्केट लिंकेज स्थापित करने का



मंत्रियों को समीकरण साधने की जिम्मेदारी

मध्य प्रदेश की 27 विधानसभा सीटों के लिए सितंबर-अक्टूबर में संभावित उपचुनाव की तैयारी में शिवराज सरकार जुट गई है। मंत्रियों को इन क्षेत्रों में चुनावी समीकरण साधने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके मद्देनजर विभागीय स्तर पर निर्णय भी लिए जा रहे हैं। लोक निर्माण विभाग ने उपचुनाव वाले क्षेत्रों में सड़क, पुल व पुलिया के काम मंजूर किए हैं तो खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग ने 36 लाख ऐसे उपभोक्ताओं को रियायती दर पर राशन देने का निर्णय लिया है, जिन्हें पात्रता पर्ची नहीं मिल रही थी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने मनरेगा सहित अन्य योजनाओं के कार्यों की गति बढ़ा दी है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने कमलनाथ सरकार द्वारा निरस्त की गई नगर परिषदों को फिर से अस्तित्व में लाने की अधिसूचना जारी कर मतदाताओं को संदेश दिया है। सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि चुनावी क्षेत्रों से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता से पूरा किया जाए। दरअसल, मुख्यमंत्री की कोशिश है कि वे मंत्रियों को आगे करके उपचुनाव में जाएं, ताकि जनता के सामने अविश्वास की स्थिति न रहे।

होमवर्क दिया गया। वहीं डॉ. प्रभुराम चौधरी, मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को जिला स्तर के अस्पतालों व सेवाओं को उच्च स्तर पर बनाए रखना, बेहतर करने का होमवर्क दिया गया है।

उधर, महेंद्र सिंह सिसोदिया, मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को मनरेगा के माध्यम से रोजगार सृजन-जल संरक्षण कार्यों का क्रियान्वयन, महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से रोजगार के अवसर, मनरेगा के माध्यम से टिकाऊ अधोसंरचना का विकास, पीएमजीएसवाय की सड़कों का संधारण, समय पर कार्य पूर्ण करने का होमवर्क दिया है।

प्रद्युम्न सिंह तोमर, मंत्री, ऊर्जा विभाग को आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत 2 प्रतिशत अतिरिक्त राजकोषीय घाटा जुटाने हेतु सुधार, विद्युत बिलों में दी गई छूट उपभोक्ताओं तक पहुंचे, इसकी लगातार समीक्षा करने, बिजली सब्सिडी सही व्यक्ति को मिले इसकी रणनीति बनाना, बिजली आपूर्ति 24x7 (घरेलू व व्यावसायिक) तथा 10 घंटे (कृषि क्षेत्र) रहे इसका होमवर्क दिया है। वहीं हरदीप सिंह डंग, मंत्री, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा, पर्यावरण को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार प्रगति, पर्यावरणीय स्वीकृति की व्यवस्था की लगातार समीक्षा करने का होमवर्क दिया गया है।

राजवर्धन सिंह प्रेम सिंह दत्तीगांव, मंत्री, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के स्तर में सुधार के लिए



कांग्रेस का आरोप- यह दिखाता है

मनरेगा के काम में तेजी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने लॉकडाउन में लौटे प्रवासी श्रमिकों सहित ग्रामीणों को रोजगार दिलाने के लिए मनरेगा के काम तेजी से प्रदेश में शुरू कराए हैं। चुनाव क्षेत्र वाली पंचायतों में इन कामों की गति अधिक है। इसे लेकर सियासत भी होने लगी है। पूर्व सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ. गोविंद सिंह ने इसे मजदूरी घोटाला करार देते हुए जांच की मांग की है। डॉ. सिंह का कहना है कि चुनाव वाले क्षेत्रों में फर्जी मस्टर रोल तैयार कर चहेतों को उपकृत किया जा रहा है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने सुरखी सहित अन्य नगर परिषदों को फिर से अस्तित्व में लाने की अधिसूचना जारी कर दी है। सुरखी विधानसभा का उपचुनाव होना है। यहां से कांग्रेस के गोविंद सिंह राजपूत विधायक थे, जिन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर सिंधिया के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। राजपूत शिवराज सरकार में राजस्व और परिवहन मंत्री हैं।

रणनीति, प्रदेश में निवेश आमंत्रित करने के लिए लगातार प्रयास, सिंगल विंडो का सही मायने में क्रियान्वयन, अनुमतियों की प्रक्रिया का सरलीकरण एवं कम्प्यूटराइजेशन, औद्योगिक केंद्रों की व्यवस्था को विश्वस्तरीय बनाने का होमवर्क दिया गया है। वहीं भारत सिंह कुशवाहा, राज्यमंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण (स्वतंत्र प्रभार), नर्मदा घाटी विकास विभाग को प्रदेश में उद्यानिकी फसलों का विस्तार, एफपीओ (कृषक उत्पादक समूहों) को बढ़ावा देना, 2024 तक एनवीडीए/नर्मदा जल आधारित परियोजनाओं को पूरा करने पर रणनीति, उद्यानिकी फसलों के लिए मार्केट लिंकेज स्थापित किए जाने के प्रयास करने का होमवर्क दिया गया है।

इंदर सिंह परमार, राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) को स्कूली शिक्षा में शिक्षा की गुणवत्ता सुधार की रणनीति, ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े स्कूल स्थापित करने एवं बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए अच्छी परिवहन व्यवस्था, हाईस्कूल-हायरसेकेंड्री स्कूलों की अधोसंरचना में सुधार करने का होमवर्क दिया है। वहीं प्रेम सिंह पटेल, मंत्री, पशुपालन विभाग, सामाजिक न्याय विभाग को गोशालाओं के संचालन की

रणनीति तैयार करने, पशुपालन से किसानों की आय कैसे बढ़े इसकी रणनीति बनाना, दुग्ध उत्पादक कृषकों को केसीसी प्रदान करने, सामाजिक सुरक्षा पेंशन वितरण की लगातार समीक्षा करने, दिव्यांगों की विशेष आवश्यकताओं के लिए सीएसआर (कंपनियों का सीएसआर मद) से प्रदेश में विश्वस्तरीय केंद्र स्थापित करने का होमवर्क दिया गया है। वहीं मोहन यादव, मंत्री (उच्च शिक्षा) को प्रदेश में कम से कम एक विश्वविद्यालय और 5 महाविद्यालयों को राष्ट्रीय स्तर की प्रथम 100 संस्थाओं में लाने की रणनीति बनाने का होमवर्क दिया है।

बृजेन्द्र सिंह यादव, राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग को जल जीवन मिशन को लागू करने/योजनाएं स्वीकृत कराना, समूह ग्रामीण नल जल योजना (जल निगम) की योजनाओं का क्रियान्वयन सह सुरक्षित/स्वच्छ पेयजल घर-घर में उपलब्ध हो इसकी रणनीति बनाने का होमवर्क दिया गया है। वहीं रामखेलान पटेल, राज्य मंत्री, (पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण (स्वतंत्र प्रभार) को विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण (स्वतंत्र प्रभार), पंचायत एवं ग्रामीण

विकास विभाग), पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्तियों के वितरण की समीक्षा करने, मनरेगा के माध्यम से रोजगार सृजन, जल संरक्षण कार्यों का क्रियान्वयन, महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से रोजगार के अवसर, मनरेगा के माध्यम से टिकाऊ अधोसंरचना का विकास, पीएमजीएसवाई की सड़कों का सुधार, समय पर कार्य पूर्ण करने का होमवर्क दिया गया है।

रामकिशोर कांवेरे, राज्यमंत्री, आयुष (स्वतंत्र प्रभार) जल संसाधन को आयुष अस्पताल की व्यवस्था में सुधार, आयुष के इलाजों को घर-घर तक पहुंचाने की रणनीति बनाने का होमवर्क दिया है। वहीं सुरेश धाकड़, राज्यमंत्री (लोक निर्माण विभाग) को सड़कों का विश्वस्तरीय संधारण, निर्माण, चंबल प्रोग्रेस-वे परियोजना की लगातार समीक्षा, भवन निर्माण कार्यों की गुणवत्ता-समयसीमा में पूर्ण किया जाकर लगातार समीक्षा, निजी क्षेत्र के सहयोग से बड़ी परियोजनाओं की परिकल्पना करने, सड़क निर्माण कार्यों की लगातार समीक्षा करने का होमवर्क दिया गया है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं इसकी निगरानी कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ वे चुनाव क्षेत्र वाले पूर्व विधायकों के साथ अलग-अलग चर्चा कर उनकी जरूरतें पूछ चुके हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मंत्रियों को भी साफ कह दिया गया है कि उपचुनाव तक सभी 27 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यों को प्राथमिकता दें। इसके मद्देनजर ही लोक निर्माण विभाग ने विधानसभा क्षेत्रों के लिए करीब दो सौ करोड़ रुपए की सड़क, पुल और पुलिया के कार्यों को मंजूरी दी है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग ने उन 36 लाख हितग्राहियों को एक रुपए किलोग्राम में चावल, गेहूं और नमक देने का फैसला किया है, जो अभी तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे में नहीं आ पाए हैं। दरअसल, प्रदेश की कुल आबादी का 75 फीसदी हिस्सा ही कानून के दायरे में आता है। यह कोटा पूरा हो चुका है इसलिए पात्रता होने के बाद भी इन्हें पात्रता पर्ची नहीं मिल पाती है। पात्रता पर्ची के बिना उचित मूल्य की राशन दुकान से खाद्यान्न नहीं मिलता है। इस काम को कराने के लिए ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर काफी समय से प्रयास कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने इन सभी हितग्राहियों को राज्य शासन की ओर से राशन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

उधर, कांग्रेस पार्टी सरकार के इस कदम को महज दिखावा बता रही है। कांग्रेसियों का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान भी कागजों पर राशन वितरण हुआ है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा दावा करती रही है कि उसके पूर्ववर्ती शासनकाल में विकास भरपूर हुआ है। फिर इसकी चिंता क्यों?

● कुमार राजेन्द्र

चोर, नमक हराम, निकम्मा, नीच आदमी, अनपढ़, गंवार, कुत्ता, चू...या, गधा, बंदर, सांप-बिच्छू... चौंकिए नहीं... ये सब विशेषण गाली नहीं हैं, बल्कि हमारे माननीय राजनेताओं के बोल हैं। आजकल राजनीति के गलियारे में इस

तरह की भाषा का इस्तेमाल आम हो चला है। खासकर जब चुनाव का माहौल हो। मप्र में उपचुनाव की सुगबुगाहट है। इस सुगबुगाहट के बीच नेता एक-दूसरे को कोसने के लिए ऐसे-ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, जिन्हें सार्वजनिक तौर पर सुनने में शर्म आती है। प्रदेश में जब तक उपचुनाव नहीं हो जाते तब तक इस तरह की भाषा का प्रयोग होता रहेगा। हमारे माननीय नेतागण तो अपना परिचय आचरण से देते ही रहते हैं अब वो अपनी भाषा से भी जनता को रूबरू करा रहे हैं।

वर्तमान राजनीतिक माहौल में आए दिन नेताओं द्वारा अमर्यादित और स्तरहीन भाषा का प्रयोग किया जा रहा है जिसे हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता है। आजकल **नेतागण विकास** की बातें करने के बजाय एक-दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं और इस क्रम में अमर्यादित भाषा का उपयोग ज्यादा करने में विश्वास रखते हैं। अभी हाल ही में सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया अपनी बेलगामी के लिए चर्चा में हैं। वैसे तो भदौरिया चंबल के मीठे पानी वाले इलाके से आते हैं, लेकिन व्यवहार में ऐसा खारापन उनके भीतर इससे पहले शायद ही कभी देखने को मिला हो। भदौरिया ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को लेकर जो गुस्सा दिखाया, वह स्तब्ध कर देने वाला है। भदौरिया एक कार्यक्रम में आगबबूला दिखे। भदौरिया ने आरोप लगाया कि कांग्रेस में जब टूट हो रही थी तब दिग्विजय के इशारे पर पुलिस ने उनके भाई को घर से उठा लिया था। उनकी मां को भी परेशान करने की कोशिश की गई। करीब चार महीने पुराने इस घटना का जिक्र करते हुए भदौरिया ने शालीनता की सीमा-रेखा को पार कर दिया। ये भिंड में चंबल के पानी का असर भी हो सकता है या फिर ये अब सत्ता में होने का। संभव है कि माइक को सामने देखकर अरविंद बेकाबू आचरण कर गए। या फिर यह भी मुमकिन है कि क्षेत्र की जनता की भीड़ ने उनके भीतर जोश के अतिरेक का संचार कर दिया हो।

मप्र की राजनीति में बेलगाम नेताओं की संख्या कम नहीं है। युवा नेताओं में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी अपने ऊटपटांग बयानों के लिए

बेलगाम माननीय



अमर्यादितों के सरताज दिग्विजय सिंह

देश की राजनीति में अमर्यादित टिप्पणी करने वाले माननीयों में दिग्विजय सिंह को उनका सरताज माना जाता है। वे अपने विवादित बयानों के कारण हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने ट्विटर पर प्रधानमंत्री मोदी के लिए चू...या शब्द का इस्तेमाल किया था। दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट पोस्ट किया, उसमें मोदी की तस्वीर के साथ तीन लाइन लिखी गई थी। इसमें लिखा था, 'मेरी 2 उपलब्धियां: 1- भक्तों को चू...या बनाया, 2- चू...या को भक्त बनाया। ये सब केवल उदाहरण हैं जो आजकल नेतागण अपने



विपक्षी नेताओं के लिए उपयोग कर रहे हैं। तो क्या इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल लोकतंत्र के लिए सही है? क्या राजनेताओं को अपने भाषण में संयम और शालीनता का परिचय नहीं देना चाहिए? क्या लोकतंत्र में शब्दों की मर्यादा अनिवार्य नहीं होना चाहिए? आखिर इनसे हमारी जनता क्या प्रेरणा ले सकती है? क्या जनता को ऐसे नेताओं को वोट देना चाहिए? क्या ऐसे नेताओं को सामाजिक बहिष्कार नहीं कर देना चाहिए? क्या इसके लिए चुनाव आयोग को कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं करना चाहिए? क्या इसे चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन के दायरे में नहीं रखना चाहिए?

हमेशा चर्चा में रहते हैं। वे प्रधानमंत्री से लेकर भाजपा के छोटे नेता पर भी अमर्यादित टिप्पणी करने से नहीं चूकते हैं। अभी हाल ही में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव भी बहक गए। नागपंचमी के अवसर पर उन्होंने सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को सांप की सजा दे डाली। उनके ट्वीट का जवाब देते हुए प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने दिग्विजय, कमलनाथ और अरुण यादव को ही सांप कह डाला। और तंज कसा कि ये आपस में ही एक-दूसरे को डंसते रहते हैं।

राजनीति में अब ऐसी भाषा का चलन बढ़ गया है। मगर मध्यप्रदेश के लिहाज से यह सब खलने वाला मामला है। यहां राजनीतिक तो दूर, नेताओं के बीच के व्यक्तिगत मतभेद में भी ऐसी शब्दावली के इस्तेमाल के कम प्रसंग ही देखने को मिलते हैं। हां, याद करेंगे तो याद आएगा, जब 2003 में दिग्विजय सिंह के प्रति उमा भारती आग

उगलती थीं तब उन्हें जनता की तालियां मिलती थीं। लेकिन वो बात अब पुरानी हो गई। लेकिन अब फिर से अमर्यादित टिप्पणियां होने लगी हैं। जानकार बताते हैं कि चुनावी माहौल आते ही नेता इस तरह का व्यवहार करने लगते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो प्रदेश में अमर्यादित टिप्पणी करने का प्रचलन पिछले कुछ सालों में अधिक बढ़ा है। सिंधिया ने जिस तरह 22 विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़ी थी उस समय उन पर कांग्रेस के हर छोटे-बड़े नेता ने अमर्यादित टिप्पणी की थी।

दरअसल, जबसे ट्विटर और फेसबुक का चलन राजनीति में बढ़ा है, तबसे नेता एक-दूसरे को कोसने के लिए अधिक बेलगाम होने लगे हैं। ट्विटर पर वे उन शब्दों का प्रयोग करने से तनिक भी परहेज नहीं करते जिसे वे बोल नहीं पाते हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि सुर्खियों में बने रहने के लिए अमर्यादित आचरण के मामले राज्य में देखने मिले हैं। इसकी वजह यह है कि नेताओं की सक्रियता जनता के बीच कम हो रही है। अतः जनता के बीच अपनी उपस्थिति बरकरार रखने के लिए वे ऐसी टिप्पणी करने से नहीं चूक रहे हैं, जो अमर्यादित होती है। माननीय अपनी अमर्यादित टिप्पणियों से भले ही सुर्खियां बटोर रहे हैं, लेकिन इससे राजनीति का स्तर गिर रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक समय ऐसा भी आ जाएगा, जब मंचों से गालियां निकलेंगी।

● **रजनीकांत पारे**

सिं गरौली में रिलायंस सासन पावर लिमिटेड अपने औद्योगिक जानलेवा हादसे के बाद भी सबक नहीं ले पाया है। घटना को दो माह बीत चुके हैं और अब भी करीब 2 लाख टन राख (फ्लाई ऐश) गवइया नाले में व 2.15 लाख टन फ्लाई ऐश तटबंध टूटने वाली जगह के बगल में कंपार्टमेंट 5 क्षेत्र में फैली है। गवइया नाला रिहंद नदी से जुड़ा है और बरसात के कारण पूरी संभावना है कि नाले से फ्लाई ऐश का बहाव फिर हो और रिजर्वायर प्रदूषित हो जाए। कंपनी ने हादसे में मरने वाले कुछ पीड़ितों को मुआवजा देने का काम भले ही जोर-दबाव में तेजी से किया है लेकिन नदी व कृषि क्षेत्र में फैली जहरीले फ्लाई ऐश की सफाई का काम वह बहुत मंद गति से कर रही है।

फ्लाई ऐश से प्रभावित होने वाला गवइया नाला लगभग 6.5 किलोमीटर लंबा, 30 मीटर चौड़ा और औसतन एक मीटर गहरा है। 14-15 जुलाई को प्रभावित जगह पर किए गए केंद्र व राज्य के अधिकारियों की निरीक्षण रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। रिपोर्ट में तटबंध टूटने का कारण ऊपरी सतह पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को बताया गया है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यानी तटबंध के ऊपरी सतह पर काफी वेग होने के कारण निचले सतह क्षेत्र (लो-लाईंग एरिया) में तटबंध पर अत्यधिक दबाव बन गया जिससे तटबंध क्षतिग्रस्त हुआ और जहरीली राख के कारण जान-माल का काफी नुकसान हुआ।

तटबंध टूटने की वजह की तकनीकी पड़ताल करने वाले आईआईटी बीएचयू जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर अरुण प्रसाद ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, तटबंध विफल होने की शुरुआती वजह पोकलेन मशीन का फिसलना था लेकिन तटबंध को काफी नुकसान अपस्ट्रीम पर गंभीर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण पहुंचा। इस क्षति के कारण फ्लाई ऐश के कीचड़ वाले बहाव ने रिटेंशन वॉल (दबाव को झेलने वाली दीवार) को भी काट दिया। कीचड़ में भूजल के मिलने से फ्लाई ऐश और अधिक विकराल हुई और जिसके कारण गांवों में जान-माल की क्षति हुई। इसके अलावा चेकडैम भी डंपिंग साइट के बिल्कुल नजदीक बनाया गया था जिससे यह क्षति हुई।

हीरालाल बैस बनाम रिलायंस सासन पावर लिमिटेड का मामला नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में लंबित है। सिंगरौली में 10 अप्रैल को मैसर्स रिलायंस सासन पावर लिमिटेड के फ्लाई ऐश कीचड़ का तेज बहाव परिसर के बाहर हुआ था। इस फ्लाई ऐश कीचड़ के तेज बहाव के कारण हरहवा गांव में छह लोगों की मृत्यु हुई, जिनमें तीन बच्चे, एक महिला और एक पुरुष शामिल थे। इसके अलावा आसपास क्षेत्र में पर्यावरण, जीवन और संपत्ति को भारी क्षति



हादसे से सबक नहीं

पोकलेन मशीन के कारण टूटी थी तटबंध की दीवार

इस जानलेवा हादसे के कारण को लेकर प्लांट के अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि 10 अप्रैल, 2020 की शाम 4 बजकर 40 मिनट पर फ्लाई ऐश की डंपिंग गड्डे वाली दीवार टूटी थी। यह दीवार निचली सतह वाले क्षेत्र पर थी। फ्लाई ऐश डंपिंग के लिए परिसर के भीतर यह चौथा और पांचवा कंपार्टमेंट था। (फ्लाई ऐश डंपिंग के लिए अलग-अलग कंपार्टमेंट हैं। एक कंपार्टमेंट दूसरे कंपार्टमेंट से बिल्कुल अलग होता है) चौथे कंपार्टमेंट के पास एक पोकलेशन मशीन मिट्टी को बराबर करने का काम कर रही थी और उसी वक्त मशीन का बैलेंस बिगड़ा और वह ढलान की तरफ लुढ़क गई जिससे तटबंध की दीवार क्षतिग्रस्त हो गई और बड़ी मात्रा में फ्लाई ऐश बहकर गांव की तरफ चली गई।

पहुंची। एनजीटी के आदेश (29 जून, 2020) के आधार पर गठित संयुक्त समिति ने 14-15 जुलाई को सिंगरौली के प्रभावित क्षेत्र का दौरा और निरीक्षण किया। वहीं, 28 जुलाई, 2020 को अपनी रिपोर्ट में कहा है कि रिलायंस की सासन यूनिट जिस लो लाईंग एरिया के तहत कंपार्टमेंट में फ्लाई ऐश डंप कर रही थी, वह करीब 6.5 मीटर गहरा 41.62 हेक्टेयर क्षेत्र है जो 27.06 लाख घन मीटर वॉल्यूम तक फ्लाई ऐश डंपिंग की क्षमता रखता है। कंपनी के जरिए हाई कंस्ट्रेशन स्लरी डिस्पोजल (एचसीडीसी) डिस्चार्ज किया जा रहा था। यानी ऐसी राख का कीचड़ जिसमें पानी और कीचड़ का अनुपात 30:70 का था। 10 अप्रैल यानी हादसे वाले दिन तक संबंधित कंपार्टमेंट में 10 लाख घन मीटर फ्लाई ऐश डंप की गई थी।

परिसर के आइसलैंड चार (सी-5 क्षेत्र) यानी

गवइया नाले और आसपास कृषि क्षेत्र में डिपॉजिट 10 लाख टन फ्लाई ऐश से 11 हेक्टेयर क्षेत्र और 3 मीटर गहराई तक 4 लाख टन फैला। फिलहाल 3.5 लाख टन फ्लाई ऐश को सी-5 क्षेत्र से निकालकर आइसलैंड 3 में डंप किया गया है। साथ ही ऐश डाइक एक और 2 को ऊंचा उठाने व बंधे को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। वहीं, 2.67 लाख टन राख गवइया नाले से निकाली गई है जिसका इस्तेमाल भी बंधा मजबूत करने में किया गया है।

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सिंगरौली के क्षेत्रीय अधिकारी एसडी वालिमकी ने 17 जुलाई, 2020 को यूनिट के दिए गए आदेश में कहा है कि यूनिट रिहंद नदी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए न सिर्फ फ्लाई ऐश की सफाई जल्द करे बल्कि बारिश की गणना और भू व सतह के जल का ससाह में दो बार नमूने लेकर मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से जांच कराए और जांच परिणाम प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध कराए। जांच समिति ने सिफारिश में कहा है कि यूनिट अब जब भी फ्लाई ऐश का डिस्पोजल करेगी उसे पहले प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति हासिल करनी होगी।

मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक कंपनी ने पर्यावरणीय क्षति के लिए 10 करोड़ रुपए के अंतरिम हर्जाने में महज 2 करोड़ रुपए ही अभी तक दिए हैं। इसके अलावा कंपनी ने छह मृतकों के परिजनों और अन्य पीड़ितों को कुल 125.3 लाख रुपए दिए हैं। इसके अलावा तीन अन्य गांवों में कृषि नुकसान आकलन का भी मुआवजा दिया है। हालांकि जांच समिति ने कहा है कि अब भी कई ऐसे लोग हैं जिन्हें कंपनी की ओर से मुआवजा दिया जाना चाहिए। इसके लिए कंपनी स्थानीय प्राधिकरणों के साथ मिलकर आसपास के ग्रामीणों की शिकायत सुने और उनका समाधान करे।

● जितेन्द्र तिवारी

6
 चाल चेहरा और
 चरित्र वाली
 भाजपा अपनी
 विचारधारा के लिए
 जानी जाती है।
 लेकिन पिछले कुछ
 सालों में भाजपा में
 दूसरी विचारधारा
 वाली पार्टियों के
 नेता थोक में आ
 रहे हैं। इन दिनों
 मप्र में भी ऐसा हो
 रहा है। पिछले 5
 माह में कांग्रेस के
 आधार स्तंभ रहे
 ज्योतिरादित्य
 सिंधिया, कांग्रेस
 के 25 पूर्व
 विधायकों सहित
 सैकड़ों कार्यकर्ता
 भाजपा का दामन
 धाम चुके हैं। इसे
 भाजपा की
 मजबूती मानी
 जाए या मजबूरी
 कि वह विश्व की
 सबसे बड़ी
 राजनीतिक पार्टी
 होने के बाद भी
 दूसरी पार्टियों में
 घुसपैठ कर रही है।



मजबूती या मजबूरी

पार्टी विश्व डिफरेंस वाली भाजपा इन दिनों खिचड़ी पार्टी बन गई है। मप्र सहित देशभर में दूसरी पार्टियों के नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। इस संदर्भ में भाजपा नेताओं का कहना है कि यह हमारी पार्टी की मजबूती का प्रमाण है। पार्टी के पदाधिकारी कहते हैं कि राजनीतिक दलों की मजबूती के दो रास्ते हैं, पहला-विचारधारा से प्रभावित लोगों का जुड़ते रहना, दूसरा-विरोधी दल के नेता साथ आ जाएं। पहले रास्ते से पार्टी मजबूत होती है, जबकि दूसरे में विरोधी पार्टी कमजोर भी होती है, यानी दोहरा लाभ। मप्र भाजपा इन दिनों दूसरे रास्ते पर चल रही है। करीब 15 साल की सत्ता

2018 में गंवाने के बाद उसे बीते मार्च में फिर से सरकार बनाने का मौका भी मिला तो दूसरे रास्ते से ही। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थक विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़ भाजपा में आ गए, जिससे कमलनाथ की कुर्सी चली गई और शिवराज सिंह चौहान चौथी बार मुख्यमंत्री बन सके।

हालांकि भाजपा को महाराष्ट्र और झारखंड में इसी रास्ते पर चलने से हुए नुकसान का आंकलन कर लेना चाहिए। पिछले साल विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में एनसीपी और कांग्रेस से कई दिग्गजों को भाजपा और शिवसेना में पलायन हुआ। नतीजा सामने है। भाजपा को इन आयातित नेताओं से कोई फायदा नहीं हुआ। वह पिछले प्रदर्शन 122 सीट (28.1 प्रतिशत) से गिरकर 105 (26.1 प्रतिशत) पर आ गई। सत्ता से भी बाहर होना पड़ा। उधर, झारखंड में भी रघुवर दास ने झारखंड विकास मोर्चा के विधायकों के लिए अपने दरवाजे खोल रखे थे। नतीजा क्या रहा? भाजपा सत्ता से बाहर हुई तो उसकी

वजह पार्टी में असंतोष बताते हुए रघुवरदास को अहंकारी तक कहा गया। मप्र फिलहाल भाजपा के सशक्त संगठनों में शुमार है, फिर भी कांग्रेस से पलायन करने वालों का स्वागत जारी है, जो भाजपा के भविष्य के लिए सवाल खड़े करता है। कांग्रेस से सीधे मोर्चा लेने वाले और सिंधिया के धुर विरोध की सियासत करने वाले भाजपा नेता नाराज चल रहे हैं। जिसे संगठन अनदेखा नहीं कर सकता।

12 जुलाई को छतरपुर जिले के बड़ा मलहरा से कांग्रेस विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी ने भाजपा ज्वाइन की। उन्हें छह घंटे बाद ही नागरिक आपूर्ति निगम का अध्यक्ष बना दिया गया। 17 जुलाई को बुरहानपुर जिले की नेपानगर सीट से विधायक सुमित्रा देवी कासडेकर ने भाजपा ज्वाइन की। 23

जुलाई को खंडवा जिले की मांधाता सीट से कांग्रेस विधायक नारायण पटेल ने भाजपा का दामन थाम लिया। वह गुर्जर समाज से हैं। प्रदेश के मंत्री ऐंदल सिंह कंधाना पहले ही कह चुके हैं कि राजस्थान में चल रहे सियासी घटनाक्रम को देखते हुए कई गुर्जर विधायक उनके संपर्क में हैं, जो जल्द ही कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ सकते हैं। कमलनाथ सरकार में खनिज मंत्री रहे वारासिवनी से निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल खनिज निगम के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है। जायसवाल ने राज्यसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान किया था।

दो राय नहीं है कि ऐसे हालात में भाजपा के कई नेताओं को अपने सियासी भविष्य पर संकट नजर आ रहा है। सवाल भी उठ रहे हैं कि सरकार बनने के बाद अब कांग्रेस से भाजपा में पलायन से क्या पार्टी

दो विधायक जाते-जाते बचे

गत दिनों कांग्रेस के दो और विधायक भाजपा में जाते-जाते बचे। सूत्रों का कहना है कि 14 जुलाई को कांग्रेस को दो विधायक पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से मिलने उनके आवास पर पहुंचे, लेकिन वहां उनकी कमलनाथ से कहासुनी हुई। जिसके बाद राजधानी के राजनीतिक गलियारों में कांग्रेस विधायक राहुल लोधी और तरवर लोधी के भाजपा में शामिल होने की खबरों ने जोर पकड़ लिया। दो विधायकों के भाजपा में जाने की खबरों की जानकारी मिलते ही कांग्रेस में खलबली मच गई। दिल्ली से कांग्रेस के प्रभारी महासचिव मुकुल वासनिक ने तुरत-फुरत कमलनाथ से चर्चाकर विधायकों को भाजपा में जाने से रोकने को कहा। जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दोनों विधायकों से बात कर डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू की। जिसके लिए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा को जिम्मेदारी दी गई। करीब तीन घंटे से अधिक समय तक दोनों नाराज विधायकों को मनाने का क्रम चला और अंत में दोनों विधायकों को मीडिया के सामने लाकर बयान दिलाया गया कि वह कांग्रेस नहीं छोड़ रहे हैं।



पलायन रोकने खोला नियुक्तियों का पिटारा

सिंधिया के भाजपा में आने से कांग्रेस में शुरू हुए पलायन के दौर को थामने के लिए कमलनाथ ने प्रदेश पदाधिकारियों से लेकर जिलास्तर और ब्लॉक के स्तर तक नियुक्तियों का पिटारा खुल गया है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से हर दिन 50 से 100 नियुक्तियों के आदेश जारी हो रहे हैं। सबसे ज्यादा नियुक्तियां उपचुनाव वाले जिलों में हो रही हैं। ग्वालियर-चंबल इलाके में सिंधिया के समर्थन में पाला बदलकर भाजपा में जा रहे नेताओं को रोकने की कवायद में जुटी कांग्रेस ताबड़तोड़ नियुक्तियां कर कांग्रेस का कुनबा बढ़ाने में जुटी हुई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में पहली बार सबसे ज्यादा पदाधिकारियों की नियुक्ति के आदेश जारी हो रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में ही अब तक 35 से ज्यादा सचिव, सहसचिव और महामंत्री पद के नियुक्ति के आदेश जारी हो चुके हैं। ग्वालियर-चंबल इलाके में ही जिला संगठन को मजबूत बनाने के लिए 500 से ज्यादा नियुक्तियां हो चुकी है। 200 से ज्यादा पदाधिकारियों की नियुक्तियां अकेले ग्वालियर-चंबल के भिंड जिले और ग्वालियर में चार जिला कार्यकारी अध्यक्षों की हुई है। मध्यप्रदेश कांग्रेस में भी कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति बढ़ाने की तैयारी है।

मजबूत होगी? आखिर हर आने वाले के गले में कमल का दुपट्टा डालने की क्या मजबूरी है? पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ग्वालियर-चंबल संभाग में सिंधिया के विरोध में सियासत करते रहे हैं। राजस्थान के घटनाक्रम के बहाने उनकी पीड़ा एक ट्वीट के जरिए सामने भी आ चुकी है। उन्होंने ट्वीट में लिखा- 'हे कांग्रेस की राजमाता! अपने कुनबे को सम्हालिये ना! आखिर आपकी रूठी हुई राजनीतिक संतानों को हम अपनों के हिस्से का कितना प्यार लुटाते रहेंगे? यदि नहीं सम्हालता तो किसी दिवालिया फर्म की तरह कांग्रेस प्राइवेट लिमिटेड का शटर डाउन क्यों नहीं कर देती? आप और देश दोनों ही शुकून में रहेंगे।' इसे भाजपा के उस बड़े वर्ग की अभिव्यक्ति माना जा रहा है, जो बाहरी नेताओं के आने से उपेक्षित हो रहे हैं। पवैया ही अकेले ऐसे नेता नहीं हैं, जिन्हें अब अपना राजनीतिक भविष्य मुश्किल लग रहा है। इससे पहले दीपक जोशी भी विरोध दर्ज करा चुके हैं, वहीं सांची में गौरीशंकर शेजवार भी बोल चुके हैं कि मौका आने पर बात करूंगा। उधर अजय विश्णोई लगातार मोर्चा खोले हुए हैं।

इधर, सियासी गलियारों में यहां तक चर्चा है कि अयोध्या में राममंदिर के भूमिपूजन के बाद कांग्रेस के कई नेताओं का हृदय परिवर्तन हो सकता है। वह भाजपा की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। इस मामले पर कांग्रेस के प्रबंधकों में सुस्ती है, उसे देखकर इन चर्चाओं से मुंह भी नहीं मोड़ा

जा सकता। हालांकि भाजपा को ये देखना ही होगा कि नए कुनबे को जोड़ने की मजबूरी कहीं उसकी मजबूती पर भारी न पड़ जाए। भाजपा ने कांग्रेसी विधायकों को अपनी पार्टी ने आकर्षित करने के लिए हाल ही में कांग्रेस से आए प्रद्युम्न सिंह लोधी को नागरिक आपूर्ति निगम का अध्यक्ष बनाने के साथ ही निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल को खनिज निगम का अध्यक्ष बनाकर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया है। इससे यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि जो भी कांग्रेस का विधायक भाजपा में शामिल होगा, उसे उचित पद और प्रतिष्ठा मिलेगी।

भाजपा सूत्रों का कहना है कि पार्टी जिन 10 विधायकों को भाजपा में लाने की तैयारी कर रही है, उनमें से 7 विधायक पहले से ही संपर्क में हैं। ये विधायक मंत्रिमंडल गठन और विभागों के बंटवारे का इंतजार कर रहे थे। सूत्रों का कहना है कि यह भी एक वजह है कि कांग्रेस छोड़कर आए 14 पूर्व विधायकों को मंत्री बनाया गया है और कईयों को महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। भाजपा सूत्रों का कहना है कि जिन कांग्रेसी विधायकों को भाजपा में लाने की कोशिश चल रही है उनमें से अधिकांश मालवा और निमाड़ क्षेत्र के हैं। वहीं कुछ विधायक मध्यभारत के भी संपर्क में हैं। ये वे विधायक हैं जिनका सिंधिया से दूर तक का नाता नहीं है। सूत्र बताते हैं कि संघ के कुछ पदाधिकारियों के साथ

ही भाजपा के नेता इस अभियान को पूरा करने में जुटे हुए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले सुमावली के पूर्व विधायक और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री ऐंदल सिंह कंधाना और भाजपा नेताओं की मानें तो कांग्रेस के कम से कम 10 और विधायक उपचुनाव से पहले भाजपा में आ सकते हैं। उनका कहना है कि अगर कोशिश की जाए तो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आने वालों की संख्या 10 से 15 तक भी हो सकती है।

मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुखिया कमलनाथ इस बात को या तो समझ नहीं पा रहे हैं या समझकर भी अपनी खामियों को छुपाने के लिए अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस के बड़े क्षत्रप खासकर दिग्विजय सिंह और उनके समर्थक भाजपा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जितने तीखे हमले कर रहे हैं ग्वालियर-चंबल अंचल में सिंधिया के प्रति लोगों में विशेष रूप से युवाओं में सहानुभूति बढ़ती जा रही है। यह दावा मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुखिया कमलनाथ द्वारा कराए गए सर्वे की रिपोर्ट में किया गया है। जिसे कमलनाथ और उनकी पार्टी के क्षत्रप हल्के में लेने की गलती कर रहे हैं। दरअसल ग्वालियर-चंबल अंचल में सदियां बीत जाने के बाद भी सिंधिया राजघराने के प्रति लोगों की आस्था अभी तक कम नहीं हुई है। खासकर पिछले विधानसभा चुनाव के बाद इसका ग्राफ पहले की तुलना में इसलिए बढ़ा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने सिंधिया को आगे कर चुनाव लड़ा और मतदाताओं को यह संदेश दिया कि यदि कांग्रेस की सरकार बनी तो सिंधिया ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद जब कांग्रेस ने सरकार बनाने का दावा किया तब दिग्विजय सिंह की कुटिलनीतिक बाजीगरी के चलते सिंधिया को पीछे कर कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनवा दिया। जिसकी वजह से इस अंचल में कांग्रेस और दिग्विजय सिंह के खिलाफ भरा गुस्सा अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। इस महत्वपूर्ण तथ्य को कांग्रेस मुखिया समझ रहे हैं और कई अवसरों पर संकेत भी दे चुके हैं। शायद इसीलिए दिग्विजय सिंह समर्थकों के भारी दबाव के बावजूद उन्होंने अभी तक दिग्विजय सिंह को उपचुनाव की रणनीति से दूर ही रखा है। कमलनाथ के सामने बड़ी मुसीबत यह भी है कि भले ही वह अभी तक दिग्विजय सिंह को दूर रखने में कामयाब रहे हैं, लेकिन निकट भविष्य में वह ज्यादा समय तक उपचुनाव की राजनीति से उन्हें दूर नहीं रख पाएंगे। यही वजह है कि कमलनाथ इस अंचल में अपनी पैठ बढ़ाने की कवायद में जुटे हुए हैं और संगठन में अपने समर्थकों की राजनीतिक नियुक्तियां कर अपनी टीम खड़ी कर रहे हैं।

● सुनील सिंह

जिस किसान कर्जमाफी को मुद्दा बनाकर कांग्रेस ने करीब डेढ़ साल पहले अपने डेढ़ दशक के राजनीतिक वनवास को समाप्त किया था, उसके सहारे ही अब एक बार फिर कांग्रेस उपचुनाव में जीत की राह तैयार करने की जुगत में है।

भाजपा भी इसी मुद्दे के सहारे कांग्रेस को पटखनी देने की तैयारी कर रही है, जिससे यह तो तय है कि उपचुनाव में किसान कर्जमाफी का मुद्दा छाया रहना तय है। यही वजह है कि यह दोनों ही प्रतिद्वंद्वी दल इस मामले में एक-दूसरे पर वार-पलटवार का कोई भी मौका नहीं चूक रहे हैं। भाजपा किसान कर्जमाफी को लेकर लगातार कांग्रेस पर हमलावर बनी हुई है। वह इसमें फर्जीवाड़े का आरोप लगाकर जांच के लिए मंत्रियों का समूह तक जांच के लिए गठित कर चुकी है। वहीं कांग्रेस भी दावा कर रही है कि उसकी सरकार में एक साल के अंदर ही 22 लाख से अधिक किसानों का कर्ज माफ कर दिया गया था। उसका आरोप है कि उनकी सरकार में चरणबद्ध तरीके से हर किसान का कर्ज माफ किया जा रहा था, लेकिन भाजपा ने षड्यंत्र कर सरकार गिरा दी। यही वजह है कि कांग्रेस भी इस मामले में भाजपा को पूरी तरह से घेरने की तैयारी में लगी है। कांग्रेस का अब पूरा फोकस इस बात पर है कि विधानसभा चुनावों की तरह इसे उपचुनावों में भी किस तरह से भुनाया जाए। इससे यह तो स्पष्ट है कि कांग्रेस किसान कर्जमाफी मुद्दे को ही प्रमुख रूप से सामने रखकर उपचुनावों में उतरने की तैयारी कर रही है।

कांग्रेस के संगठन स्तर पर कर्जमाफी पाने वाले किसानों के वीडियो बनाने की तैयारी है, जिससे कि उन्हें दिखकर कांग्रेस के पक्ष में पूरी तरह से किसानों को लाया जा सके। यह बात अलग है कि इसमें अधिकांश किसान ऐसे हैं, जिनका 50 हजार रुपए तक का कर्ज माफ हुआ है। इनके वीडियो सोशल मीडिया में वायरल करने की तैयारी की जा रही है। इसमें यह भी बताया जाएगा कि कर्जमाफी का दूसरा चरण शुरू हो चुका था और तीसरे चरण की तैयारी थी। इसके बाद सभी किसानों का कर्ज माफ हो जाता, लेकिन भाजपा द्वारा सरकार गिरा देने से ऐसा नहीं हो पाया है। यही वजह है कि कांग्रेस सरकार गिरने के बाद से लगातार भाजपा की शिव सरकार से किसान कर्जमाफी योजना को चालू रखने की मांग कर रही है।

कांग्रेस को जबाव देने के लिए भाजपा ने भी अभी से पूरी तरह पलटवार की तैयारी कर ली है। भाजपा भी आने आरोपों को यही साबित करने के लिए ऐसे किसानों का सहारा लेगी, जिनका अब तक एक पैसे का भी कर्ज माफ नहीं हुआ है। इसमें दस दिन में किसानों का कर्ज माफ करने के कांग्रेस के वादे का इसमें भी पूरी तरह से फोकस उपचुनाव वाले विधानसभा क्षेत्रों पर किया

किसान भरोसे



कर्जमाफी की जांच के लिए मंत्रियों का समूह गठित

भाजपा सरकार बनने के बाद शिव सरकार द्वारा इस मामले में कांग्रेस सरकार को निशाने पर रखने के लिए ही मंत्री समूह का गठन किया गया है। इस मामले में कृषि मंत्री कमल पटेल शुरू से ही पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार पर हमलावर बने हुए हैं। वे तो यहां तक कह चुके हैं कि कर्जमाफी के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया है। वे लगातार किसानों का आह्वान कर रहे हैं कि जिन किसानों को कर्जमाफी का प्रमाण-पत्र मिल चुका है, लेकिन उनका कर्ज माफ नहीं हुआ है, वो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराए। यह बात अलग है कि अब तक इस तरह को कोई भी मामला सामने नहीं आया है।

जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने किसान कर्जमाफी के मुद्दे को एक बार फिर अपना वचन बताते हुए 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कैंस कराने की तैयारी शुरू कर दी है। इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने किसान कांग्रेस को सौंपी है। किसान कांग्रेस बूथ स्तर पर किसान सैनिक की नियुक्ति कर कर्जमाफी के मुद्दे पर भाजपा के आरोपों का जवाब देने का काम करेगी। कांग्रेस पार्टी की कोशिश है कि बूथ लेवल पर लोगों को पूर्व की कमलनाथ सरकार के किसान कर्जमाफी की जानकारी पहुंचाई जाए, ताकि भाजपा द्वारा फैलाए गए भ्रम को दूर किया जा सके।

कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि 24 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में कर्जमाफी का मुद्दा उसके लिए जीत की राह को आसान बना सकता है। इसके लिए किसान कांग्रेस ने बूथ स्तर तक

किसान सैनिक की नियुक्ति करने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। मप्र किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर के मुताबिक पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए बूथ स्तर पर किसान सैनिक के जरिए किसानों से जुड़े मुद्दों पर पूर्व की कांग्रेस सरकार के फैसलों की जानकारी और मौजूदा सरकार की नाकामियों को गिनाने का काम होगा। वहीं भाजपा ने भी सूबे की सत्ता संभालते ही किसान कर्जमाफी के नाम पर कांग्रेस की पूर्व सरकार पर धोखा देने का आरोप तेज कर दिया है। प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल किसान कर्जमाफी में हुए गड़बड़ियों की जांच की बात कर चुके हैं। इसको लेकर सरकार ने गुप ऑफ मिनिस्टर का गठन भी किया है, जो कांग्रेस सरकार में हुई गड़बड़ियों की जांच कर रहा है। भाजपा प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने कहा है कि किसान कर्जमाफी किसानों के साथ धोखा साबित हुई है और अब यह उपचुनाव में काम नहीं करेगी।

दरअसल, पूर्व की कमलनाथ सरकार ने इस बात का दावा किया था कि प्रदेश में 20 लाख से ज्यादा किसानों का कर्ज माफ हुआ है। दूसरे चरण में दो लाख तक किसानों का कर्ज माफ किया जाना प्रक्रिया में था लेकिन कांग्रेस की सरकार सत्ता से बेदखल हो गई। किसान कर्जमाफी का तीसरा चरण जून से शुरू होना था और कांग्रेस इस बात को लेकर दबाव बना रही है कि मौजूदा सरकार पिछली सरकार के कैबिनेट में हुए फैसले पर अमल कर किसान कर्जमाफी का तीसरा चरण शुरू करे। लेकिन योजना में गड़बड़ी का अंदेशा जताते हुए मौजूदा सरकार ने किसान कर्जमाफी योजना की जांच शुरू कर दी है। बहरहाल यह तय हो गया है कि उपचुनाव में किसान कर्जमाफी फिर एक बार बड़ा मुद्दा होगा।

● लोकेश शर्मा

डा कुओं और अपराधियों की शरणस्थली रहे चंबल के बीहड़ में मोदी सरकार ने खेती करवाने की योजना बनाई है। इसमें विश्व बैंक मदद करेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि यहां 3 लाख हेक्टेयर से भी अधिक गैर-खेती योग्य बीहड़ भूमि है, जिसमें कृषि विकास किया जाएगा। एक महीने में इसकी प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट पेश की जाएगी। सरकार का दावा है कि इस क्षेत्र में खेती-किसानी व पर्यावरण में सुधार होगा। इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। विश्व बैंक, मध्यप्रदेश के अधिकारियों एवं कृषि विशेषज्ञों ने परियोजना पर सैद्धांतिक सहमति जताई है। तोमर ने बताया कि चंबल क्षेत्र के लिए पहले भी विश्व बैंक के सहयोग से बीहड़ विकास परियोजना प्रस्तावित थी, लेकिन कुछ कारणों से विश्व बैंक उस पर राजी नहीं हुआ। अब नए सिरे से इसकी शुरुआत की गई है। इस परियोजना में खेती के साथ-साथ कृषि बाजारों, गोदामों व कोल्ड स्टोरेज का विकास भी होगा।

तोमर ने कहा कि क्षेत्र में चंबल नदी किनारे काफी जमीन है जहां कभी खेती नहीं हुई। इसलिए यह क्षेत्र जैविक रकबे में जुड़ेगा जो बड़ी उपलब्धि होगी। जो चंबल प्रोग्रेस-वे बनेगा, यहीं से गुजरेगा। प्रारंभिक रिपोर्ट बनाए जाने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ बैठक की जाएगी और आगे की बातें तय होंगी। मध्यप्रदेश में देश का सबसे ज्यादा आर्गेनिक क्षेत्रफल है, जिसे प्रमोट करने की जरूरत है। ताकि आर्गेनिक फार्मिंग और आगे बढ़ सके। प्रोजेक्ट को मिशन मोड में लेकर अत्याधुनिक तकनीक के साथ काम करेंगे। विश्व बैंक के अधिकारी आदर्श कुमार ने कहा कि विश्व बैंक मध्य प्रदेश में काम करने का इच्छुक है। परियोजना से जुड़े जिलों में किस तरह से, कौन-सा निवेश हो सकता है, देखना होगा। विश्व बैंक के ही अधिकारी एबल लुफाफा ने कहा कि क्षेत्रीय स्तर पर भूमि इत्यादि की जो स्थितियां हैं, उन्हें समझते हुए प्रोजेक्ट पर विचार किया जाएगा। हम अन्य देशों का उदाहरण लेकर काम कर सकते हैं।

ग्वालियर-चंबल के बीहड़ में करीब 3 लाख हेक्टेयर जमीन को खेती योग्य बनाया जाएगा। विश्व बैंक की मदद से इस परियोजना पर काम किया जाएगा। भारत सरकार के केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण ग्रामीण विकास तथा पंचायती

बीहड़ में होगी खेती



राज मंत्री व मुंरैना-शयोपुर सांसद नरेंद्र सिंह तोमर की पहल पर ग्वालियर-चंबल क्षेत्र के बीहड़ को कृषि योग्य बनाने के लिए विश्व बैंक की मदद से एक बड़ी परियोजना बनाते हुए व्यापक काम किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री की पहल पर गत दिनों उच्चस्तरीय बैठक हुई। बैठक में तोमर के अलावा विश्व बैंक व मप्र के वरिष्ठ अधिकारी एवं कृषि विशेषज्ञ शामिल हुए।

केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि इस परियोजना से बीहड़ क्षेत्र में खेती-किसानी तथा पर्यावरण में अधिक सुधार होगा। रोजगार के काफी अवसर पैदा होंगे। परियोजना पर सभी ने सैद्धांतिक सहमति जताई है। प्रारंभिक रिपोर्ट महीनेभर में तैयार हो जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में केंद्रीय मंत्री तोमर ने प्रस्तावित परियोजना के माध्यम से बीहड़ क्षेत्र में कृषि का विस्तार करने, उत्पादकता बढ़ाने तथा वैल्यू चैन विकसित करने पर जोर दिया है। तोमर ने कहा कि चंबल क्षेत्र के लिए पूर्व में विश्व बैंक के सहयोग से बीहड़ विकास परियोजना प्रस्तावित थी। लेकिन विभिन्न कारणों से विश्व बैंक उस पर राजी नहीं हुआ। अब नए सिरे से इसकी शुरुआत की गई है।

केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि बीहड़ की 3 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन खेती योग्य नहीं है। प्रोजेक्ट के माध्यम से क्षेत्र में सुधार हो जाए तो वहां खेती प्रारंभ होगी तथा पर्यावरण की दृष्टि से भी यह ठीक होगा। लोगों को आजीविका भी मिलेगी। परियोजना से बीहड़ विकास के अलावा नए रिफार्म से खेती-किसानी के लिए मदद होगी। तोमर ने कहा कि क्षेत्र में नदी किनारे काफी जमीन है। जहां कभी खेती नहीं हुई तो यह क्षेत्र जैविक रकबे में जुड़ेगा जो बड़ी उपलब्धि होगी। जो चंबल प्रोग्रेस-वे बनेगा, यहीं से गुजरेगा।

मप्र कृषि संचालक संजीव सिंह ने बताया कि प्रदेश में कृषि की वर्तमान स्थितियों और अन्य प्रदेशों का आकलन करते हुए परियोजना का प्रारूप बनाया जाएगा। खेती संबंधी रिफार्म के आधार पर किसानों तथा अन्य संबंधित वर्गों को ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे मिले, यह भी देखा जाएगा। मप्र में देश का सबसे ज्यादा आर्गेनिक क्षेत्रफल है, जिसे प्रमोट करने की जरूरत है। प्रोजेक्ट को मिशन मोड में लेकर अत्याधुनिक तकनीक के साथ काम करेंगे।

● विकास दुबे

सैटेलाइट इमेज से प्रारूप बनाया जाएगा

मप्र के कृषि उत्पादन आयुक्त केके सिंह ने कहा कि पुराने प्रोजेक्ट को रिवाइज किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री के दिशा-निर्देशों के अनुरूप महीनेभर में प्रारंभिक रिपोर्ट बनाने पर सहमति जताई। विश्व बैंक के साथ सहयोग करते हुए सैटेलाइट इमेज सहित अन्य माध्यमों से परीक्षण कर प्रारूप बनाया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने कहा कि रिसर्च, टेक्नालाजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, पूंजीगत लागत, निवेश आदि पर विचार किया जाए। विश्व बैंक के अधिकारी आदर्श कुमार ने कहा कि विश्व बैंक मप्र में काम करने की इच्छुक है। परियोजना से जुड़े जिलों में किस तरह से, कौन-सा निवेश हो सकता है यह देखना होगा। प्रोजेक्ट नए रिफार्म के अनुकूल हो सकता है। हम अन्य देशों का उदाहरण लेकर काम कर सकते हैं। मार्केटिंग की सुविधा, इंफ्रास्ट्रक्चर आदि को ध्यान में रखते हुए पूरी योजना बनाना होगी। वैल्यू चैन पर काम करना ज्यादा फायदेमंद होगा।

कें द्र की मोदी सरकार की ओर से शुरू किए गए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप शिवराज सरकार तैयार कर रही है। मध्य प्रदेश के आत्मनिर्भर बनने के रोडमैप को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जनता के सामने पेश करेंगे। इसके तहत उन क्षेत्रों की पहचान की जा रही है, जिनमें मध्य प्रदेश लीडर की तरह उभर सकता है। प्रदेश के हर जिले की एक खासियत की पहचान कर उसे विकसित किया जाएगा तथा विश्व स्तर पर लाने का प्रयास किया जाएगा। स्व-सहायता समूहों और लघु, कुटीर उद्योगों के जरिए लोकल को वोकल बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने गत दिनों आत्मनिर्भर मप्र के रोडमैप का एक प्रेजेंटेशन भी देखा। आत्मनिर्भर मप्र के लिए कई सुझाव भी मिले हैं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोडमैप बनाने की प्रक्रिया में जल्द ही विभिन्न क्षेत्रों के विषय-विशेषज्ञों के साथ मुख्यमंत्री वैबनार करेंगे। इसमें मिले सुझावों को रोडमैप में शामिल किया जाएगा।

इस अभियान के तहत ऐसे प्रोजेक्ट लागू किए जाएंगे जिससे लोगों की आमदनी भी हो और उसके लिए **बाहर से किसी की मदद** न लेनी पड़े। मसलन किसानों को उनकी निजी भूमि पर वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। किसानों द्वारा उनके खेतों में लगाए गए सागौन आदि के पेड़ों को काटने के लिए सरल प्रक्रिया बनाई जाएगी। अभियान के तहत गारमेंट उद्योग में रोजगार की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। इसे मध्य प्रदेश में अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाएगा। गारमेंट उद्योग स्थापित करने के लिए निवेशकों को सरकार की तरफ से सहूलियतें दी जाएंगी। प्रदेश में जिन फसलों का उत्पादन अधिक है, उनकी प्रोसेसिंग, ग्रीडिंग, पैकेजिंग के लिए एग्रेसिव एप्रोच अपनाई जाएगी। मध्य प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ ही वन नेशन वन मार्केट की अवधारणा को मध्य प्रदेश में बढ़ावा दिया जाएगा। इसके माध्यम से किसानों को उनकी फसल का अधिक से अधिक मूल्य मिल पाएगा।

आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के लिए मिले सुझावों में ये शामिल हैं- उन क्षेत्रों की पहचान और



आत्मनिर्भर मप्र का प्लान

विश्लेषण किया जाए, जिनमें मध्यप्रदेश लीडर की तरह उभर सकता है। एक जिला-एक पहचान के तहत प्रत्येक जिले के लिए एक उत्पाद की पहचान की जाए तथा उसे विश्व स्तर पर लाने का प्रयास हो। ऐसी वस्तुओं और सेवाओं का चयन हो जो विकेंद्रीकृत रूप से निर्मित की जा सके और केंद्रीयकृत एजेंसी के द्वारा जिनकी मार्केटिंग संभव हो। स्व-सहायता समूहों, कुटीर उद्योगों एवं एमएसएमई द्वारा उत्पादित सामान को ई-कामर्स के माध्यम से जोड़ा जाए। प्रदेश के नेचुरल रिसोर्सेस पर आधारित आजीविका को बढ़ावा दिया जाए। बांस के उत्पादन को बढ़ाने के साथ-साथ बांस आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना। अधिक रोजगार प्रदाय करने वाले उद्योगों जैसे गारमेंट, खाद्य प्रसंस्करण आदि को बढ़ावा दिया जाए। खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए अतिरिक्त उपज का समुचित प्रबंधन, फसलों का विविधीकरण, परंपरागत खेती जैसे कोदो-कुटकी एवं जैविक खेती को बढ़ावा। किसानों के मजबूत उत्पादक संगठनों के माध्यम से किसानों की इनपुट आपूर्ति एवं मार्केटिंग की व्यवस्था हो।

इसके साथ ही वन नेशन वन मार्केट की अवधारणा की दिशा में कार्य किया जाए। भूमि और वन क्षेत्र के कारण आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए ऐलीवेटेड एक्सप्रेस-वे का

निर्माण। वृहद एवं अधिक सुविधाओं से सुसज्जित ऐसे स्कूलों को खोला जाना, जिनमें बच्चों को आसानी से आवागमन की व्यवस्था हो। स्वास्थ्य सेवाओं में इलाज के साथ ही रोकथाम की दिशा में प्रभावी कार्य हो। विकलांगता प्रमाण-पत्र मेडिकल बोर्ड के द्वारा उसी दिवस पर डिजिटल हस्ताक्षर के द्वारा जारी किया जा सकता है। लर्निंग लायसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने के पश्चात उसी दिन सिस्टम **जनरेटेड लर्निंग लाइसेंस** मिलने का प्रावधान किया जाए। इसके साथ-साथ आरटीओ कार्यालय जाने की बाध्यता समाप्त की जाए। विभाग द्वारा जन्म/मृत्यु प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए तहसील से तहसीलदार के आदेश होने की बाध्यता को समाप्त करते हुए सीधे स्थानीय निकाय में इसके अधिकार दिए जा सकते हैं। एक ऐसे पोर्टल का निर्माण किया जाए, जिसमें मध्यप्रदेश के समस्त विभागों के स्टैंडिंग सर्कुलर्स को अपलोड किया जाए। ई-दक्ष केंद्र का उपयोग वर्तमान में केवल शासकीय कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए किया जाता है, इस केंद्र का उपयोग जिले के परिवार के ऐसे बच्चे जो 11वीं एवं 12वीं में अध्ययन करते हैं, के कौशल उन्नयन के लिए किया जा सकता है। इन सुझावों के आधार पर प्रदेश सरकार आत्मनिर्भर मप्र का रोडमैप तैयार करेगी।

● नवीन रघुवंशी

योजनाओं के लिए अलग से पोर्टल विकसित किया जाए

भूमि, अधिग्रहण, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास के लिए प्रथक पोर्टल विकसित किया जाए, जिसके माध्यम से भू-अधिग्रहण परियोजनाओं की प्रगति की सतत निगरानी एवं समीक्षा की जा सकेगी। इस कदम से अवार्ड प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। इस पोर्टल पर राज्य के विभिन्न जिलों में पूर्व में किए गए समस्त भू-अधिग्रहण परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी एवं दस्तावेज उपलब्ध कराए जा सकते हैं। स्वरोजगार योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एवं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया का सरलीकरण आवश्यक है तथा मोबाइल एप पर भी उपलब्ध होना चाहिए। लाडली लक्ष्मी योजना अंतर्गत बालिका का पंजीयन माता-पिता के आधार क्रमांक के आधार पर किया जाए, जिससे आवेदन की पुनरावृत्ति नहीं होगी। सीएसआर फंड आकर्षित करने के लिए अधिक से अधिक जन उपयोगी प्रोजेक्ट्स तैयार कर कंपनियों को उसमें सहभागिता के लिए आकर्षित करना। स्व-सहायता समूह के सदस्यों को दिए गए ऋण पर किश्त चालू करने की अवधि में 6 महीने की रियायत दी जा सकती है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे लालजी टंडन का 21 जुलाई की सुबह लखनऊ के मेंदाता अस्पताल में निधन हो गया। 85 वर्षीय टंडन लखनऊ में अपने समर्थकों और लोगों के बाबूजी के नाम से जाने जाते रहे। लालजी टंडन 12 वर्ष की उम्र में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हो गए थे और 1960 में उन्होंने सक्रिय राजनीति में कदम रख दिया था। इसी दौरान उनकी मुलाकात पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से हुई, जैसे-जैसे समय बीताता गया लालजी टंडन और वाजपेयी का रिश्ता गहरा और अटूट होता गया जो आखिरी दम तक कायम रहा।



पार्षद से राज्यपाल तक का सफर

लालजी टंडन खुद कहते थे अटलजी ने राजनीति में उनके साथी, भाई और पिता तीनों की भूमिका अदा की है। करीब 60 के दशक में राजनीति में आए लालजी ने 5 दशक तक अटल जी का साथ निभाया। यही वजह है अटलजी के बाद उनकी राजनीतिक विरासत को लखनऊ में टंडन ने ही संभाला था। वे 2009 के लोकसभा चुनाव में लखनऊ सीट से सांसद चुने गए थे।

लालजी टंडन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ अपने पारिवारिक संबंध कई बार मंचों से साझा कर चुके हैं। वे कहते थे कि राजनीति में वह आज जो कुछ भी हैं उसका पूरा श्रेय वाजपेयी को ही जाता है। अटलजी ने राजनीति में उनके साथी, भाई और पिता तीनों की भूमिका को निभाया है। वाजपेयी के राजनीति से संन्यास लेने के बाद लालजी टंडन लखनऊ से भाजपा के प्रत्याशी बने। 2009 में पार्टी से टिकट मिलने के बाद लालजी टंडन पहले वाजपेयी से मिलने गए। इसके बाद चुनाव प्रचार में जुट गए। उस वक्त उन्होंने जनता के बीच यही प्रचार किया कि वह अटलजी की खड़ाऊं लेकर आए हैं। इस चुनाव में टंडन की बड़ी जीत हुई और वह पहली दफा चुनकर लोकसभा पहुंचे थे।

लालजी कोई भी बड़ा काम अटलजी के आशीर्वाद से ही शुरू किया करते थे। अटलजी और लालजी टंडन की मित्रता पर कभी राजनीतिक रंग नहीं चढ़ा। अटलजी के साथ उनके संबंध हमेशा एक जैसे ही रहे। वाजपेयी, लालजी और लखनऊ का रिश्ता अटूट था जो उनके दिल में लखनऊ बसता था। दोनों का लखनऊ प्रेम उनके बीच सेतु का काम करता था। 2014 के लोकसभा चुनाव में जब भाजपा ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया इसके बाद से ही मोदी के लखनऊ और वाराणसी से लोकसभा चुनाव को लेकर लड़ने को चर्चा तेज हो गई। दोनों सीटों को लेकर पार्टी के भीतर खींचतान की खबरें सामने आने लगीं।

2004 में जब साड़ी कांड से हुई परेशानी

2004 में लोकसभा चुनाव के पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी अपनी परंपरागत सीट लखनऊ से चुनाव लड़ रहे थे। चुनावों के दौरान ही अपने जन्मदिन के मौके पर टंडन ने गरीब महिलाओं को साड़ियां बांटने का कार्यक्रम भी रखा। इस कार्यक्रम में मची भगदड़ में कई महिलाएं और एक बच्चों की मौत हो गई थी। इस घटना को लेकर विपक्ष ने वाजपेयी को भी निशाना बनाया था। वहीं लालजी पर आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप भी लगे। विपक्ष की मांग के बाद टंडन पर मुकदमा भी दर्ज हुआ। इस दौरान चुनाव आयोग ने भाजपा से भी स्पष्टीकरण मांगते हुए यह तक कहा था 'क्यों न पार्टी की मान्यता ही रद्द कर दी जाए।' साड़ी कांड पर बवाल मचने के बाद भाजपा ने इसे लालजी का निजी कार्यक्रम बताया था। बाद में यह मामला टंडे बस्ते में चला गया। वहीं कांड में टंडन को वलीनचिट भी मिल गई। 2007 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान विवादित सीडी बांटने के मामले में चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की थी।

इसी बीच तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह की गाजियाबाद सीट छोड़कर लखनऊ से लड़ने की बात सामने आई तो लालजी ने लखनऊ सीट छोड़ने पर नाराजगी जाहिर की।

टंडन ने कहा था, 'उन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए सीट छोड़ने की बात खुद स्वीकार की थी और राजनाथ सिंह के लखनऊ से लड़ने को लेकर तो कोई बात ही नहीं हुई है।' जब लखनऊ सीट को लेकर बवाल बढ़ा तो लालजी ने सफाई देते हुए कहा था, 'राजनाथ सिंह मेरी पार्टी के अध्यक्ष हैं क्यों उनका नाम घसीटा जा रहा है। मेरे उनसे व्यक्तिगत संबंध हैं। हम अपने मन की बात एक दूसरे से कह सकते हैं। जब कोई बात मेरे सामने ऐसी आई ही नहीं कि कोई यहां से दावा पेश कर रहा है, जब पार्टी ने अभी तक इस बारे में कोई निर्णय ही नहीं किया तो बेवजह एक मुद्दा खड़ा किया जा रहा है। उसका कोई अर्थ नहीं है।'

टंडन का कहना था कि, 'मोदी के लिए मैंने स्वयं कहा कि अगर वह लड़ेंगे तो मुझे खुशी होगी और उनके लखनऊ से चुनाव लड़ने से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। मेरा सारा राजनीतिक जीवन लखनऊ में बीता, यहीं मेरा जन्म हुआ, यहीं मेरा अंत होगा।' बाद में भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति ने राजनाथ सिंह के नाम पर मुहर लगा दी। 2014

लोकसभा चुनाव में राजनाथ अटलजी का भेंट किया हुआ अंगवस्त्र पहनकर नामांकन दाखिल कराने पहुंचे थे। इस सीट से राजनाथ ने जीत हासिल की। इसके बाद से ही लालजी टंडन लखनऊ और उत्तर प्रदेश की राजनीति से कटते चले गए। 2018 में उन्हें बिहार का राज्यपाल बनाया गया था।

अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने पार्षद से लेकर मंत्री, सांसद और राज्यपाल तक का सफर तय किया। 1970 के दौर में इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ जयप्रकाश नारायण के राष्ट्रव्यापी आंदोलन में हिस्सा भी लिया। वे दो बार 1978 से 1984 तक और 1990 से 1996 तक उत्तर प्रदेश की विधानपरिषद् के सदस्य भी रहे हैं। 1991 से 1992 की उत्तरप्रदेश सरकार में वे मंत्री भी रहे। 1996 से 2009 तक तीन बार चुनाव जीतकर विधानसभा भी पहुंचे। 1997 में नगर विकास मंत्री भी रहे। इसके अलावा उप विधानसभा में विपक्ष के नेता का दायित्व भी संभाल चुके हैं। 2009 में लखनऊ लोकसभा सीट से वे सांसद पहुंचे। 2018 में बिहार के राज्यपाल बने और 2019 में वे मध्यप्रदेश के राज्यपाल बने।

● राजेश बोरकर

सरकार 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का दावा कर रही है, लेकिन हकीकत यह है कि आज भी किसान बदहाल और परेशान हैं। किसानों के कल्याण के नाम पर सरकार तरह-तरह के वादे और दावे करती रही है। उन्हीं में से एक है फसल बीमा योजना लेकिन मध्य प्रदेश में बीमा प्रीमियम भरने के बावजूद हजारों किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसे में आमदनी दोगुनी कैसे हो पाएगी, यह सवाल किसान पूछ रहे हैं।

मध्य प्रदेश में हर साल लाखों किसान फसल बीमा कराते हैं वह समय पर प्रीमियम भी भरते हैं। बावजूद इसके उनको बीमा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। राजधानी से करीब 200 किलोमीटर दूर आगर मालवा जिला मुख्यालय पर रूपनारायण अपने परिवार के नाम से पांच कृषि खातों की करीब 60 बीघा जमीन पर हर साल सहकारी संस्था से ऋण लेते हैं, और हर फसल में फसल बीमा योजना का प्रीमियम भी भरते हैं, लेकिन कहते हैं बीमा आज तक नहीं मिला। रूपनारायण कहते हैं- बीमा का प्रीमियम कटता है दो फसल में, गेहूँ और सोयाबीन में पर आज तक मुआवजा मिला ही नहीं, बीमा हमारा फुल काटते हैं, कहते हैं जब सरकार से आएगा तब मिलेगा। कभी कहते हैं कि पटवारी ने गिरवारी नहीं की होगी, हमारी चप्पल घिस गई जाते-जाते।

वहीं आवर गांव में नारायण सिंह कहते हैं उनके गांव में किसी किसान को फसल बीमा योजना का पैसा नहीं मिला, जबकि आसपास के दूसरे सारे गांवों में इसका लाभ मिल गया। इसी गांव के भुवान सिंह और देवी सिंह अपने खातों में पासबुक के पन्ने पलटकर बार-बार ये देखने की कोशिश करते हैं कि शायद उनकी फसल बीमा की राशि आ गई हो। नारायण सिंह कहते हैं, 'प्रीमियम साल का 15 हजार देते हैं, 18 में जो बीमा था वो हमें नहीं मिला लेकिन हमारे खेत के पास देवली के पास मिला है, तीनों दिशाओं में तीन गांव हैं, उन्हें बीमा मिला है। बैंक कहता है पटवारी जाने, पटवारी कहता है बैंक जाने, आज तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला।'

उधर, भुवान सिंह का कहना है कि साल भर में दो बार कटे हैं, प्रीमियम काटकर भर लेते हैं, पलटी करते हैं, ब्याज और बीमा भी काटते हैं, हमारे पास वाले गांव में मुआवजा मिला लेकिन हमारे गांव में नहीं। खराब मौसम और खेती के लिए कर्ज से राहत के लिए 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई थी। इसके तहत किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2 फीसदी प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए किसानों को 5 प्रतिशत प्रीमियम का



बीमा योजना का लाभ नहीं

प्रीमियम मरा 1411 करोड़, दावा मिला 171 करोड़

फसल बीमा की हकीकत क्या है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि साल 2017-18 रबी सीजन में 59,89,531 किसानों ने बीमा करवाया, किसान, केंद्र-राज्य ने मिलाकर 1411 करोड़ रुपए का प्रीमियम भरा, दावा मिला 171 करोड़ रुपए का। 2018 खरीफ में 35,00,244 किसानों ने प्रीमियम भरा, 4049 करोड़ रुपए का प्रीमियम भरा गया, दावा वितरण हुआ 1921 करोड़ रुपए का। 2018-19 रबी सीजन में 25,04,463 किसानों ने बीमा करवाया, 1473 करोड़ रुपए का प्रीमियम जमा हुआ, भुगतान हुआ 1060 करोड़ रुपए का। 2019 खरीफ में 37,27,835 किसानों ने बीमा करवाया, 2350 करोड़ रुपए का प्रीमियम भरा गया। पैसे मिले नहीं हैं। 2019-20 रबी सीजन में 34,38,996 किसानों ने बीमा करवाया, 947 करोड़ रुपए का प्रीमियम भरा गया, दावे का निपटारा नहीं हुआ है। वैसे 2018 से बीमे का पैसा भी सियासी दावपेंच में उलझा था 1 मई को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 15 लाख किसानों के बैंक खातों में फसल बीमा दावा राशि के 2,981.24 करोड़ रुपए मंत्रालय से ऑनलाइन ट्रांसफर किए।

भुगतान करना पड़ता है। अमूमन कर्ज देने वाला बैंक, सहकारी संस्था खुद रकम खाते से काटकर बीमा कंपनी को दे देते हैं, सरकारी व्यवस्था में पटवारी और कृषि विभाग के अधिकारी मिलकर किसान के खेत पर जाकर नुकसान का आंकलन

करते हैं, लेकिन यहां पेंच है क्योंकि इसका पैमाना खेत या गांव ना होकर पटवारी हल्का है।

आगर मालवा में जिला सहकारी बैंक के सहायक नोडल अधिकारी सुरेश शर्मा कहते हैं, 'व्यक्तिगत किसान को नुकसान है तो उसको व्यक्तिगत रूप से बीमे की मांग करनी होगी, जैसे बोनी में बीज फेल हो गया, आग लग गई, उसके व्यक्तिगत अलग से होता है नहीं तो हल्के से ही होता है।' जानकार पटवारी हल्के के अलावा भी इसमें कई कमियां गिना रहे हैं। मध्यप्रदेश में कृषि सलाहकार परिषद के पूर्व सदस्य केदार सिरोही कहते हैं, 'ये बीमा योजना कॉर्पोरेट को ज्यादा फायदेमंद रही है। अगर 100 हैक्टेयर से कम बुवाई उस यूनिट पर हुई है तो उसका बीमा नहीं होगा, जो यूनिट है वो किसान रखना चाहिए था लेकिन अभी भी पंचायत स्तर है, पटवारी हल्का है, उसमें कई समस्या आती है, तीसरा सबसे बड़ा इंडेमेन्टी 70-80 प्रतिशत है यानी 100 रुपए में 80 प्रतिशत ही मिलेगा, औसत में भी नुकसान है।' जानकारों को ऐतराज है लेकिन सरकार को लगता है कि पटवारी हल्के से ज्यादा फायदा हो रहा है।

कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा, 'पहले इकाई तहसील था, जब मैं राजस्व मंत्री बना तो पटवारी हल्का किया, उस समय पटवारी हल्के थे 11622, उसके हमने पंचायत को पटवारी हल्का माना। इसलिए 23 हजार पटवारी हल्के हैं, 54 हजार गांव हैं इसलिए एक गांव इकाई है, उससे फसल बीमा का लाभ अधिक मिल रहा है, सबसे अधिक कहीं मुआवजा मिला है तो देश में मध्यप्रदेश में मिला है।

● प्रवीण कुमार

केंद्र सरकार द्वारा देश के 80 करोड़ गरीबों के लिए शुरू की गई महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का कम से कम देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में कई गंभीर सवालों से सामना हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह

है कि क्या अब किसी विपदा के वक्त फौरी राहत के तौर पर जैसे-तैसे की गई पेट भरने की जुगत से ही गरीबों का कल्याण हुआ मान लिया जाएगा? अगर नहीं तो क्यों सरकार इस अन्न योजना को 'दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा योजना' के रूप में प्रचारित कर गरीबों के कल्याण से जोड़ने, उसकी वाहवाही लूटने और जिन रोजी-रोजगारों से वास्तविक गरीब कल्याण मुमकिन है, उनकी योजनाओं में कोताही बरतने पर अमादा है? क्यों प्रवासी मजदूरों को वैकल्पिक रोजगार देने के गरीब रोजगार कल्याण अभियान को उसने 6 राज्यों के 116 जिलों और 125 दिनों तक ही सीमित रखा है? क्या वह भी पिछले दिनों उच्चस्तरीय हलकों में पूछे जा रहे इस बेहद अमानवीय और निर्दयी सवाल से इत्तेफाक रखती है कि जब गरीबों को मुफ्त राशन दिया ही जा रहा है तो उनके जन-धन खातों में पांच-पांच सौ रुपए डालने की भला क्या जरूरत है?

लॉकडाउन के शुरुआती दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल, मई और जून महीनों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का ऐलान किया था, जिसके तहत गरीब परिवारों के हर व्यक्ति को हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल तथा प्रति परिवार एक किलो दाल मुफ्त देने की बात थी। यह राहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत गरीब परिवारों को दो से तीन रुपए प्रति किलो की दर से मिलने वाले अनाज के अतिरिक्त थी। इन तीन महीनों में देश के विभिन्न हल्कों से इस योजना के ठीक से जमीन पर न उतर पाने की अनेक शिकायतें सामने आईं तो यह मांग भी उठी कि गरीबों को मुफ्त अनाज के बदले उनके जन-धन खातों में सीधे नकद सब्सिडी दी जाए, जिससे वे किसी कोटेदार के मोहताज होने के बजाय अपनी सुविधा से जहां कहीं से भी चाहें अपनी जरूरत का अनाज या दूसरी चीजें खरीद लें। यह मांग इस जमीनी हकीकत के मद्देनजर थी कि इस संकटकाल में गरीब सिर्फ मुफ्त अनाज से काम नहीं चला सकते। लेकिन प्रधानमंत्री ने इसको मानने की बजाय अपनी योजना का जयगान करते हुए उसे आगामी नवंबर तक बढ़ा दिया। अब सारे गरीबों को इसका लाभ न मिल पाने की शिकायतें तो अपनी जगह रहीं, जिनको लाभ मिल रहा है, वे भी मुफ्त मिला अन्न दूसरी जरूरतों के लिए औने-पौने दाम पर बेचने को अभिशप्त हो रहे हैं।

इस बीच किसी भी स्तर पर इस सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा कि क्या सुनिश्चित रोजगार के बढ़ते अभाव के बीच ऐसी राहों से



गरीबों की अनदेखी

अनियमित रोजगार में लगे लोग और रोजगारविहीन हो सकते हैं

चिंता की बात इसलिए भी है कि अभी तो उल्टे यही आशंका ज्यादा है कि कहीं भविष्य में अनियमित रोजगार में लगे लोगों की और बड़ी संख्या रोजगारविहीन न हो जाए। ध्यान देने की बात है कि 80-85 प्रतिशत गरीब अनियमित रोजगार के अवसरों तथा छोटे-छोटे संसाधनों से जुड़े हैं और उनके इन अवसरों के घटने व साधनों के टूटने का कारण केवल कोरोना व लॉकडाउन नहीं हैं। इन दोनों ने तो सिर्फ इस समस्या को तात्कालिक रूप से बढ़ाने और सतह पर लाने का काम किया है। इसलिए लोगों को यह कहते सुना जा सकता है कि कोरोना से बड़ी महामारी रोजगार जाने की है और इसे रोका नहीं गया तो यह कोरोना से ज्यादा लोगों को परिवार समेत मार देगी। बढ़ती आर्थिक तंगी के चलते आत्महत्याओं व आर्थिक-सामाजिक अराजकताओं की बढ़ती आशंकाओं से भी वे कम त्रस्त नहीं हैं। यकीनन, लॉकडाउन के दौरान रोजगारों के खात्मे की प्रक्रिया अपने विकरालतम रूप में प्रकट हुई है और कहा नहीं जा सकता कि कोरोना से जंग की समाप्ति के बाद भी अपने कामों से हटे या हटाए गए लोगों की पूरी तरह से वापसी नहीं हो पाएगी। हां, उनकी एक संख्या वापस जरूर होगी लेकिन उन पर दूसरे रूपों में रोजगारमारक आर्थिक या रोगाणुजनित महामारी की मार पड़ने का खतरा मौजूद और बढ़ता भी रहेगा। साफ कहे तो यह उनके लिए पिछले 30 सालों में बढ़ते रहे रोजगारविहीन विकास की एकमुश्त कीमत चुकाने का वक्त है। चाहे वे किसान हों, दस्तकार, छोटे उद्यमी या कारोबारी।

गरीबों का वास्तविक कल्याण हो पाएगा और उनकी गरीबी कम या खत्म हो पाएगी? अगर नहीं

तो क्या इसे 'राहत योजना' की जगह 'कल्याण योजना' कहना उचित है? यह अन्न योजना क्योंकर अन्नपूर्णा, पुष्टहार और मिड-डे मील या फिर रोजगार गारंटी की राहत योजनाओं से अलग है? कई जानकार यह भी पूछ रहे हैं कि गरीबों की संख्या तक को विवादास्पद बना दिए जाने के बाद प्रधानमंत्री इस योजना के लिए अचानक 80 करोड़ गरीब कहां से ढूंढ लाए हैं और क्या यह संख्या उनकी सरकार के कामकाज पर कोई टिप्पणी नहीं है? खासकर जब बड़ी संख्या में गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाए जाने के दावों के बीच उनकी संख्या ही विवादास्पद बना दी गई है। देश में 80 करोड़ गरीब हैं तो वे बड़े-बड़े दावे तो स्वतः झूठे सिद्ध हो जाते हैं, जिनमें बहुआयामी गरीबी में तेजी से कमी आने की बात कही जाती रही है।

प्रसंगवश, देश में गरीबों की गिनती करने वाली आर्थिक संस्थाओं एवं आयोगों की रिपोर्टों में भारी अंतर रहा है। 1995-96 के बाद आई रिपोर्टों में से कुछ ने गरीबों को कुल आबादी का 50 से 55 प्रतिशत, तो कुछ ने 40 से 42 प्रतिशत तथा कुछ ने 25 से 30 प्रतिशत बताया है। प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए 80 करोड़ लोगों को गरीब बताकर उनकी संख्या को 60 प्रतिशत से ऊपर पहुंचा दिया है। रोजाना कमाने-खाने वाले लोगों में बढ़ती गरीबी की वजह से खाद्यान्न का भी संकट बढ़ा है। कहना होगा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना इस बड़ी आबादी के लिए राहतकारी भी तभी तक सिद्ध होगी, जब तक वह चलेगी, लेकिन जब तक गरीबों के रोजगार के अवसरों व साधनों में वृद्धि नहीं होगी और उनमें स्थायित्व नहीं आ जाएगा, गरीबों का कल्याण तो होने से रहा।

● श्याम सिंह सिकरवार

देश में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला मप्र वन्य प्राणियों की तस्करी का अंतर्राष्ट्रीय अड्डा बन गया है। आए दिन यहां वन्य प्राणियों के शिकार के मामले सामने आते रहते हैं। आलम यह है कि बाघ से लेकर सांप तक के तस्कर पूरे प्रदेश में सक्रिय हैं। गत दिनों उज्जैन में वन्यजीवों की तस्करी करने वाले दो गिरोह को एसटीएफ की टीम ने दबोचा। पुलिस गिरफ्त में आए 10 तस्करों में चार महिलाएं भी हैं। टीम ने एक गिरोह के पास से एक दुर्लभ गोल्डन उल्लू तो दूसरे गिरोह के पास से एक दोमुंहा सांप बरामद किया है। बताया जा रहा है कि बाजार में इनकी कीमत दो से तीन करोड़ रुपए है। ये लोग स्थानीय तस्कर को करीब एक करोड़ रुपए में वन्यजीवों को बेचने वाले थे।

मप्र में आए दिन वन्यजीवों की तस्करी में जुटे लोग पकड़े जाते हैं। इन तस्करों से मिले संकेत के अनुसार यहां के वन्यजीवों की विदेशों में सबसे अधिक मांग है। बताया जाता है कि मप्र से गोल्डन उल्लू, दोमुंहा सांप और पेंगोलिन की सबसे अधिक तस्करी की जा रही है। ये सभी असम, मिजोरम व मेघालय में व्यापारियों को बेचे जाते हैं। इन व्यापारियों द्वारा म्यांमार से होते हुए चीन भेजा जाता है। इनकी म्यांमार, चीन, थाईलैंड, मलेशिया, हॉन्गकॉन्ग, वियतनाम आदि देशों में अधिक मांग है।

सूत्र बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में मप्र पेंगोलिन की तस्करी का केंद्र बना हुआ है। अलग-अलग राज्यों से पेंगोलिन के शिकार और तस्करी के लिए बड़ा रैकेट काम कर रहा है। मप्र से नेपाल के रास्ते पेंगोलिन की तस्करी चीन तक हो रही है। मप्र पेंगोलिन की तस्करी का अंतर्राष्ट्रीय अड्डा बन गया है और बालाघाट शिकार का सेंटर पॉइंट। मप्र में पेंगोलिन के शिकार और तस्करी का सिलसिला साल-दर-साल बढ़ता ही जा रहा है। बालाघाट इसके शिकार और तस्करी का सेंटर पॉइंट बन गया है। विदेशों में इसकी बढ़ती मांग और तस्करी के लिए सक्रिय गिरोह से विलुप्त प्रजाति के पेंगोलिन पर खतरा बढ़ गया है। शेड्यूल 1 कैटेगरी का वन्यप्राणी पेंगोलिन वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय तस्करी से जुड़े लोगों की गिरफ्त में है। अब तक एसटीएफ ने डेढ़ सौ से अधिक लोगों को इसकी तस्करी व शिकार के मामले में गिरफ्तार किया है। लेकिन सजा महज एक केस में हुई है। ज्यादातर मामले सुनवाई में हैं, और इन केसों के आरोपी कानून की पहुंच से काफी दूर हैं।

एसटीएफ के रिकार्ड में अब तक 164 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। 13 केस रजिस्टर्ड। चार ट्रांसफर केस हैं जिसकी एसटीएफ जांच कर रही है। पांच केस में एसटीएफ अनुसंधान में मदद कर रही है। एसटीएफ की जांच में सामने आए केसों में अब तक एक में सजा हुई है। नरसिंहगढ़

तस्करी का अंतर्राष्ट्रीय अड्डा



बालाघाट पेंगोलिन शिकार का सेंटर पॉइंट बना



सीसीएफ बालाघाट एनके सनोडिया कहते हैं कि बालाघाट का जंगल काफी बड़ा है और पेंगोलिन के लिए यहां उपयुक्त वातावरण है। जिसके चलते पेंगोलिन बहुतायत में पाए जाते हैं। यही वजह है कि यहां शिकार के मामले अधिक सामने आते हैं। वन विभाग की सतर्कता से पेंगोलिन के शिकारी भी पकड़े जा रहे हैं। उसके संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। पूर्व में भी एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई कर अंतर्राष्ट्रीय संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया था। जिसमें करीब 12 राज्यों से डेढ़ सैकड़ से अधिक लोगों की गिरफ्तारियां हुई थीं। वज्रशल्क या पेंगोलिन या फोलीडोटा का एक गण है। इसके शरीर में कैराटीन के बने शल्क होते हैं। जिससे यह अन्य प्राणियों से अपनी सुरक्षा करता है। यह स्केलनुमा संरचना का अकेला स्तरधारी जीव है, जो अफ्रीका व एशिया में पाया जाता है। इसे मध्यभारत में चीटीखोर के नाम से भी जाना जाता है। यह मूलरूप से चीटियों को खाकर ही अपना जीवन यापन करता है और बिलों में रहता है। रात के वक्त ही यह जंगलों में विचरण करता है।

मामले में 5 आरोपियों को चार-चार साल की सजा व 10-10 हजार रुपए का कोर्ट ने अर्थदंड लगाया है। पेंगोलिन के शिकार और तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली से भी मॉनीटरिंग की जा रही है। इसी दौरान सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखते हुए वारासिवनी वन परिक्षेत्र में पेंगोलिन समेत 3 लोगों को पकड़ने में सफलता मिली है। इतना ही नहीं इस मामले में 12 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। एसटीएफ की टीम 4 फरार संदिग्धों की भी तलाश कर रही है।

अब तक गिरफ्त में आए आरोपियों से हुए खुलासे में पेंगोलिन के शिकार के पीछे अंधविश्वास की कड़ी भी उजागर हुई। जिसमें यह सामने आया है कि ग्रामीण स्तर पर लोग नोटों की झड़ती के लिए भी अंधविश्वास के चलते शिकार की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। पेंगोलिन भी बाघ की तरह शेड्यूल-1 का वन्य प्राणी है। इसके भी शिकार मामले में सात साल की सजा का प्रावधान है, लेकिन एक को भी अब तक 10 साल में इतनी सजा नहीं हुई। करीब 10 मामलों में अब तक महज एक केस में आरोपियों को 4-4 साल की सजा हुई है। पेंगोलिन भी बाघ की तरह शेड्यूल-1 कैटेगरी का वन्य प्राणी है। इसके शिकार में बाघ के बराबर ही शिकार में कानूनी प्रावधान है। इतना ही नहीं इसके शल्क भी बाघ की खाल के बराबर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत रखते हैं। इसके शल्क स्थानीय बाजार में 50 हजार रुपए किलो तक बिकते हैं। जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत डेढ़ से दो लाख रुपए प्रति किलो है।

● राकेश ग्रोवर

कलंक मिटाने की कोशिश

देश और दुनिया में बुंदेलखंड की पहचान सूखा, गरीबी, पलायन और बेरोजगारी के रूप में है, लेकिन अब यहां के लोग हालात बदलना चाहते हैं। इसके लिए सबसे जरूरी पानी को सहेजने या उसकी बचत करने की दिशा में पहल की है। इसके तहत खेत का पानी खेत में और गांव का पानी गांव में ही रोकने की जुगत तेज की गई है, जिससे बुंदेलखंड के माथे पर लगे कलंक को मिटाया जा सके।

बुंदेलखंड के बांदा जिले के बबेरु डेवलपमेंट ब्लॉक के अंधाव गांव में किसानों ने पानी को सहेजने की योजना बनाई है। इसके जरिए बारिश का पानी गांव और खेत से बाहर नहीं जा पाएगा। अगर यह कोशिश सफल होती है तो गांव में पानी के संकट की समस्या को दूर किया जा सकेगा। शोध छात्र और जल संरक्षण के लिए काम करने वाले पर्यावरण कार्यकर्ता रामबाबू तिवारी ने बताया कि गांव की 300 बीघे के खेतों में मेड़ बनाकर बारिश के पानी को इकट्ठा करने का काम किया जा रहा है। गांव वालों ने 300 बीघे में (जल संरक्षण के लिए 'खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में' अभियान के तहत खेत पर मेड़, मेड़ पर पेड़) मेड़बंदी करवा दी है। इस मेड़बंदी से खेत का पानी खेत में ही रह जाएगा और किसान धान तक की खेती कर सकेंगे।

कोरोनाकाल में घर वापस आए प्रवासी मजदूर और किसान, जो रोजगार और आमदनी के लिए अन्य राज्यों में पलायन कर चुके थे, वह इस समय अपने गांव घर में आ चुके हैं। ये कामगार भी अपने खेतों में काम कर रहे हैं और मेड़बंदी में लगे हैं। ये प्रवासी मजदूर भी अपने खेतों के जरिए अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाह रहे हैं। रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों को जाने वाले लव विश्वकर्मा बताते हैं, इस साल हम लोगों ने अपने चार बीघे खेत में अपने प्राइवेट खर्च से मेड़ बनाई है और धान की खेती के बाद गेहूं की खेती करेंगे। हर साल इस चार बीघे खेत को बटाई को दे देते थे लेकिन इस साल खुद खेती कर रहे हैं। इसी के चलते खेत में पैसा खर्च कर खेत को समतल कराया गया और मेड़ बनवाई गई। इससे खेती में उपज बढ़ेगी और हम अपने सालभर का खर्चा इसी खेत से चला सकेंगे क्योंकि इस कोरोना के चलते अब हम दूसरे राज्यों में कमाने नहीं जाएंगे।

कोरोना की वजह से अपने गांव लौटे किसानों की मदद के लिए लोग भी आगे आए हैं। खेतों को समतल करने और मेड़बंदी के लिए ट्रैक्टर की जरूरत थी, लेकिन उनके पास नगदी नहीं थी तो ट्रैक्टर मालिकों ने किसानों की मदद करने का फैसला लिया। इन किसानों से ट्रैक्टर मालिकों ने केवल डीजल का पैसा लिया है और फसल आने तक बाकी किराया और अन्य मजदूरी लेंगे।

किसान मनोज दीक्षित बताते हैं, इस साल 'खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में'



सुखाड़ जैसे हालात से परेशान बुंदेलखंड के किसान

लॉकडाउन और खराब मौसम के बाद खरीफ किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, बुंदेलखंड का किसान पिछले कई वर्षों से मौसम की मार झेल रहा है। कभी बेवक्त बारिश, सूखा, अतिवृष्टि और ओलावृष्टि जैसे हालात बनते रहे। पिछले खरीफ सीजन की दलहनी फसलें बेवक्त बारिश से तबाह हुई थीं, नुकसान के इस मंजर को किसान भुला नहीं पाए। पूरे साल टोकर खाने के बाद किसान फायदे में नहीं रहा। बुंदेलखंड के लाखों किसानों ने उड़द, सोयाबीन जैसी दलहनी फसलें बो दीं। बारिश ना होने से तेज धूप का प्रकोप है, कीट पतंगे फसलों के पत्तों को खा रहे हैं खरपतवार बढ़ रहे हैं। पिछले साल हुई बेवक्त बारिश से किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी। यही अंदेशा सूखे जैसे हालात से फसल बर्बादी का डर किसानों को सता रहा है। बुंदेलखंड में सूखे जैसे स्थिति भयावह रूप धारण कर रही है जलवायु परिवर्तन की उत्पन्न परिस्थितियां किसानों की चिंता बढ़ा रही है।

मिशन के तहत नौ बीघे खेत में मेड़ बनाई गई है। इसके पहले खेत में हम लोग सिर्फ एक ही फसल ले पाते थे लेकिन इस साल हम लोग दोहरी फसल लेने की तैयारी में हैं और इस खेत के मेड़ में पेड़ भी लगा रहे हैं। निश्चित ही इससे हमारी आमदनी बढ़ेगी, और गांव में रोजगार बढ़ेगा। ईश्वर की कृपा से बस बारिश अच्छी हो जाए।

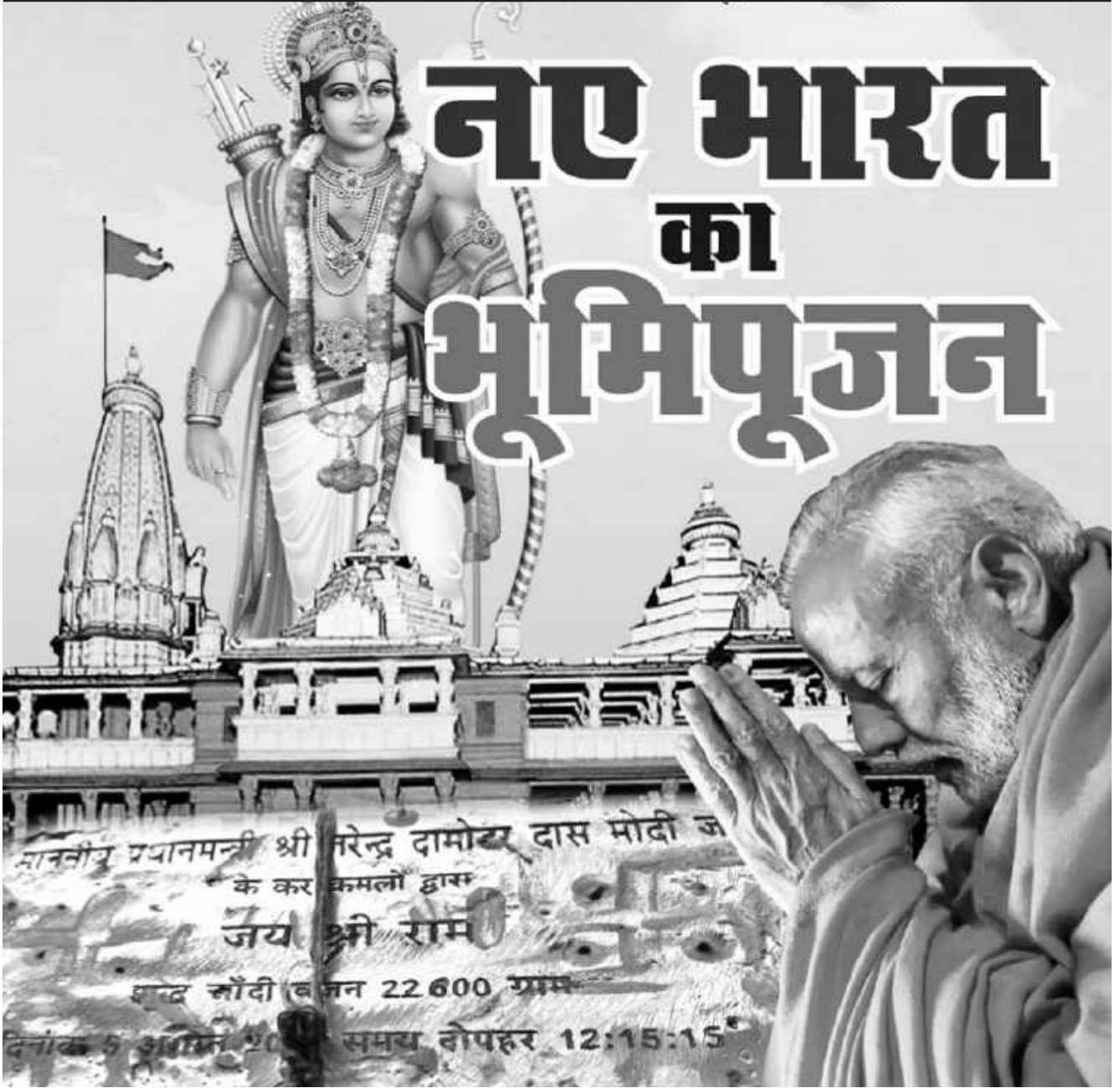
जल संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले बुंदेलखंड के निवासी और कई किताबों के लेखक डॉ. केएस तिवारी का कहना है, सतही

और भूगर्भीय जल बुरी तरह प्रदूषित हो चुका है। उसका कारण, हमारे द्वारा जल का अति दोहन और इस्तेमाल दोनों हैं। जल संरक्षण के लिए जरूरी है कि जल संरचनाओं को संरक्षित किया जाए। उनको अपने पुराने रूप में लाया जाए। बांदा के अंधाव गांव में जो एक्सपेरिमेंट (प्रयोग) किया जा रहा है वह तारीफ के काबिल है। आने वाले सालों में इसके नतीजे देखने को मिल सकते हैं। लोगों में पानी के संरक्षण के लिए जागरूकता लाने का यह बेहतरीन प्रयास है।

सत्तर वर्षीय किसान दयाली कहते हैं, जैसे बंदर की चूक डाल से हो जाए तो पूरे साल बंदर बिरादरी में शामिल नहीं हो सकता इसी तरह आषाढ़ (खरीफ की फसल) में किसान की फसल से चूक हो जाए तो पूरे साल किसान नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता एक बार फिर ऐसे ही हालात बन रहे हैं। बड़ी जोत के किसान दयाली ललितपुर जिले के महरोनी तहसील अंतर्गत सतलींगा गांव के रहने वाले हैं। बारह सदस्यों वाले परिवार के मुखिया दयाली की पिछले साल तैयार उड़द की फसल ज्यादा बारिश के कारण खेत में ही सड़ गई थी, इस बार दयाली की चिंता सता रही है कि उड़द, सोयाबीन की फसल पिछले साल की तरह इस बार सूखने से खराब ना हो जाए। किसानों को उम्मीद थी इस साल खरीफ सीजन की दलहनी (उड़द, मूंग, सोयाबीन, तिलहन) फसल के लिए मानसून समय पर आएगा 21 जून के बाद हुई बारिश के तुरंत बाद जिले के किसानों ने फसल बोते ही मानसून ने साथ छोड़ दिया। 25 दिन की फसल सूखने की कगार पर है, वहीं कई किसानों के बीज मर गए उन्हें दोबारा बुवाई करनी पड़ी।

● सिद्धार्थ पांडे

नए भारत का भूमिपूजन



5 अगस्त 2020 का दिन भारत की संस्कृति, संस्कार और आध्यात्मिक विरासत का एक बहुत ही पावन और ऐतिहासिक पड़ाव होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम के जन्म स्थान अयोध्या में उनके भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य का भूमिपूजन इसी दिन होगा। करीब 500 वर्षों बाद यह पावन दिन आया है। इसकी खुशी और भावुकता हम सभी समझ सकते हैं। कभी-कभी घोर आश्चर्य होता है कि प्रभु श्रीराम के जन्म स्थान पर उनका एक भव्य मंदिर बनाने में आजाद भारत को 70 साल लग गए।

● राजेंद्र आगाल

तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है- जासु बिरहं सोचहु दिन राती। रटहु निरंतर गुन गन पांती॥ रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता। आयउ कुसल देव मुनि त्राता॥ यानी जिनके विरह में आप दिन-रात सोच करते (घुलते) रहते हैं और जिनके गुण समूहों की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वे ही रघुकुल के तिलक, सज्जनों को दुःख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्रीराम जी सकुशल

आ गए। तुलसी बाबा की यह चौपाई 5 अगस्त को उस दिन साकार होगी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में भारतीय संस्कृति, संस्कार, आध्यात्मिक विरासत के प्रतिरूप श्रीराम मंदिर निर्माण का भूमिपूजन करेंगे। यह केवल एक मंदिर का भूमिपूजन नहीं होगा, बल्कि यह नए भारत का भूमिपूजन होगा। हमारी सामाजिक एकता, अखंडता को मजबूत बनाने में यह मंदिर मील का पत्थर साबित होगा। इसलिए 5 अगस्त का इंतजार केवल भारतीयों को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को है।



श्रीराम मंदिर ही नहीं एक नए युग का भी है भूमिपूजन

प्रधानमंत्री के कारण ही देश और दुनिया लगभग पांच शताब्दी बाद इस शुभ मुहूर्त की अनुभूति कर पा रही है। 5 अगस्त, 2020 को भूमिपूजन और शिलान्यास न केवल मंदिर का है वरन एक नए युग का भी है। यह नया युग प्रभु श्रीराम के आदर्शों के अनुरूप नए भारत के निर्माण का है। यह युग मानव कल्याण का है। यह युग लोककल्याण हेतु तपोमयी सेवा का है। यह युग रामराज्य का है। भाव-विभोर करने वाले इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रत्येक देशवासी का मन प्रफुल्लित होगा, किंतु स्मरण रहे प्रभु श्रीराम का जीवन हमें संयम की शिक्षा देता है। उत्साह के बीच हमें संयम रखते हुए वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत शारीरिक दूरी बनाए रखना है, क्योंकि यह भी हमारे लिए परीक्षा का क्षण है। विश्व के विभिन्न भागों में मौजूद समस्त श्रद्धालुजन 4 एवं 5 अगस्त को अपने-अपने निवास स्थान पर दीपक जलाएंगे और धर्माचार्यगण देवमंदिरों में अखंड रामायण का पाठकर दीप जलाएंगे। ऐसे ऐतिहासिक क्षण का प्रत्यक्ष अवलोकन किए बिना गोलोक पधार चुके अपने पूर्वजों का स्मरण कर उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेंगे और पूर्ण श्रद्धाभाव से प्रभु श्रीराम का स्तवन करेंगे।

करीब 500 साल बाद सकल आस्था के प्रतिमान रघुनंदन प्रभु श्रीराम की जन्मस्थली धर्मनगरी अयोध्या की पावन भूमि पर श्रीरामलला के भव्य और दिव्य मंदिर की स्थापना की प्रक्रिया गतिमान है। लगभग पांच शताब्दियों की भक्तपिपासु प्रतीक्षा, संघर्ष और तप के उपरांत कोटि-कोटि सनातनी बंधु-बंधवों के स्वप्न को साकार करते हुए पांच अगस्त को अभिजीत मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्रीरामलला के चिर अभिलाषित भव्य-दिव्य मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी। यह अवसर उल्लास, आह्लाद, गौरव एवं आत्मसंतोष और करुणा का है। हम भाग्यशाली हैं कि प्रभु श्रीराम ने हमें इस ऐतिहासिक घटना के साक्षी होने का सकल आशीष प्रदान किया। भाव-विभोर कर देने वाली इस बेला की प्रतीक्षा में पांच शताब्दियां व्यतीत हो गईं। दर्जनों पीढ़ियां अपने आराध्य का मंदिर बनाने की अधूरी कामना लिए भावपूर्ण सजल नेत्रों के साथ ही इस धराधाम से परमधाम में लीन हो गईं, किंतु प्रतीक्षा और संघर्ष का क्रम सतत जारी रहा। अब वह शुभ घड़ी आ ही गई जब कोटि-कोटि सनातनी आस्थावानों के त्याग और तप की पूर्णाहुति

होने जा रही है। मर्यादा के साक्षात् प्रतिमान, पुरुषोत्तम, त्यागमयी आदर्शसिक्त चरित्र के नरेश्वर, अवधपुरी के प्राणप्रिय राजा श्रीराम अपने वनवास की पूर्णाहुति कर हमारे हृदयों के भावपूरित संकल्प स्वरूप सिंहासन पर विराजने जा रहे हैं।

राष्ट्र का मंदिर

अयोध्या में निर्मित होने वाला भव्य राम मंदिर राष्ट्र का भी मंदिर होगा। भारत के स्वाभिमान, आत्मसम्मान और भारत की आध्यात्मिक विरासत- 'एकं सद् विप्रा बहुधा वदति' का भी जयगान होगा। इसलिए 5 अगस्त का दिन राष्ट्र के आत्मसम्मान और स्वाभिमान के लिए भी अहम होगा। भव्य राम मंदिर के बाद अयोध्या नए रूप में संवरेगी और निखरेगी। विश्व की धरोहर बनेगी। लाखों की संख्या में भक्त और पर्यटक आएंगे और इलाके के विकास में चार चांद लगाएंगे। मंदिर निर्माण से कबीर, रहीम और रसखान की सोच को एक नई मजबूती मिलेगी। यही तो है भारत की आध्यात्मिक विरासत जो सभी को अनुप्राणित करती है। यही तो मर्यादा पुरुषोत्तम के जीवन का उपदेश भी है।

इनके जिम्मे है भव्य राम मंदिर का निर्माण

राममंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष की कमान नृपेंद्र मिश्रा के हाथों में है। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वंपत राय रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव हैं। अयोध्या आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले महंत नृत्य गोपाल दास श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। ऐसे में राममंदिर निर्माण के लिए उन्हें सबसे अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील के. पराशरण रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के स्थायी सदस्य हैं। पराशरण ने सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या केस में लंबे समय से हिंदू पक्ष की पैरवी की। अयोध्या राज परिवार के बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के स्थायी सदस्य हैं। राम मंदिर निर्माण में बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं। श्रीरामजन्मभूमि मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में दलित समुदाय के तौर पर कामेश्वर चौपाल स्थायी सदस्य के तौर पर शामिल हैं। 1989 के राम मंदिर आंदोलन के समय हुए शिलान्यास में कामेश्वर ने ही राम मंदिर की पहली ईंट रखी थी। होम्सोपैथी के डॉक्टर अनिल कुमार मिश्र श्रीरामजन्मभूमि मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के स्थायी सदस्य हैं। मिश्र राममंदिर आंदोलन के दौरान विनय कटियार के साथ जुड़े थे। निर्माही अखाड़ा के प्रमुख महंत दिनेंद्र दास भी श्रीरामजन्मभूमि मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के स्थायी सदस्य के तौर पर शामिल हैं। निर्माही अखाड़े की ओर से सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय तक मुकदमा लड़ते रहे हैं। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वतीजी महाराज श्रीरामजन्मभूमि मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य हैं। वे बद्रीनाथ स्थित ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं। जगतगुरु मध्वाचार्य स्वामी विश्व प्रसन्नतीर्थ जी महाराज श्रीरामजन्मभूमि मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी सदस्य हैं। वो कर्नाटक के उडुपी स्थित पेजावर मठ के 33वें पीठाधीश्वर हैं। युगपुरुष परमानंद जी महाराज श्रीरामजन्मभूमि मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य हैं और अखंड आश्रम हरिद्वार के प्रमुख भी। वेदांत पर उनकी 150 से ज्यादा किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। स्वामी गोविंद देव गिरिजी महाराज ट्रस्ट के सदस्य के साथ-साथ कोषाध्यक्ष भी हैं। ऐसे में राममंदिर निर्माण के लिए चंदे का सारा हिसाब-किताब इन्हीं के पास है।

सर्वानुमति से निर्णय

यह सर्वविदित है कि अयोध्या में श्रीराम मंदिर का निर्माण सर्वानुमति यानी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद ही हो रहा है। यही कारण है कि आज पूरा भारत चाहे वह किसी भी जाति धर्म का क्यों न हो वह मंदिर निर्माण से उत्साहित है। आस्था से उत्पन्न भक्ति की शक्ति का प्रताप अखंड होता है। श्रीरामजन्मभूमि मंदिर निर्माण में अवरोध विगत पांच शताब्दियों से सनातन हिंदू समाज की आस्थावान सहिष्णुता की कठोर परीक्षातुल्य था। श्रीरामलला विराजमान की भव्य प्राण-प्रतिष्ठा भारत की सांस्कृतिक अंतरात्मा की समरस अभिव्यक्ति का प्रतिमान सिद्ध होगा। 5 अगस्त को अयोध्या में आयोजित भूमिपूजन और शिलान्यास में सहभागिता हेतु प्रभु श्रीराम के असंख्य अनन्य भक्तगण परम इच्छुक होंगे, किंतु कोरोना महामारी के कारण यह संभव नहीं हो पा रहा। इसे प्रभु इच्छा मानकर सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। प्रधानमंत्री सवा सौ करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं के प्रतिबिंब हैं। वह वहां रहेंगे। यह प्रत्येक भारतीय के लिए गौरव का क्षण होगा।

महामारी का असर

अयोध्या में भूमिपूजन को भव्य बनाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बीते सप्ताह उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अयोध्या जाकर तैयारियों का जायजा लिया था। कोरोना संक्रमण की वजह से सीमित संख्या में ही लोग इस आयोजन का हिस्सा बन सकेंगे। राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से भी अपील की गई है कि लोग भूमिपूजन के दिन को पर्व की तरह मनाएं और अपने-अपने घरों में रहकर ही दीप जलाएं। माना जाता है कि बाबर के दौर में अयोध्या में राम मंदिर को तुड़वाकर मस्जिद का निर्माण कराया गया। पिछली पांच सदी से यह विवाद था, जिसने देश की राजनीतिक दशा और दिशा को बदल दिया है। आजादी के बाद से अब तक इस विवाद ने देश की राजनीति को प्रभावित किया है। अयोध्या को लेकर देशभर में आंदोलन किए गए, कानूनी लड़ाई भी लड़ी गई और सुप्रीम कोर्ट के जरिए राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। अब जाकर मंदिर के भूमिपूजन की तारीख भी तय हो चुकी है।

मुहूर्त पर विवाद

श्रीराम मंदिर निर्माण के भूमिपूजन के लिए निर्धारित किए गए 5 अगस्त के मुहूर्त को लेकर विवाद किया जा रहा है। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती और कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह इस तिथि को अशुभ बता रहे हैं। वहीं मंदिर निर्माण से जुड़े लोगों का कहना है कि त्रेता युग में जब मुनि वशिष्ठ से राम के राज्याभिषेक का मुहूर्त पूछा



गया तो उन्होंने कहा कि शुभ और अशुभ राम से ही प्रकाशित होते हैं। राम का जिस दिन राज्याभिषेक होगा वह शुभ दिन बन जाएगा। भारतवर्ष में 5 अगस्त एक नया शुभ मुहूर्त बनने जा रहा है। इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में श्रीराम मंदिर के गर्भगृह का भूमिपूजन करेंगे। इसके साथ 5 अगस्त को सनातन धर्म की संस्कृति की समाज में पुनर्स्थापना का श्रीगणेश होगा। पुनर्स्थापना

इसलिए कि पिछली कई शताब्दियों में हम धीरे-धीरे अपनी ही संस्कृति से दूर होते गए हैं। भारतीय संस्कृति का मूल आधार है गृहस्थ व्यवस्था और राम इस व्यवस्था के चरम आदर्श हैं। राम के बिना भारतीय संस्कृति की कल्पना भी कठिन है। उनके चरित्र से समाज में मर्यादाएं बनीं, आदर्श स्थापित हुए। राम भारत की सांस्कृतिक विरासत के सर्वोच्च प्रतीक हैं।

दरअसल, राम और सनातन धर्म का विरोध धर्मनिरपेक्षता का सर्टिफिकेट बन गया। मंदिर का विरोध करने

आधुनिक संस्कृति का नया प्रतिमान बनकर उभरेगी अयोध्या

जन्मभूमि की मुक्ति के लिए बड़ा और कड़ा संघर्ष हुआ। न्याय और सत्य की संयुक्त विजय का यह उल्लास अतीत की कटु स्मृतियों को विस्मृत कर नए कथानक रचने और समाज में समरसता की सुधा सरिता के प्रवाह की नवप्रेरणा दे रहा है। सनातन संस्कृति के प्राण प्रभु श्रीराम की जन्मस्थली हमारे शास्त्रों में मोक्षदायिनी कही गई है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार इस पावन नगरी को पुनः इसी गौरव से आभूषित करने हेतु संकल्पबद्ध है। अयोध्या वैश्विक मानचित्र पर महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में अंकित हो और इस धर्मधरा में रामराज्य की संकल्पना मूर्त भाव से अवतरित हो, इसके लिए नियोजित नीति के साथ निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। वर्षों तक राजनीतिक उपेक्षा के भंवरजाल में उलझी रही अवधपुरी आध्यात्मिक और आधुनिक संस्कृति का नया प्रतिमान बनकर उभरेगी। यहां रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। विगत 30 वर्षों में विश्व ने अयोध्या की भव्य दीपावली देखी है। अब यहां धर्म और विकास के समन्वय से हर्ष की सरिता और समृद्धि की बयार बहेगी।

वाले भूल गए कि आजादी के आंदोलन का ध्येय ही राम राज्य की स्थापना था। राम राज्य की स्थापना के नारे पर आजादी की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी की सरकार ने अदालत में खड़े होकर कहा कि राम तो काल्पनिक हैं। यह वह मानसिकता है जो मूल रूप से जो कुछ भारतीय है उसके विरोध में खड़ी है। यही कारण है कि भारतीय धर्म और दर्शन के इतिहासकारों ने दाराशिकोह के मज्मउल बहरैन (समुद्र संगम) जैसे ग्रंथों की उपेक्षा की। इतना ही नहीं अलबरूनी, शेख मुबारक नागौरी, अब्दुरहीम खानखाना, मलिक मोहम्मद जायसी और नजीर अकबराबादी के लिखे को भी महत्व नहीं दिया। सनातन धर्म और संस्कृति पर लिखने वाले तमाम लोगों को हमेशा यह शिकायत रही। यह शिकायत सही भी है।

रामराज की जगी उम्मीद

साल 1949 से चल रहे मुकदमे और उससे पहले के संघर्ष को देखते हुए किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि अयोध्या में राम जन्म स्थान पर कभी राम मंदिर बन जाएगा। विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल ने 1986 में 30 अक्टूबर को राम मंदिर आंदोलन का शुभारंभ किया था। यह उन्हीं की तपस्या का फल है। भारतीय जनता पार्टी

अयोध्या आंदोलन की टाइमलाइन

1528-29 में मुगल राजा बाबर के सेनापति मीर बाकी ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई। 1853 में इस मुद्दे को लेकर पहली बार अयोध्या में दंगे हुए थे। 1885 में पहली बार जिला अदालत में यह विवादित मामला पहुंचा। 1959-61 में दोनों पक्षों ने विवादित स्थल के हक के लिए मुकदमा किया। 1984 में रामजन्मभूमि मुक्ति समिति का गठन किया गया। फरवरी 1986 में ताला खोलने का आदेश दिया गया और इसी साल बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनी। जून 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर का शिलान्यास किया। 25 सितंबर 1990 को आडवाणी की रथ यात्रा बिहार में रोकी गई, और उन्हें गिरफ्तार किया गया। 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में पहली बार कारसेवा हुई और गोलीकांड हुआ। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ढहा दी गई। 13 मार्च 2002 को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में यथास्थिति बरकरार रखने को कहा। अप्रैल 2002 में हाईकोर्ट में मालिकाना हक को लेकर सुनवाई शुरू की। मार्च-अगस्त 2003 में पुरातत्व विभाग ने विवादित स्थल के नीचे खुदाई की। 30 सितंबर 2010 को कोर्ट के फैसले के बाद विवादित स्थल को तीन हिस्सों में बांट दिया गया। 9 मई 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। नवंबर-दिसंबर 2017 में रिजवी बोले- विवादित स्थल पर राम मंदिर बने। 16 अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले में सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रखा। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के सितंबर, 2010 के फैसले के खिलाफ दायर अपीलों पर 6 अगस्त से रोजाना 40 दिन तक सुनवाई की। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर-बाबरी मस्जिद विवाद पर अपना फैसला सुनाया। इसके तहत कोर्ट ने 2.77 एकड़ विवादित जमीन को रामलला को देने का आदेश दिया। साथ ही मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को देने का फैसला सुनाया। कोर्ट ने सरकार को मंदिर निर्माण के लिए तीन माह के भीतर एक ट्रस्ट बनाने का आदेश भी दिया था। 5 फरवरी 2020 को राम मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में 15 सदस्यीय श्री रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का ऐलान किया। 19 फरवरी 2020 को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की पहली बैठक हुई। महंत नृत्यगोपाल दास को ट्रस्ट का अध्यक्ष चुना गया, जबकि नेता चंपत राय को महामंत्री बनाया गया। उसके बाद ट्रस्ट ने मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को भूमिपूजन की तिथि तय की।



और लालकृष्ण आडवाणी की भूमिका मई 1989 में हिमाचल के पालमपुर अधिवेशन में राम मंदिर पर पास प्रस्ताव से शुरू हुई। पिछले 30 साल में अयोध्या आंदोलन से भाजपा को राजनीतिक फायदा और नुकसान दोनों हुआ है। 6 दिसंबर, 1992 को विवादित ढांचा गिरने के बाद मंदिर मुद्दे पर भाजपा की विश्वसनीयता खत्म सी हो गई थी। उसके विरोधी तंज करते थे कि रामलला हम आएं, मंदिर वहीं बनाएं, लेकिन तारीख नहीं बताएं। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद मंदिर समर्थकों की उम्मीद बढ़ी, पर पहले कार्यकाल में कोई ठोस पहल न होने से थोड़ी निराशा हुई।

याद आ रहे तस्वी बलिदान

राम मंदिर निर्माण शुरू होने की घड़ी में विहिप नेता अशोक सिंहल और रामचंद्रदास परमहंस की कमी सबको खल रही है जिन्होंने दशकों तक राम जन्मभूमि आंदोलन का नेतृत्व किया, पर भव्य राम मंदिर का सपना आंखों में बसा, गोलोकधाम चले गए। ये दोनों महारथी राम मंदिर के लिए अपनी निष्ठा, नेतृत्व और तपस्या की वजह से इस आंदोलन का चेहरा बन चुके थे, पर उनके जीवनकाल में यह विवाद तमाम प्रयास के बावजूद नहीं निपट सका। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो दशकों से राम जन्मभूमि आंदोलन का रणनीतिकार रहा, आर्थिक सहयोग के बहाने 10 करोड़ परिवारों को भावनात्मक रूप से राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया से जोड़ने का अभियान चलाएगा। राम मंदिर निर्माण के लिए धन और सोना-चांदी दान करने के संकल्प देश-विदेश में व्यक्त होने लगे हैं। कोई मंदिर के लिए स्वर्ण-शिखर तो कोई इसके हिस्सों को सोने-चांदी से मंडित कराने का इच्छुक है। राम मंदिर निर्माण शुरू होने की घटना सनातन धर्म के वैभवशाली इतिहास का पूज्य-पावन पल है।

कैसा सुखद संयोग है कि रामलला के भव्य मंदिर का सदियों पुराना सपना साकार होने की घड़ी में उत्तर प्रदेश की सियासी कमान भगवाधारी संत योगी आदित्यनाथ के हाथ में है जो खुद राम मंदिर अनुष्ठान के साधक रहे हैं। वह जिस गोरक्ष पीठ के महंत हैं, वह शुरू से राम जन्मभूमि आंदोलन की ध्वजवाहक रही। तत्कालीन गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत अवैद्यनाथ राम जन्मभूमि न्यास के संस्थापक अध्यक्ष थे। ऐसे में राम जन्मभूमि से गोरक्षपीठ और योगी आदित्यनाथ का भावनात्मक रिश्ता समझा जा सकता है। मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद से ही योगी को अयोध्या और सरयू की फिक्क रही, पर राम मंदिर निर्माण का मार्ग निष्कंटक होने के बाद अयोध्या में विश्व का भव्यतम मंदिर बनाने का उनका सपना बार-बार व्यक्त हो रहा है। वह मौका मिलते ही अयोध्या पहुंचते हैं और तैयारी को परखते हैं। राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन करने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आ रहे हैं। यह सोने पर सुहागा जैसा संयोग है।

तीर्थस्थल से बढ़कर राम मंदिर

राम मंदिर महज एक मंदिर नहीं है। इसकी महत्ता एक तीर्थस्थल से बढ़कर है, क्योंकि यह राम के जन्मस्थल पर निर्मित हो रहा है। इसकी महत्ता उतनी ही है जितनी मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि मंदिर की। दुराग्रही वर्ग यह समझने को भी तैयार नहीं दिखता कि किसी देश की आत्मा उसकी अपनी संस्कृति में रची-बसी होती है और राम इस देश की संस्कृति में बहुत गहरे रचे-बसे हैं। यह किसी से छिपा नहीं कि आजादी के बाद शिक्षा व्यवस्था में वामपंथी हावी रहे और उन्होंने जानबूझकर इतिहास को एकपक्षीय ढंग से प्रस्तुत किया। गलत इतिहास के साथ ही उस विजातीय सेक्युलरिज्म ने भी ऐसे लोगों के चिंतन को दूषित किया जो तुष्टीकरण का पर्याय बनकर रह



राम मंदिर शिलान्यास पर कोरोना का साया

5 अगस्त को राम मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री मोदी के अयोध्या आगमन से पहले रामजन्मभूमि परिसर में कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है। रामलला के सहायक पुजारी के साथ 16 सुरक्षाकर्मी के कोरोनावायरस पॉजिटिव पाए जाने के बाद अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। आनन-फानन में परिसर में मौजूद सभी सुरक्षाकर्मियों के साथ व्यवस्था में लगे कर्मचारियों की कोरोना जांच की जा रही है। राम जन्मभूमि पर राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमिपूजन के बाद आधारशिला रखेंगे। इस दौरान राम मंदिर आंदोलन से जुड़े प्रमुख संत के साथ संघ और केन्द्रीय मंत्रिमंडल के लोग मौजूद होंगे। इस आयोजन को लेकर फोटो आईडी कार्ड युद्ध स्तर पर तैयार किए जा रहे हैं। जर्मन हैंगर टेंट के साथ ही परिसर में लगभग 500 कर्मचारी तैयारी के लिए लगाए गए हैं। लेकिन इस आयोजन के पहले रामजन्मभूमि परिसर में कोरोनावायरस मिलने से हड़कंप मच गया है। आनन-फानन में सभी अधिकारी परिसर में चल रही तैयारियों में लगे कर्मचारी व तैनात सुरक्षाकर्मियों की जांच शुरू कर दी है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमिपूजन 5 अगस्त को होना है।

गया। इस सेक्युलरिज्म में हिंदू मूल्यों और मान्यताओं के लिए कोई स्थान नहीं। इस सेक्युलरिज्म को सही समझने वाले इस मुगालते में हैं कि भारत इसलिए सेक्युलर है, क्योंकि संविधान में सेक्युलर शब्द का उल्लेख है। ध्यान रहे संविधान में सेक्युलर शब्द आपातकाल के दौरान जोड़ा गया। संविधान निर्माताओं ने इसकी आवश्यकता इसीलिए नहीं समझी थी, क्योंकि वे जानते थे कि भारत तो सदियों से पंथनिरपेक्षता का पोषक है और सर्वधर्म समभाव उसके स्वभाव में है। सेक्युलरिज्म के नाम पर अल्पसंख्यकों खासकर मुस्लिम समाज को या तो भयभीत करने का काम किया गया या फिर उसकी अनुचित मांगों को मानने का। शाहबानो मामला इसका सटीक उदाहरण है। सेक्युलरिज्म की विकृत राजनीति के कारण ही अयोध्या विवाद का समाधान होने में बहुत देरी हुई। कथित सेक्युलर-लिबरल लॉबी ने इसके लिए पूरी कोशिश की कि उच्चतम न्यायालय अयोध्या विवाद सुलझाने का काम न करे।

वर्तमान को अतीत से जोड़ने की पहल

कायदे से आजादी के बाद अयोध्या विवाद का समाधान उसी तरह होना चाहिए था जैसे सोमनाथ का किया गया, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और इसकी वजह रही नेहरू की वामपंथी

सोच। नेहरू सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के भी खिलाफ थे, लेकिन गृहमंत्री सरदार पटेल और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के आगे उनकी नहीं चली। कांग्रेस नेहरू की सोच को ही आगे बढ़ाती रही और मुसलमानों का जमकर तुष्टीकरण करती रही। इसी कारण वह समान नागरिक संहिता पर मौन रही या फिर उसका विरोध करती रही। राम मंदिर निर्माण के भूमिपूजन समारोह पर मीन-मेख निकाल रहे लोग यह सुनने-समझने को तैयार नहीं दिख रहे कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने क्या कहा? उन्होंने मंदिर निर्माण की प्रक्रिया में राष्ट्र को जोड़ने का उपक्रम बताने के साथ ही यह रेखांकित किया कि यह मंदिर वर्तमान को अतीत से और स्वयं को संस्कार से जोड़ने की पहल है।

विरासत संवारने का मौका

श्रीराम मंदिर निर्माण के साथ ही यह सवाल भी उठने लगे हैं कि अब देशभर में श्रीराम की सांस्कृतिक विरासत को तलाशने-तराशने का दायित्व तो निभाया ही जा सकता है। ग्रंथों, तथ्यों, मान्यताओं के आधार पर जो प्रमाण मिलता है, उस आधार पर दावे से कहा जा सकता है कि श्रीराम ने वनवास के चौदह में से साढ़े ग्यारह साल वर्तमान मध्य प्रदेश में व्यतीत किए थे। इतना लंबा समय यहां बिताने के प्रमाण

मिलने के बाद भी, मध्य प्रदेश ने कभी कोई एकल दावेदारी नहीं की और न ही प्रचार-प्रसार के जरिए उसे भुनाने का प्रयास किया। यह भी मानना ही होगा कि प्रदेश में राम वन गमन पथ, भाजपा-कांग्रेस के लिए बड़ा राजनीतिक मुद्दा होने के बावजूद, दोनों दलों ने बहुत धैर्य रखा।

केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से ही इस महत्वपूर्ण कार्य को, प्रामाणिकता के साथ आगे बढ़ाने का प्रयत्न भी किया। जबकि इस वजह से वे जनता को किए गए वादे को पूरा न करने के लिए, चुनाव के दौरान बारी-बारी से कठघरे में भी खड़े हो गए। राज्यों के समन्वय से सरकारी फाइलों में यह महत्वाकांक्षी परियोजना भले ही देरी से पूरी हो, लेकिन जनता-जनप्रतिनिधि इन्हें संरक्षित कर अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभा ही सकते हैं। पिछले 49 वर्षों से राम वन गमन पथ के प्रमाण जुटा रहे और रामायण सर्किट के लिए बनी राष्ट्रीय कमेटी के अध्यक्ष डॉ. राम अवतार अयोध्या से जनकपुर और रामेश्वरम तक कई बार भ्रमण कर चुके हैं। इस मार्ग पर उन्होंने 290 स्थान और स्मारक चिह्नित किए हैं। इसमें से मध्य प्रदेश 'विभाजित एवं अविभाजित' के पड़ाव को लेकर उनका अनुभव अन्य शोधार्थियों से बिल्कुल अलग है।

वे बताते हैं, 'संभवतः लोग मेरे मत से सहमत नहीं हों, लेकिन मेरी गणना के अनुसार श्रीराम मध्य प्रदेश दो बार आए थे। यही उनकी कर्मभूमि भी थी और प्रतिज्ञा भूमि भी। वाल्मीकि और गोस्वामी तुलसीदास, दोनों की रामायण में लिखी चौपाइयों से मिलान करें तो वनवास के दौरान चार साल का विस्तार से उल्लेख मिलता है। बाकी दस साल को वाल्मीकि ने चार श्लोक और तुलसीदास ने आधी चौपाई में बता दिया है। वनवास के दौरान सीता-राम जहां-जहां रुके, उनमें से कुछ स्थानों व आश्रमों में वे दोबारा लौटे थे। रामायण सर्किट में चिह्नित राम वन गमन पथ सतना, पन्ना, मैहर, कटनी, पिपरिया, होशंगाबाद, उमरिया, बांधवगढ़, शहडोल, अनूपपुर जिले से होकर गुजरता है। इस मार्ग के बीच में ही वे नासिक गए और वहां से लौटकर फिर शहडोल होते हुए कोरिया (वर्तमान में छत्तीसगढ़) में प्रवेश किया। चित्रकूट में फटिक शीला व गुप्त गोदावरी से जुड़े संस्मरण मिलते हैं। सतना में सरभंगा, अत्रीमुनि, अश्वमुनि, सुतीक्षण आश्रम, सीता रसोई और राम शैल पर्वत हैं। सिद्धा पहाड़ में राम ने ऋषियों की सुरक्षा के लिए प्रतिज्ञा ली थी। पन्ना के सारंगधर में वृहस्पति कुंड, बड़ा गांव में अग्निदेव आश्रम, सलेहा में अगस्त आश्रम, मैहर में राम जानकी मंदिर, कटनी में शिवमंदिर, पिपरिया में रामघाट, होशंगाबाद में श्रीराम मंदिर, पासी घाट, उमरिया में मार्कंडेय, आश्रम, बांधवगढ़ में राम मंदिर, उमरिया में दशरथ घाट होते छत्तीसगढ़ पहुंचने के प्रमाण हैं।

कम हो पढ़ाई का बोझ

हर पीढ़ी को सबसे अधिक चिंता भविष्य की पीढ़ी की ही होती है। सभी का प्रयास यही रहता है कि बच्चों और युवाओं को अपने से और आज से अधिक सुनहरा और परिपूर्ण जीवन मिले। मानव सभ्यता के विकास के लक्ष्य में यह बात समाहित है। मनुष्य के पास यह समझ भी विकसित हो चुकी है कि किसी एक समूह का भविष्य सुनहरा हो जाए और अन्य का न हो तो बात बनेगी नहीं। गांधी जी ने जॉन रस्किन की पुस्तक 'अन टू दिस लास्ट' पढ़कर अपनी आत्मकथा में जो सूत्र लिखे थे उनमें पहला यही था कि सबकी भलाई में ही प्रत्येक की भलाई संभव है। प्राचीन भारतीय दर्शन में भी निहित 'सर्व भूत हिते रत' और 'सर्वे भवतु सुखिनः' इसी को लगातार प्रकट करते रहे हैं। सभी को शिक्षा और समग्र विकास की अवधारणाएं सुनहरे भविष्य की वैश्विक संकल्पना को साकार करने के महत्वपूर्ण प्रयास हैं।

बहुधा दोहराया जाता है कि सुनहरे भविष्य का रास्ता तो स्कूलों के दरवाजों से निकलकर ही जाता है। किसी भी देश का भविष्य इस पर निर्भर करता है कि उसकी शिक्षा की गुणवत्ता किस स्तर की है। उसमें कौशलों का स्थान कितना महत्वपूर्ण है और व्यवस्था कितनी चाक-चौबंद है। इस समय हर तरफ और हर जगह शिक्षा की स्थिति एकाएक असमंजस की बन गई है।

कोरोना महामारी के कारण लगभग 200 करोड़ बच्चों की शिक्षा सारे विश्व में प्रभावित हुई है। आगे की स्थिति भी डांवाडोल है। स्कूल कब खुलेंगे, कोई नहीं कह सकता है। माता-पिता घबराहट में हैं। स्कूल खुलने पर भी बच्चों को वहां भेजने के लिए अभी तो तैयार नहीं दिखते हैं। ऑनलाइन शिक्षा की अपनी सीमाएं हैं, लेकिन स्कूल बंद रहते हुए हाथ पर हाथ धरकर बैठने से तो यह कहीं श्रेष्ठतर विकल्प है। वैसे सामान्य परिस्थितियों में भी ऑनलाइन शिक्षा ने अपना स्थान बना लिया है और इसका सकारात्मक उपयोग आगे भी होता रहेगा।

इस समय की सबसे बड़ी समस्या यह है कि 2020-21 सत्र के लिए बच्चे किस प्रकार तैयार किए जाएं? किस प्रकार उनके अंदर जो घबराहट, चिंता और अनिश्चितता छा गई है उससे उन्हें बाहर निकाला जाए। अनेक उपायों पर विचार हो रहा है। इस स्थिति का गहन मंथन कर सीबीएसई (केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड) ने पाठ्यक्रम के लगभग 30 प्रतिशत भाग को अध्यापन और मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। इस श्रेणी के पाठ पुस्तकों में तो बने रहेंगे, मगर उन पर परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। इस निर्णय से स्कूल के बच्चों में एक नए उत्साह और प्रसन्नता की लहर दौड़ गई है। पहली अपेक्षा तो यही है कि सभी राज्यों के स्कूल बोर्ड भी ऐसा ही करेंगे। देश के सबसे बड़े स्कूल बोर्ड उप्र बोर्ड



सिलेबस में हुई 30 फीसदी की कटौती

पूरे मध्यप्रदेश में बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग अब 9वीं से 12वीं कक्षाओं का सिलेबस कम करने जा रहा है। इससे पहले केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 9वीं से 12वीं कक्षा के सिलेबस में 30 फीसदी की कटौती की थी। सीबीएसई की तरह मध्यप्रदेश बोर्ड में भी 9वीं से 12वीं कक्षा तक के सिलेबस में 30 प्रतिशत तक की कटौती की जाएगी। बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण फिलहाल स्कूलों में नया सत्र शुरू नहीं हो पाया है और बच्चों की शुरुआती दौर की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इसी स्थिति को देखते हुए और छात्रों पर से पढ़ाई का बोझ कम करने के लिए बोर्ड ने ये फैसला किया है। वहीं मध्यप्रदेश में नया शिक्षा सत्र 1 अप्रैल से शुरू हो चुका है। इस समय ऑनलाइन क्लासेस के जरिए छात्र-छात्राओं की तैयारी करवाई जा रही है।

ने इसकी घोषणा भी कर दी है। बस्ते का बोझ पिछले तीस वर्षों से चर्चा का विषय रहा है। देश का ध्यान इस पर 1990-91 में गया था जब प्रसिद्ध लेखक आरके नारायण ने राज्यसभा में एक अत्यंत मार्मिक भाषण दिया था। उसके बाद व्यावहारिक सुझाव देने के लिए प्रसिद्ध वैज्ञानिक और शिक्षाविद् प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। उन्होंने बस्ते का बोझ घटाने के लिए कई सुझाव दिए थे, लेकिन तत्कालीन संग्राम सरकार ने उन पर गौर करना मुनासिब नहीं समझा।

इस समय देश में स्कूली शिक्षा में 2005 में बनाए गए पाठ्यक्रम और उसके अनुसार बनी पाठ्य पुस्तकें ही चल रही हैं। सामान्यतः शिक्षा के क्षेत्र में सजग और सतर्क देशों में पाठ्यक्रम और पुस्तकें हर पांच वर्ष में बदली जाती हैं। इस आवश्यकता को हर वह व्यक्ति समझ सकता है जो इस समय की परिवर्तन की तेजी से परिचित है। मई 2014 के बाद से शिक्षा से जुड़े सभी लोगों को अपेक्षा थी कि यह कार्य अपेक्षित प्राथमिकता के साथ किया जाएगा, परंतु यह

अभी तक हो नहीं सका है। जो पुस्तकें जाने-माने वामपंथी व्यक्तियों द्वारा बनवाई गई थीं, वे आज भी बदली नहीं गई हैं। यह आश्चर्य की स्थिति है, मगर इस अर्थ में सराहनीय भी है कि 2014 के बाद की केंद्र सरकार ने बदले की भावना से पुस्तकें और पाठ्यक्रम नहीं बदले। जैसा कि मई 2004 के बाद किया गया था। यहां पर एक घटना को याद करना अत्यंत रुचिकर होगा। 2000-01 में एनसीईआरटी के अनुरोध पर सीबीएसई ने कक्षा 8वीं की इतिहास की पुस्तक से एक अंश हटाया था जिसमें लिखा था कि दिल्ली, आगरा और मथुरा के आसपास एक नई जाट शक्ति का उदय हुआ। उन्होंने भरतपुर में अपनी रियासत स्थापित की। वहां से उन्होंने आसपास के इलाकों में लूटपाट की और दिल्ली दरबार की साजिशों में भाग लिया। यह इतिहास लगभग 35 साल से पढ़ाया जा रहा था। अनेक इतिहासकारों और संस्थाओं ने लगातार सुझाव दिए कि इसे तथ्यपरक बनाया जाए, मगर उस पर ध्यान नहीं दिया गया।

● धर्मेन्द्र सिंह कथूरिया

6

भारतीय लोकतंत्र के भीड़ भरे बाजार में बेशुमार पार्टियां हैं।

लेकिन भाजपा अकेली राष्ट्रीय पार्टी है जिसे विचारधारा और पॉलिटिक्स के आधार पर अलग से पहचाना जा सकता है। उसके पास कुछ ऐसा है जो बाकी पार्टियों के पास नहीं है। मार्केटिंग की भाषा में भाजपा के पास यूएसपी यानी यूनिक सेलिंग पॉइंट या पॉइंट्स हैं। इस यूएसपी के सहारे भाजपा ने भारतीय राजनीति में तो जगह बना ली है जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि हम भाजपा सिस्टम यानी भाजपा के वर्चस्व वाली राजनीति के दौर में प्रवेश कर चुके हैं या करने वाले हैं।

यह दौर लंबा चल सकता है।

9



दीदी का दम

कई बड़े और छोटे राज्यों को भाजपा ने फतह कर लिया है, लेकिन पश्चिम बंगाल को फतह करने की उसकी मंशा अभी तक अधूरी है। पार्टी को उम्मीद है कि 2021 के विधानसभा चुनाव में वह पश्चिम बंगाल में भगवा झंडा फहरा सकती है। लेकिन दीदी यानी ममता बनर्जी को मात देना इतना आसान नहीं है। इसलिए पार्टी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का मानना है कि पार्टी इस बार पश्चिम बंगाल की सत्ता हासिल करके ही दम लेगी। इसके लिए पार्टी ने बहुत आक्रामक रणनीति तैयार की है। लेकिन दीदी का दम भी कम नहीं है।

ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में डिजिटल रैली के साथ चुनावी मुहिम की शुरुआत कर दी है। 21 जुलाई को ममता बनर्जी हर साल शहीद दिवस रैली करती हैं और अपना एजेंडा बताने के साथ-साथ राजनीतिक विरोधियों पर जोरदार हमला भी बोलती हैं। वैसे भाजपा की तरफ से डिजिटल रैली तो अमित शाह ने 9 जून को ही कर डाली थी। हमेशा की तरह ममता बनर्जी की डिजिटल रैली में भी निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ही रहे, लेकिन हड़बड़ी में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने एक बड़ी गलती कर दी है। 2021 के विधानसभा चुनाव का एक बड़ा मुद्दा मोदी-शाह के सामने पहले ही खोल कर गलती से मिस्टेक भी कर डाली है।

ममता बनर्जी हर साल 21 जुलाई को पश्चिम बंगाल के लोगों के बीच होती हैं और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ इकट्ठा होकर शहीद दिवस मनाती हैं। 1993 में

ममता बनर्जी तब की वाम मोर्चे की सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही थीं और उसी दौरान हुई पुलिस फायरिंग में 13 लोग मारे गए। तभी से हर साल तृणमूल कांग्रेस की तरफ से शहीद दिवस रैली आयोजित की जाती रही है। हर रैली में ममता बनर्जी का तेवर तो तकरीबन एक जैसा ही रहता है, लेकिन चुनावी साल में ये ज्यादा आक्रामक हो जाता है। 2019 के आम चुनाव के चलते तो ममता का एक जैसा अंदाज लगातार दो बार देखने को मिला था। पहले जुलाई, 2018 में जब वो मन ही मन प्रधानमंत्री पद की भी दावेदार बनी हुई थीं और फिर जुलाई, 2019 में जब भाजपा ममता के बंगाल में भी सेंध लगा चुकी थी।

चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर काफी पहले से ही ममता बनर्जी के कैंपेन की निगरानी कर रहे हैं। बीच-बीच में वो अपने दूसरे काम भी करते रहते हैं जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का कैंपेन और अपने लिए 'बात बिहार की' कैंपेन। काफी दिनों से ममता बनर्जी के हाव-भाव और राजनीतिक तौर-तरीके में प्रशांत किशोर की गाइडलाइंस का काफी प्रभाव भी दर्ज किया गया है। मगर, ममता बनर्जी ने मोदी-शाह को लेकर अब जो बात कही है, उससे तो यही लगता है कि प्रशांत किशोर, ममता बनर्जी को उसी तरीके से चुनाव लड़ा रहे हैं जैसे 2015 में नीतीश कुमार के चुनाव अभियान में देखने को मिला।

उधर, भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई ने 2021 के विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है, जहां पिछले

27 फीसदी मुस्लिम मतदाताओं का दम

बंगाल की माटी पर एकाएक उदय हुई भाजपा ने ममता के वजूद को संकट में डाल दिया है। बंगाल में करीब 27 फीसदी मुस्लिम मतदाता हैं। इनमें 90 फीसदी तृणमूल के खाते में जाते हैं। इसे तृणमूल का पुख्ता वोटबैंक मानते हुए ममता ने मोदी व भाजपा विरोधी छवि स्थापित करने में अपनी ताकत झोंक दी है। इसमें मुस्लिमों को भाजपा का डर दिखाने का संदेश भी छिपा था। किंतु इस क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया हिंदुओं में स्वस्फूर्त ध्रुवीकरण के रूप में दिखाई देने लगी। बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैटिए भाजपा को वजूद के लिए खतरा मानकर देख रहे हैं। नतीजतन बंगाल के चुनाव में हिंसा का उबाल आया हुआ है। इस कारण बंगाल में जो हिंदी भाषी समाज हैं, वह भी भाजपा की तरफ झुका दिखाई दे रहा है। हैरानी इस बात पर भी है कि जिस ममता ने 'मां माटी और मानुष' एवं 'परिवर्तन' का नारा देकर वामपंथियों के कुशासन और अराजकता को चुनौती दी थी, वही ममता इसी ढंग की भाजपा के लोकतांत्रिक प्रतिरोध से बौखला गई हैं। उनके बौखलाने का एक कारण यह भी है कि 2011-2016 में उनके सत्ता परिवर्तन के नारे के साथ जो वामपंथी और कांग्रेसी कार्यकर्ता आ खड़े हुए थे, वे भविष्य की राजनीतिक दिशा भांपकर भाजपा का रुख कर रहे हैं।

कुछ दिन से ये काफी पैठ बना रही है और बंगाली आइकन के तौर पर डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी की ओर देख रही है। मुखर्जी जो किसी समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में शामिल थे, बाद में अलग हो गए और भारतीय जनसंघ का गठन किया, जो भाजपा की पूर्ववर्ती थी, लेकिन बंगाल में वो गुमनामी के अंधेरे में चले गए। वो राज्य जो उनके पिता सर आशुतोष मुखर्जी को 'बांगलार बाघ' (बंगाल टाइगर) के तौर पर याद करता है, जो अंग्रेजी शासन के खिलाफ खड़े हुए थे।

प्रदेश नेताओं का कहना है कि मुखर्जी को बंगाल के महान नेता के तौर पर महिमा मंडित करने का विचार गृहमंत्री अमित शाह के दिमाग की उपज है। नाम न बताने की शर्त पर एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने इस बात की तरफ इशारा किया कि शाह और मोदी की भारत की परिकल्पना, मुखर्जी की राष्ट्र की अवधारणा से मेल खाती है। 'यही वजह है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शासन में, मुखर्जी और उनके विचारों को उतनी शोहरत नहीं मिली, जितनी अब मिल रही है।' अपने पूरे जीवन में मुखर्जी, जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे के खिलाफ रहे।

वरिष्ठ भाजपा नेता और मेघालय के राज्यपाल तथागत रॉय, जो मुखर्जी के जीवनीकार भी हैं, ने कहा, '1952 तक देश में, जम्मू-कश्मीर जिसका एक अभिन्न अंग था, दो प्रधानमंत्री थे, नेहरू और (शेख) अब्दुल्लाह, दो राष्ट्राध्यक्ष थे, भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति और जम्मू-कश्मीर के सदर-ए-रियासत, दो संविधान थे, जिनमें से एक अभी अधूरा था और दो ध्वज थे।' उन्होंने आगे कहा, 'क्या दुनिया के किसी देश ने जो अपने किसी हिस्से को राष्ट्र का अभिन्न अंग समझता हो, खुद को इतनी अपमानजनक स्थिति में रखा है? यही वो अपमान था जिसके खिलाफ दहाड़ते हुए डॉ. मुखर्जी ने कहा था 'एक देश में दो विधान, दो निशान, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे।'

भाजपा अब बंगाल में मुखर्जी को 'धरती पुत्र' के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाह रही है जिन्होंने बटवारे के समय पश्चिम बंगाल, खासकर कोलकाता को पश्चिम बंगाल के साथ रखने के लिए आंदोलन की अगुवाई की। भाजपा की बुद्धिजीवी विंग, जिसमें अनिबान गांगुली और राज्यसभा सांसद स्वपनदास गुप्ता शामिल हैं, श्यामाप्रसाद मुखर्जी, बटवारे और नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के कथानक को आगे

बढ़ाने के लिए, अलग-अलग समूहों तक पहुंच रही है। भाजपा सीएए को मुखर्जी की एक और 'इच्छा' बता रही है, ये कहकर कि इससे बटवारे के शिकार हिंदू बंगाली पीड़ितों को नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि इस रणनीति की सफलता काफी कुछ इस पर निर्भर करेगी कि 'औसत बंगाली भद्रलोक' इस कथानक से कितने संतुष्ट होते हैं। कोलकाता यूनिवर्सिटी में राजनीति विज्ञान के



भाजपा ने बाकी दलों के कार्यक्रमों को अपनाया

भाजपा जीतती और हारती रही है लेकिन उसने अपने मुद्दे और पहचान को कभी नहीं छोड़ा। ये बात भाजपा की सबसे बड़ी ताकत बन गई। इस वजह से उसका कोर वोट उसके साथ लगातार जुड़ा रहा क्योंकि भाजपा ने उन्हें कभी निराश नहीं किया। विचारधारा और सरकार के बीच चुनने का मौका आने पर उसने सरकार को छोड़ने और विचार को पकड़ने का फैसला लिया। भाजपा विकास, प्रशासनिक कार्य और शिक्षा, स्वास्थ्य और नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के मामले में बाकी दलों की तरह ही है। जैसे बाकी दल देश और प्रदेशों का 'विकास' कर रहे हैं, वैसे ही भाजपा भी 'विकास' कर रही है। बाकी दलों की तरह भाजपा भी भ्रष्टाचार से लड़ती रहती है! भाजपा उतनी ही भ्रष्ट और नाकारा है, जितनी बाकी पार्टियां हैं। मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में मानव विकास के मामले में भाजपा कांग्रेस से भी लवर साबित हुई है। बिहार में भाजपा लंबे समय से सत्ता में है लेकिन उसने कोई अलग पहचान नहीं छोड़ी है। इन कारणों से बाकी पार्टियों के वोटर पार्टी बदल लेते हैं लेकिन भाजपा का वोटर भाजपा के साथ टिका रहता है।

प्रोफेसर समीर दास ने कहा, 'भाजपा ने एक ऐसी शिखरयत को चुना है जिसे बंगाल लगभग भूल चुका है। अब देखना ये है कि एक औसत बंगाली भद्रलोक, उनके और उनकी विचारधारा के साथ कैसे जुड़ेगा।' उन्होंने कहा कि राज्य में युवा और अधेड़ लोग, मुखर्जी के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानते। 'डॉ. मुखर्जी को लेकर ये अचानक उत्साह, कम्युनिस्टों के उस सोचे-समझे एक्शन का दूसरा चरम रूप है, जिसमें उन्होंने मुखर्जी को गुमनामी में धकेल दिया था'।

उन्होंने आगे कहा, 'इस तरह के स्विच-ऑन, स्विच-ऑफ फेज, उनके चरित्र या अखंड भारत के उनके साहसी और अनोखे विचारों को, कभी सामने नहीं ला सके। वो हमेशा से इन दो चरम स्थितियों के बीच झूलते रहे हैं।' उन्होंने आगे कहा, '2012 में जेएनयू में अपने कार्यकाल के दौरान, वहां मैं उनके बारे में चर्चाएं सुनता और देखता था। लेकिन उनका गृह राज्य उनके विचारों से ज्यादातर अज्ञान ही रहा। कुछ समय से भाजपा उन्हें एक बंगाल

आइकन के रूप में प्रोजेक्ट कर रही है। लेकिन मुझे लगता है कि ये अधूरे मन से हो रहा है और राजनीति से प्रेरित है। संघीय भारत और देश की सीमाओं और राज्यों के बारे में उनके विचारों का कोई विश्लेषण नहीं हो रहा है। भारतीय राजनीति में वो पहले भी अकेले थे, अभी भी अकेले हैं।'

सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस को लगता है कि मुखर्जी को एक बंगाली आइकन के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया जा सकता। टीएमसी के वरिष्ठ सांसद प्रोफेसर सौगत रॉय ने कहा, 'भाजपा के पास कोई बंगाली आइकन नहीं है। पहले उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय को लाने की कोशिश की लेकिन यहां उनके बारे में कोई कुछ नहीं जानता।' उन्होंने आगे कहा, 'किसी बंगाली चेहरे की जरूरत महसूस करते हुए उन्होंने श्यामाप्रसाद का नाम लेना शुरू कर दिया। लेकिन उनके बारे में जरा सी रिसर्च से पता चल जाएगा कि उनके जीवनकाल में बंगालियों ने उन्हें कभी हीरो या आइकन नहीं समझा। जितने भी बंगाली देशभक्त आजादी की लड़ाई में शरीक थे, वो सब जेल गए, सिवाय उनके। केवल जनसंघ के सदस्यों और बाद में कम्युनिस्टों का आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं रहा।' अब देखना यह है कि पश्चिम बंगाल में चुनावी घोषणा तक क्या-क्या तैयारियां होती हैं।

● इन्द्र कुमार



देश में लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों में युवा पीढ़ी को बड़ी-बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। लेकिन कांग्रेस में युवाओं को हाशिए पर रखा जा रहा है। इसका परिणाम यह हुआ है कि अधीर युवा पीढ़ी बगावत पर उतर आई है। अभी तक तीन युवा नेता कांग्रेस को गुड बाय कर चुके हैं।



अधीर युवा पीढ़ी

राजस्थान में पायलट बनाम गहलोट ड्रामे ने कुछ ऐसी परतें उघाड़ दी हैं जिन्हें लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर हमेशा छिपाने का आरोप लगाया है, खासकर राजस्थान और मध्य प्रदेश में अपने मुख्यमंत्री चुनने के मामले में। भाजपा कांग्रेस पर 'दरबारी' होने और युवा नेताओं को बर्खास्त या दरकिनार करने के लिए पुराने घाघ नेताओं का पक्ष लेने का आरोप लगाती है। यहां तक कहा जाता है कि कांग्रेस युवा नेताओं को बढ़ावा नहीं देती है क्योंकि वह नहीं चाहती कि कोई भी राहुल गांधी के रास्ते में आड़े आए। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया, अदिति सिंह और अब सचिन पायलट से जुड़ी हालिया घटनाएं यह स्पष्ट करती हैं कि यह कांग्रेस की अधीर युवा पीढ़ी है जो पार्टी की **रैंक व्यवस्था** तोड़ने के लिए खुलकर सामने आ रही है। उनके ऐसा करने की वजहें अलग-अलग हो सकती हैं— लालच, सत्ता की आकांक्षा, निराशा, छिछली विचारधारा, आत्म-सुरक्षा की भावना या फिर एक पुरानी पार्टी के अंदर संगठनात्मक ढांचे से जुड़े असल मुद्दे। लेकिन अपनी बदली सोच के खुले प्रदर्शन में वह लगभग एक ही लय में दिखते हैं।

कांग्रेस के पुराने नेता इस पर जोर देते हैं कि जैसा अशोक गहलोट ने हाल में एक साक्षात्कार में कहा, पार्टी के युवा नेताओं में धैर्य की कमी है। गहलोट ने तर्क दिया कि उन्होंने 1984 में कांग्रेस की राजस्थान इकाई की कमान संभालने के बाद मुख्यमंत्री बनने के लिए 14 साल तक इंतजार किया और सचिन पायलट को भी इसी तरह धैर्य दिखाना चाहिए था क्योंकि राजनीति इसी तरह चलती है। लेकिन क्या राजनीति इसी तरह काम करती है? और क्या भाजपा का कांग्रेस पर युवा नेताओं को दरकिनार करने का आरोप लगाना न्यायसंगत है?

राजनीति में 49 वर्ष के सिंधिया, 42 के पायलट और 50 के राहुल गांधी को युवा माना

जाता है। इसे ही ध्यान में रखकर देखते हैं कि भाजपा 55 वर्ष से कम आयु के अपने युवा नेताओं के साथ कैसा व्यवहार करती है। भाजपा ने उस समय 45 वर्ष की उम्र वाले गोरखनाथ मठ के महंत योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में चुना, जबकि 2017 विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिली प्रचंड जीत की वजह थे इसके प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा। लेकिन सचिन पायलट के विपरीत, जो वास्तव में कभी उपमुख्यमंत्री की भूमिका में स्थिर नहीं हो पाए और हमेशा इसका इंतजार करते रहे कि कांग्रेस गहलोट द्वारा संभाली जा रही कुर्सी पर उन्हें बैठा दे, मौर्य और शर्मा ने कभी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का डिप्टी होने पर कभी नाखुशी नहीं जताई। शायद, पार्टी संगठन पर अमित शाह की मजबूत पकड़ भाजपा में पदानुक्रम व्यवस्थित बनाए रखती है। लेकिन आदित्यनाथ का चुना जाना जहां एक सोची-समझी रणनीति थी, वहीं पायलट की नियुक्ति कांग्रेस के लिए एक बाधक थी। आदित्यनाथ न केवल एक लोकप्रिय हस्ती हैं और युवाओं के एक वर्ग पर खासा प्रभाव रखते हैं जो उनकी हिंदू युवा वाहिनी के सदस्य हैं, बल्कि भाजपा की हिंदुत्ववादी भाषणशैली पर भी खरे उतरते हैं। लेकिन आदित्यनाथ को चुना जाना एक जुआ भी था जिसे नरेंद्र मोदी-अमित शाह ने राष्ट्रीय

स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के कहने पर यह जानते हुए भी खेला था कि वह कई मौकों पर भाजपा के खिलाफ विद्रोह कर चुके थे। फिर भी, मोदी-शाह ने उन्हें यूं ही नहीं छोड़ दिया और भाजपा में उनकी स्थिति को और मजबूत किया। कुछ लोगों का तो यहां तक कहना है कि वह 2024 में मोदी के उत्तराधिकारी हो सकते हैं।

असम में, हिमंता बिस्वा सरमा की कहानी एक ऐसा उदाहरण है जो युवा नेताओं को लेकर भाजपा और कांग्रेस के नजरिए में जमीन-आसमान के अंतर को पूरी तरह स्पष्ट करती है। पत्रकार राजदीप सरदेसाई की 2019 में आई किताब: हाउ मोदी वॉन इंडिया के मुताबिक, पूर्व कांग्रेस नेता सरमा ने एक बार सोनिया गांधी से कहा था, 'अगर आप असम में अगला चुनाव जीतना चाहती हैं तो आपको कांग्रेस का नेतृत्व कर रही पीढ़ी में प्रभावी बदलाव करना होगा।' 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के बुरी तरह हारने के मद्देनजर दी गई सरमा की यह सलाह भी कोई बदलाव नहीं ला सकी।

कांग्रेस ने जहां 80 वर्षीय तरुण गोगोई के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का फैसला किया, वहीं भाजपा ने एक बार सरमा के अपनी नाव में सवार होने के बाद राज्य में पार्टी की बागडोर उन्हीं के हाथों सौंप दी। वह 2016 में असम में भाजपा को पहली बार सत्ता में लाने में मददगार साबित

कांग्रेस नेतृत्व ने युवा चेहरों को आजमाने में चूक क्यों की ?

युवा नेताओं की पुराने नेताओं से रार और एक बार फिर राहुल गांधी को अध्यक्ष के तौर पर आजमाने की कसरत के बीच यह सवाल भी मौजू है कि कांग्रेस आलाकमान बिगड़ते राजनीतिक घटनाक्रमों को संभालने में नाकाम क्यों हो रहा है? इस सवाल का जवाब कांग्रेस में होती टूट के लिए भाजपा को जिम्मेदार बताने से नहीं मिलेगा, यह कांग्रेस नेतृत्व की अपनी जिम्मेदारी है। जिन दो राज्यों में कांग्रेस में टूट का संकट दिखा है, उनको लेकर यह सवाल भी उठा कि कांग्रेस नेतृत्व ने युवा चेहरों को आजमाने में चूक क्यों की? इसको लेकर राजनीतिक विश्लेषकों के बीच कई मत हैं। एक मत यह भी है कि 'नेहरू-इंदिरा' परिवार और उसके इर्द-गिर्द रहने वाले पुराने नेता युवा चेहरों को राहुल गांधी के लिए चुनौती के रूप में देखते हैं। इस तर्क में दम इसलिए भी है, क्योंकि अनेक अवसर मिलने के बावजूद राहुल गांधी एक सफल नेतृत्वकर्ता के रूप में खुद को प्रमाणिक तौर पर खरा साबित नहीं कर पाए हैं।

हुए और बदले में उन्हें वित्त, स्वास्थ्य, पीडब्ल्यूडी से लेकर शिक्षा तक कई अहम विभागों का प्रभार सौंपा गया। कांग्रेस चाहे तो वह भी अपने युवा नेताओं के साथ ऐसा तरीका अपना सकती है- इसलिए नहीं कि भाजपा ऐसा करती है, बल्कि इसलिए कि ऐसा करना तर्कसंगत है।

आदित्यनाथ और सरमा अपवाद भर नहीं हैं। भाजपा ने अपने युवा नेताओं को नेतृत्व की अहम जिम्मेदारियाँ सौंपकर सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया है और अब तीसरी पीढ़ी के नेताओं की पौध तैयार कर रही है। हमेशा की तरह आरएसएस इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सहयोग की स्थापित व्यवस्था के तहत आरएसएस काबिल युवा नेताओं को ढूंढता है और फिर उन्हें भाजपा में भविष्य की भूमिकाओं के लिहाज से तराशता है जैसा इसने मनोहर पर्रिकर के साथ किया। काफी पहले से ऐसे नेताओं को भाजपा में विशेष जगह मिलती रही है जिसमें शामिल हैं सियासी परिवार से जुड़े अनुराग ठाकुर, जिन्हें चुनावों में और पार्टी की हिंदुत्ववादी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और आरएसएस से निकले एक अन्य कार्यकर्ता तेजस्वी सूर्या, दक्षिण में भाजपा के युवा नेतृत्व का चेहरा हैं जो 2019 के चुनाव में पार्टी के सबसे युवा सांसद बने।

आरएसएस की पृष्ठभूमि वाले अधिकांश भाजपा नेता आज पार्टी में महत्वपूर्ण पदों पर हैं- राम माधव कश्मीर में भाजपा मामलों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और पी मुरलीधर राव, जो कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनवाने में केंद्रीय भूमिका में थे, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। छत्तीसगढ़ में सरोज पांडे और मध्य प्रदेश के कैलाश विजयवर्गीय अपने-अपने राज्यों में अहम जिम्मेदारी संभालते हैं।

पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को 2018 के ओडिशा विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश करके पार्टी ने यह बता दिया था कि उनके लिए क्या संभावनाएं हैं। झारखंड में भाजपा ने अर्जुन मुंडा को आगे बढ़ाया जो वर्तमान में जनजातीय



मामलों के मंत्री हैं। और इससे आगे हैं महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस और उत्तर प्रदेश में स्मृति ईरानी, जिन्होंने 2002 के दंगों के बाद गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी के इस्तीफे की मांग को लेकर आमरण अनशन की घोषणा तक कर दी थी। फिर भी, वह सब भुलाकर 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्हें सत्ता के गलियारों में आगे लाया गया। आखिरकार 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ खड़ा किया गया, जहां उन्होंने जीत भी हासिल की। क्या कांग्रेस नेतृत्व कभी इतने खुले तौर पर विरोध जताने वाले को इतनी आसानी से बढ़ावा देगा? जाहिर तौर पर नहीं।

कुछ सच ऐसे होते हैं जिनके घटित होने के बाद भी उन पर यकीन नहीं होता। एक साल पहले तक देश का धुरंधर से धुरंधर राजनीतिक विश्लेषक पूरे विश्वास से यह नहीं कह सकता था कि आने वाले दिनों में ज्योतिरादित्य सिंधिया और फिर सचिन पायलट कांग्रेस को छोड़ सकते हैं। कांग्रेस ने अगर 2019 के चुनावों के पहले भाजपा को कभी जरा सा सशंकित किया या चौंकाया था तो सिर्फ मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे बड़े राज्यों में चुनावों के बाद ही चौंकाया था, जब इन दोनों राज्यों से भाजपा की सरकार

चली गई थी। जब राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की वापसी हो गई थी और गुजरात में भी उसने नैतिक विजय हासिल कर ली थी, उसके बाद कांग्रेस 2019 के चुनाव के लिए अगर बहुत जोरदार नहीं तो सम्मान योग्य प्रतिद्वंद्वी बन गई थी। लेकिन चुनावों के बाद अगर कांग्रेस की तकनीकी दुर्दशा के साथ-साथ उसकी मनोवैज्ञानिक दुर्बलता भी दयनीयता के साथ बेनकाब हुई है, तो इसका संबंध लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की पराजय से ज्यादा मध्य प्रदेश और राजस्थान में विधानसभा चुनावों को जीतने के बाद पार्टी आलाकमान के नेतृत्व की बागडोर को सौंपने को लेकर गलत निर्णय था।

इसमें कोई दो राय नहीं है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ और राजस्थान में अशोक गहलोत ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट से कहीं ज्यादा अनुभवी राजनेता हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में अगर कांग्रेस सत्ता में आई, तो इसके पीछे अनुभवी नेताओं की राजनीति या राजनीतिक होमवर्क नहीं था, बल्कि इसमें मुख्य योगदान इन दोनों प्रदेशों में इन्हीं युवा नेताओं का था, जिन्हें आज कांग्रेस खो चुकी है।

● दिल्ली से रेणु आगाल

कांग्रेस की 1970 के दशक वाली राजनीति

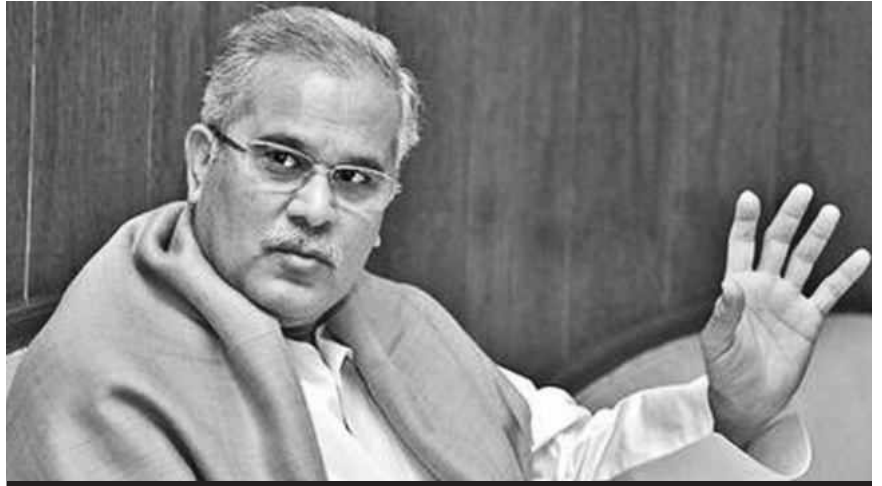
कांग्रेस ने सचिन पायलट के सिर्फ यह कहने भर पर उनसे सभी पद छीन लिए कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो वह पार्टी छोड़ देंगे। टेप लीक हो रहे हैं और एक-दूसरे पर कीचड़ उछालना जारी है। गहलोत खेमा और कांग्रेस की पूरी आईटी सेल यह साबित करने में जुटी है कि पायलट एक 'मौकापरस्त' हैं जिनकी अपनी विचारधारा कभी ठीक नहीं रही। लेकिन कांग्रेस को 1970 के दशक की भारतीय राजनीति से इतर देखने की जरूरत है। हम एक लंबा सफर तय कर चुके हैं और खेल एकदम बदल गया है। मोदी और शाह के जमाने में हार-जीत नितांत निजी है। भाजपा की सत्ता की लालसा, किसी भी तरह जीत हासिल करना, खतरनाक है लेकिन प्रेरणादायी भी है। यही वजह है कि इसके आलोचक भी राजस्थान संकट के मामले में खुद को बेवकूफ बनाने के लिए कांग्रेस की आलोचना करने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। पायलट के जाने से कांग्रेस में प्रतिभा की कमी और गहरा जाएगा। कई लोग सोचते हैं कि कांग्रेस के लिए सबसे अच्छी बात यही हो सकती है कि छिछली विचारधारा वाले नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। लेकिन यह तो समय ही बताएगा कि करिश्मा विकसित नहीं किया जा सकता, कुछ लोग इसके साथ ही पैदा होते हैं। कांग्रेस अंततः यह तभी समझ पाएगी जब उसे अहसास होगा कि उसके पास नई पीढ़ी के ऐसे नेताओं की कमी है जिनके साथ भारत के लोग खुद को जोड़ सकें।

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के देहांत के बाद खाली हुई मरवाही विधानसभा सीट का उपचुनाव मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए एक बड़ी चुनौती बनने जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इसकी गंभीरता को देखते हुए मरवाही उपचुनाव को 'टारगेट 70' का नाम दे दिया है। हालांकि, यहां यह देखना दिलचस्प होगा कि पिछले पांच चुनावों यानी 25 वर्षों से जोगी परिवार की यह सीट किस करवट बैठती है तब जब मरवाही उपचुनाव में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट अजित जोगी के बेटे अमित जोगी ही रहेंगे।

राजनीति के जानकारों का यह भी कहना है कि मरवाही विधानसभा सीट पिछले 5 चुनावों में जोगी परिवार से बाहर नहीं गई, लेकिन इस उपचुनाव को और खासकर इस सीट को बघेल की साख से जोड़कर देखा जा रहा है। बघेल अपने व्यक्तिगत राजनीतिक कद को बढ़ाने और विरोधियों को शांत करने के लिए एक बड़े अवसर के रूप में देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता भी कह रहे हैं कि मरवाही उपचुनाव बघेल के लिए एक तीर से कई शिकार करने वाला साबित होगा लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री का यह गढ़ फतह करना आसान नहीं है।

कांग्रेसी नेताओं के अनुसार भूपेश बघेल के नेतृत्व में यदि कांग्रेस मरवाही उपचुनाव जीत लेती है तो उनका राजनीतिक कद राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बढ़ेगा बल्कि कांग्रेस हाईकमान के सामने उनकी 'बारगेनिंग पावर' काफी बढ़ जाएगी। इसका सीधा अर्थ होगा कि आने वाले तीन साल उनका शासन बेरोकटोक चलता रहेगा। पार्टी के अंदर उनके खिलाफ उठने वाली आवाज हमेशा के लिए शांत हो जाएगी। बघेल के लिए अजीत जोगी हमेशा ही एक राजनीतिक मोहरा रहे हैं। कांग्रेस में बघेल के समर्थक भी यह मानते हैं कि उनके द्वारा अजीत जोगी का लगातार विरोध करना और जोगी का कांग्रेस से निष्कासन के बाद 2018 विधानसभा चुनाव में पार्टी की भारी जीत ने उनके मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को मजबूत बना दिया था।

कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर कहा- 'भूपेश बघेल हमेशा से यह कहते हैं कि जोगी और भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की सांठगांठ के कारण कांग्रेस 15 साल तक सत्ता से बाहर रही।' हालांकि बघेल का आरोप कांग्रेस की 2018 के विधानसभा चुनाव में हुई जीत से काफी हद तक साबित हो गया। करीब 15 साल तक विपक्ष में रहने के बाद पार्टी ने पहली बार चुनाव जोगी के बिना लड़ी और 90 सीटों वाली विधानसभा में 67 सीट के साथ भारी बहुमत से जीत हासिल की उसके बाद चित्रकूट और जगदलपुर उपचुनाव में भी कांग्रेस ने ही बाजी मारी और यह 67 का



कांग्रेस का 'टारगेट 70'

भाजपा भी कांग्रेस नहीं बघेल को हराना चाहती है

राजनीतिक विश्लेषक और भाजपा के नेताओं का कहना है कि मरवाही उपचुनाव में पार्टी अपने उम्मीदवार की जीत से ज्यादा फोकस सत्तारूढ़ दल की हार पर करेगी। इसके लिए भाजपा को यदि छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के तय उम्मीदवार अमित जोगी के खिलाफ डमी उम्मीदवार भी देना पड़ा तो पार्टी वैसा ही करेगी। शर्मा कहते हैं, 'भाजपा की स्ट्रैटजी का यह एक पहलू हो सकता है लेकिन यदि उसे लगा कि कांग्रेस और जोगी के बीच टक्कर बराबर की हो सकती है तो पार्टी यह उपचुनाव जीतने के लिए लड़ेगी। फिर भी प्रदेश भाजपा की मंशा कांग्रेस से ज्यादा भूपेश बघेल को हराने की होगी।' वहीं दूसरी ओर भाजपा के प्रवक्ता सच्चिदानंद उपासने का कहना है कि भाजपा कांग्रेस और भूपेश बघेल दोनों को हराने के लिए चुनाव लड़ेगी न की किसी की मदद करने के लिए। हमें जोगी परिवार और कांग्रेस के बीच होने वाले संग्राम का पूरा एहसास है लेकिन मरवाही उपचुनाव में जीत भाजपा की ही होगी, यह पूरा देश देखेगा।

आंकड़ा 69 पर पहुंच गया। इस नेता ने आगे बताया, 'इसी कड़ी में बघेल के लिए अपने इस आरोप को और पुख्ता करने का मरवाही उपचुनाव से बड़ा मौका नहीं मिल सकता। यही कारण है कि बघेल ने इस विधानसभा उपचुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। और वो खुद मरवाही के पार्टी कार्यकर्ताओं से जुड़ गए हैं और निर्देश दे रहे हैं।' पार्टी के नेताओं का मानना है

कि मुख्यमंत्री का हालिया बयान कि कांग्रेस मरवाही उपचुनाव हर हाल में जीतेगी उनकी गंभीरता को दर्शाता है। पार्टी के एक पूर्व प्रवक्ता और विधायक कहते हैं कि बघेल के लिए यह चुनाव जीतना सिर्फ राजनीतिक चुनौती नहीं है बल्कि उनके साख के लिए भी जरूरी है।

पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं- 'बघेल जोगी परिवार के बड़े आलोचक माने जाते हैं। कांग्रेस यदि चुनाव हारती है तो यह मुख्यमंत्री के लिए व्यक्तिगत हार भी होगी और संगठन में उनके आलोचक और भी मुखर हो जाएंगे। यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने अपने समर्थकों के मरवाही उपचुनाव में जीत को 'टारगेट 70' का नारा दिया है।' हालांकि प्रदेश कांग्रेस के एक अन्य प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने बताया, 'मरवाही विधानसभा सीट भले अजीत जोगी और उनके परिवार के पास ही रही है लेकिन यहां मतदाता परंपरागत तौर पर कांग्रेस पार्टी का है। अजीत जोगी की पहचान भी कांग्रेस पार्टी से ही थी।' ठाकुर आगे कहते हैं, 'यहां तक की 2018 के चुनाव में जोगी की जीत उनके कांग्रेसी पृष्ठभूमि के कारण ही हुई थी। लेकिन भूपेश बघेल के नेतृत्व में पार्टी ने आने वाले उपचुनाव के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस की जीत निश्चित है। टारगेट 70 पूरा जरूर होगा।' बता दें कि पिछले 18 महीनों में राज्य में हुए दो विधानसभा उपचुनाव और स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में ही हैं जिससे बघेल के दावों को भी कमजोर नहीं आंका जा सकता है। जोगी परिवार की व्यक्तिगत पकड़ के अलावा इस उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी और मुख्यमंत्री को कांग्रेस में भितरघात से भी लड़ना पड़ेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है।

● रायपुर से टीपी सिंह

राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच चल रही तनातनी और उसकी वजह से पैदा हुई सियासी उथल-पुथल के बीच प्रदेश की एक कद्दावर नेता की खामोशी तमाम नेताओं की बयानबाजी से भी ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई है। ये नेता हैं प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का पर्याय मानी जाने वाली वसुंधरा राजे सिंधिया। वे बीते कई दिनों से केंद्रीय राजधानी दिल्ली या जबरदस्त राजनीतिक उठापटक का सामना कर रहे जयपुर के बजाय धौलपुर में स्थित अपने राजमहल में मौजूद हैं।

हालांकि भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से ही इन आरोपों को सिरे से खारिज करती रही है कि राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार को अस्थिर करने में वह सचिन पायलट की साझेदार है। लेकिन हाल की कई घटनाएं पार्टी के रुख पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा करती हैं। जैसे कांग्रेस की तरफ से जारी किए गए एक ऑडियो में कथित तौर पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का विधायकों की खरीद-फरोख्त से जुड़ी बातचीत करना। सचिन पायलट का हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए मुकुल रोहतगी और हरीश साल्वे जैसे ऐसे वकीलों को ही अपना पैरोकार चुनना जिनका भाजपा के प्रति स्पष्ट झुकाव किसी से नहीं छिपा है। पायलट का अपने समर्थक विधायकों के साथ भाजपा शासित प्रदेश हरियाणा में ही रुके रहना। और बीते कुछ दिनों में मुख्यमंत्री गहलोत के करीबियों के यहां अचानक से ईडी और सीबीआई के छापे पड़ना। इसके अलावा राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा गहलोत सरकार को विधानसभा सत्र बुलाने की इजाजत न देना भी ऐसी ही घटनाओं में से एक है।

यदि भारतीय जनता पार्टी के इस दावे को सही मान भी लें कि ये पूरी खींचतान कांग्रेस की अंदरूनी फूट का ही नतीजा है और इसमें उसकी कोई भूमिका नहीं है। तो भी इतने महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम से वसुंधरा राजे जैसी दिग्गज नेता का दूरी बनाए रखना जानकारों को चौंकाता है। राजे की इस चुप्पी को लेकर सूबे के राजनीतिक विश्लेषक मुख्य तौर पर दो मत रखते हैं। पहला तो यह कि वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान और खासतौर पर भाजपा में ऐसा कोई भी नया क्षत्रप उभरने नहीं देना चाहती हैं जो आगे चलकर उन्हें चुनौती दे सके। और जब बात सचिन पायलट जैसे युवा, महत्वाकांक्षी और ऊर्जावान नेता की हो तो किसी का भी अतिरिक्त सतर्क होना लाजमी है। इसके अलावा प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में मुख्यमंत्री गहलोत और



महारानी मौन क्यों ?

उम्मीद पर फिरा पानी

लोकसभा चुनाव में पार्टी के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए वसुंधरा राजे को उम्मीद थी कि उनके पुत्र और झालावाड़ से सांसद दुष्यंत सिंह को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह जरूर मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रतिक्रिया के तौर पर वसुंधरा राजे खुद दिल्ली पहुंच गईं और प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण से पहले राजस्थान से चुने गए सभी सांसदों की मीटिंग बुला ली। खबरें तो यह थी कि राजे नाराज सांसदों को मनाने के लिए दिल्ली आई थीं। लेकिन कई जानकारों ने इसे उनके शक्ति-प्रदर्शन के तौर पर भी देखा। बताया जाता है कि तभी से वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की नजरों की किरकिरी बन गईं।

वसुंधरा राजे द्वारा अंदरखाने एक-दूसरे को समर्थन देते रहने की चर्चा भी आम है। हाल ही में सचिन पायलट ने भी मुख्यमंत्री गहलोत और राजे के बीच गठजोड़ होने के आरोप लगाए थे और लोकसभा में भाजपा की सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) के प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने भी।

हालांकि इसके बाद वसुंधरा राजे ने एक ट्वीट के जरिए कांग्रेस पर हमला बोला था। लेकिन जानकारों ने उसे महज औपचारिकता के तौर पर ही देखा। क्योंकि इसके बाद वे एक बार फिर पूरे परिदृश्य से नदारद हो गईं हैं। कुछ जानकार राजे और पायलट परिवार के बीच के असहज रिश्तों के लिए 2003 के विधानसभा चुनाव का भी हवाला देते हैं। तब सचिन पायलट की मां रमा पायलट ने राजे को उनकी पारंपरिक सीट झालरापाटन पर चुनौती दी थी। हालांकि रमा पायलट वह चुनाव जीत पाने में नाकाम रहीं

थीं। इस पूरे मामले में विश्लेषक वसुंधरा राजे की खामोशी की दूसरी बड़ी वजह के तौर पर भाजपा हाईकमान से उनके असहज रिश्तों को भी गिनवाते हैं। भाजपा से जुड़े एक वरिष्ठ नेता इस बारे में इशारों में हमें बताते हैं, 'इस सबके लिए हाईकमान ने राज्य में अपनी सबसे प्रमुख नेता को विश्वास में ही नहीं लिया। जबकि मैडम ये सब नहीं चाहती थीं।'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह से वसुंधरा राजे के असहज रिश्ते ही थे जिनके चलते उनके पिछले कार्यकाल (2013-18) में उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने की चर्चाएं लगभग हर छह महीने में जोर पकड़ने लगती थीं। जानकारों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री राजे के बीच की अनबन सबसे पहले 2008 में सामने आई थी। तब राजस्थान-गुजरात की संयुक्त नर्मदा नहर परियोजना के उद्घाटन के समय एक ही पार्टी से होने के बावजूद इन दोनों नेताओं ने बतौर मुख्यमंत्री एक-दूसरे के कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं लिया था। हालांकि पांच साल बाद इनके बीच रिश्ते सामान्य होने की खबरें भी खूब सुनने को मिलीं जब दोनों ने एक-दूसरे के लिए चुनावों में जमकर प्रचार किया था। मोदी लहर कहें या राजे की मेहनत 2013 में भाजपा ने राजस्थान विधानसभा चुनावों में जबर्दस्त बहुमत हासिल किया और अपनी लय बरकरार रखते हुए पार्टी ने 2014 के लोकसभा चुनावों में प्रदेश की सभी 25 सीटों पर कब्जा कर लिया। लेकिन जब इस जीत का श्रेय लेने की बारी आई तो दोनों एक-दूसरे को एक बार फिर खटकने लगे। प्रदेश में इस जीत पर अपना-अपना दावा करते राजे और मोदी समर्थक कई मौकों पर एक-दूसरे को आंखे तररेते भी नजर आए।

● जयपुर से आर.के. बिन्नानी

बैंकों से संबंधित कोई अध्यादेश किसी निर्वाचित सरकार के लिए खतरे की घंटी बन जाए, इससे दिलचस्प साजिश की बात और क्या हो सकती है? लेकिन राष्ट्रपति ने जो 'बैंकिंग रेगुलेशन (अमेंडमेंट)' अध्यादेश 2020 लागू किया, उसके बारे में महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार के कई सहयोगियों का यही विचार है। अब इसके लिए आप उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में चल रही तीन दलों की गठबंधन सरकार की अंदरूनी कमजोरियों को भी जिम्मेदार ठहरा सकते हैं या विपक्ष के 'मोदी-शाह फोबिया' को भी। मामूली से दिखते इस अध्यादेश ने एमवीए के सहयोगियों शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) और कांग्रेस की नींद उड़ा दी है। वे इसमें 'ऑपरेशन कमल' की दबे पांव आहट सुन रहे हैं, यानी इसे वे राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारों को अस्थिर करने के लिए दलबदल को उकसाने की भाजपाई चाल मान रहे हैं।

अध्यादेश भाजपा को कितना सियासी फायदा पहुंचाएगी और इसको लेकर एमवीए की आशंकाएं कितनी जायज हैं, इन प्रश्नों पर विचार करने से पहले यह देखें कि नरेंद्र मोदी सरकार प्रशासनिक लिहाज से इस अध्यादेश से क्या हासिल करना चाहती है। अध्यादेश सहकारी बैंकों पर दोहरे नियंत्रण के कारण पैदा होने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए लाया गया है। राज्य सरकारों सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के माध्यम से इन बैंकों में चुनाव और उनके प्रबंधकों पर नियंत्रण रखती है, जबकि रिजर्व बैंक इनके बैंकिंग संबंधी कामों को नियंत्रित करता है।

दरअसल, रघुराम राजन जब रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, उन्होंने इस दोहरी व्यवस्था को दूर करने में मदद मांगने के लिए महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण से मुलाकात की थी। चव्हाण भी इन सहकारी बैंकों पर चाबुक चलाना चाहते थे लेकिन वे अपने हाथ बंधे हुए महसूस करते थे क्योंकि उनकी गठबंधन सरकार की सहयोगी एनसीपी के नेता और खुद उनकी कांग्रेस पार्टी के साथियों का भी इन बैंकों में बहुत कुछ दांव पर लगा था। अर्थशास्त्री इला पटनायक ने स्पष्ट किया है कि इस दोहरी व्यवस्था का मतलब है कि सहकारी बैंक का प्रबंधन अगर अक्षम है या उसे खोखला कर रहा है तो भी



ऑपरेशन कमल की आहट!

रिजर्व बैंक कुछ नहीं कर सकता। लेकिन यह अध्यादेश रिजर्व बैंक को यह अधिकार दे रहा है कि वह इन बैंकों के प्रबंधन को बर्खास्त करने के लिए सहकारिता रजिस्ट्रार के फैसले को पलट सकता है, सहकारी समितियों को भंग या उनका विलय कर सकता है। मोदी सरकार के अध्यादेश ने एक झटके में उन नेताओं के मन में दहशत पैदा कर दी है, जो इन सहकारी बैंकों के प्रबंधन पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण के जरिए इनके ग्राहकों के पैसों के बल पर अपना राजनीतिक या वित्तीय मतलब सीधा करते रहे हैं। तब, महाराष्ट्र की एमवीए सरकार इसको लेकर परेशान क्यों है? इस गठबंधन के किसी सहयोगी ने खुलकर कोई आशंका नहीं जाहिर की है लेकिन एमवीए के अंदर गहरी खलबली मची हुई है।

अगर आप केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता में गंभीरता से विश्वास नहीं करते तो यह कहा जा सकता है कि सहकारी बैंकों पर रिजर्व बैंक की निगरानी केंद्र सरकार को महाराष्ट्र में भारी बढ़त दिलाएगी। उसे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं रह जाएगी, जिसने एनसीपी नेता शरद पवार, उनके भतीजे अजित पवार और अन्य लोगों के खिलाफ कथित महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक

घोटाले में कालेधन को सफेद करने का मुकदमा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दायर किया था। उस समय इस पर खूब शोर मचा था और पवार ने इसे बड़ी चतुराई से मराठा अस्मिता पर हमले का मामला बता दिया था।

रिजर्व बैंक सहकारी बैंकों पर राजनीतिक और वित्तीय लाभ उठाने पर रोक लगा सकता है। इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि शिवसेना को महाराष्ट्र में सहकारिता क्षेत्र की संगठित लूट में शामिल नहीं माना जाता है लेकिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपने सहयोगियों को इस लूट की छूट देने को तैयार दिखते हैं। पृथ्वीराज चव्हाण सरकार ने उस प्रथा को बंद करवाया था जिसके तहत सहकारी बैंकों द्वारा दिए जाने वाले कर्ज में राज्य सरकार को गारंटर बनाया जाता था। देवेंद्र फडणवीस सरकार ने भी इस नीति को जारी रखा था। लेकिन, एमवीए के अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि उद्धव सरकार ने इसे उलट दिया है। राज्य सरकार शोलापुर और पुणे में एनसीपी और कांग्रेस के एक-एक विधायक के संरक्षण वाली चीनी मिलों को दिए गए 80 करोड़ रुपये के कर्ज की गारंटर बन गई है। अब दिल्ली में बैठे राजनीतिक आका चाहें, तो अधिकार-प्राप्त रिजर्व बैंक उस सहकारी बैंक के प्रबंधकों, उन दोनों विधायकों और एमवीए सरकार का जीना दूध कर सकता है। 1960 के दशक से सहकारी बैंक महाराष्ट्र की राजनीति में क्या भूमिका निभाते रहे हैं, इसकी यह तो बस एक छोटी-सी मिसाल है।

● बिन्दु माथुर

अब महाविकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार में वैचारिक मतभेद के बिना भी दरारें उभरने लगी हैं, तो जाहिर है कि भाजपा की बांछे खिल उठी होंगी। सरकार में प्रशासन संबंधी मतभेदों को सुलझाने के लिए जब एमवीए के जनक शरद पवार उद्धव ठाकरे के साथ बैठकें करते नजर आते हैं तो इससे मुख्यमंत्री की कोई बेहतर छवि नहीं उभरती। कांग्रेसी मंत्री तालमेल की कमी की बातें खुलकर कह रहे हैं। यह भी कोई रहस्य नहीं है कि यहां शिवसेना से हाथ मिलाने के फैसले के कारण राहुल गांधी अपनी पार्टी के वरिष्ठ

एमवीए की कमजोरियां

नेताओं से खुश नहीं हैं। लेकिन राहुल के किसी कदम से राज्य में चुनाव की नौबत आती है, तो उनके कई विधायक पाला बदल सकते हैं। ऐसे अधिकतर बागी वैचारिक अनुकूलता के कारण एनसीपी के तंबू में ज्यादा सहज महसूस कर सकते हैं। लेकिन पवार पैसे की ताकत को कम आकने की गलती नहीं कर सकते। हाल में इसकी ताकत कई राज्यों में दिख चुकी है, मध्य प्रदेश सबसे ताजा उदाहरण है। इसके अलावा, पवार को अपने भतीजे की महत्वाकांक्षाओं और बढ़ती अधीरता का भी पूरा एहसास है।

मिशन 2022

उत्तर प्रदेश की मृतप्राय कांग्रेस इकाई में जान फूंक रही पार्टी की नेता प्रियंका गांधी राज्य व राज्यवासियों की दुर्गति के लिए सत्तापक्ष ही नहीं, विपक्ष को भी लाल आंखें दिखा रही हैं।
मिशन 2022 पर नजर गड़ाए प्रियंका ने अपनी दादी इंदिरा गांधी का नाम ले सियासी

उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का सियासी संग्राम दिन पर दिन तेज होता जा रहा है। दरअसल, प्रियंका गांधी की नजर 2022 पर है। टारगेट है विधानसभा चुनाव और वहां की 403 सीटें। बचपन से राजनीति देखती, सुनती, समझती प्रियंका गांधी अब खुद राजनीति के मैदान में हैं। हालांकि सक्रिय राजनीति में वे डेढ़ साल पहले ही आई हैं और किसी भी सदन की सदस्य नहीं हैं लेकिन परिपक्व हैं। परिपक्वता का यह सुबूत है कि एक ही जुमले से उन्होंने सत्ता के साथ विपक्ष पर बहुत ही करारा वार किया है। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव व पार्टी की उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने कहा कि, मैं इंदिरा गांधी की पोती हूँ, विपक्ष के कुछ नेताओं की तरह भाजपा की अघोषित प्रवक्ता नहीं। अपनी पार्टी की ओर से उग्र प्रभारी होने के नाते प्रियंका राज्य सरकार की लापरवाहियों को समय-समय पर जोर-शोर से उठाती रहती हैं। उधर, सपा के अखिलेश यादव और बसपा की मायावती को सियासी तौर पर डरा चुके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य में प्रियंका की बढ़ती लोकप्रियता से चिंतित हैं।

उत्तर प्रदेश की मौजूदा विपक्षविहीन सी राजनीति में प्रियंका गांधी दमदार विपक्षी नेता के तौर पर उभरी हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कोरोना संक्रमण से लेकर कानपुर शेल्टर होम मामले तक योगी सरकार को जबरदस्त तरीके से घेरने में जुटी हैं। वहीं, उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टियां (सपा और बसपा) कांग्रेस की तर्ज पर योगी सरकार को घेरती नजर नहीं आईं। मजदूरों की घरवापसी के लिए प्रियंका गांधी और योगी सरकार के बीच बस विवाद में जब मायावती कूदी थीं तो ऐसा लगा मानो वे योगी सरकार का बचाव कर रही हों। अपने ट्वीट की एक पूरी श्रृंखला में मायावती का तीखा हमला योगी सरकार के बजाय कांग्रेस पार्टी पर दिखाई दिया। वहीं, अखिलेश यादव ने एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में इशारों में कांग्रेस पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने बसपा को बाकायदा भाजपा का सहयोगी दल और मायावती को भाजपा का प्रवक्ता तक कहा था।

प्रभारी होने की जिम्मेदारी को निभाती हुई महासचिव प्रियंका गांधी राज्य के कांग्रेसियों को सक्रिय बनाने में एड़ी-चोटी का जोर लगाए हुए हैं। उग्र में कांग्रेस को पुराने तेवर में लाने के मकसद के तहत प्रियंका गांधी ने सोनभद्र में आदिवासियों के नरसंहार का मामला हो, नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों का मामला हो, उत्तर प्रदेश में बिजली-पानी की कीमतें बढ़ने से लेकर शिक्षक भर्ती मामला या जनहित से जुड़ा कोई और मुद्दा, लगातार आवाज उठाई है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने लगातार बढ़ रही पेट्रोल-डीजल की



विधानसभा चुनाव से पहले मजबूती की कवायद

दशकों से उग्र की राजनीति ऐसे मोड़ पर है कि जब चुनाव का समय होता है तो कांग्रेस को सभी पार्टियां अछूत मानने लगती हैं। सो, अब भावी 2022 में होने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस अपने को इस स्थिति में ले आना चाहती है कि उसे किसी पार्टी की दरकार न रहे, बल्कि दूसरी पार्टियां उससे मिलकर अपनी चुनावी नैया पार करने को लालायित दिखें। वर्ष 2022 तक पार्टी संगठन व पार्टीजनों को ऊर्जावान बनाए रखने में प्रियंका गांधी सफल रहती हैं तो कांग्रेस हाईकमान उम्मीद कर सकता है कि पार्टी राज्य की सभी 403 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करे। परिस्थितिवश, किन्हीं छोटी पार्टियों के साथ कुछ सीटों के लिए चुनावी समझौता करना पड़े, तो बात दूसरी होगी।

कीमतों को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि भाजपा सरकार ने पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ाकर यह बात साफ कर दी है कि भाजपा को महामारी संकट के समय भी जनता की जब

काटने में ज्यादा रूचि है। उन्होंने कहा कि जनता इस लूट को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है।

प्रियंका ने दावा किया कि इस संकट के समय केंद्र सरकार ने जनता की जब काटने का इतिहास रचा है। डीजल की कीमत, पेट्रोल की कीमत को पार कर चुकी है, जबकि दुनियाभर में कच्चे तेल के दाम में भारी गिरावट है। कोविड-19 संकट सहित तमाम मुद्दों को लेकर प्रियंका गांधी ट्वीट कर योगी सरकार को घेरने में जुटी हैं तो कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर सरकार को कठघरे में खड़ा कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को 21 दिनों तक जेल में भी रहना पड़ा है।

कांग्रेस हाईकमान वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में 3 दशकों बाद बड़ी जीत की उम्मीद कर रहा है। पार्टी की इस उम्मीद का सारा बोझ महासचिव व प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी पर है। प्रियंका इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने की मंशा के साथ पार्टी के प्रदेश संगठन के नटबोल्ट कस रही हैं यानी संगठन को ऊर्जावान बना रही हैं। उनके इस मिशन में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू कंधे से कंधा मिलाए हुए हैं।

● लखनऊ से मधु आलोक निगम

को रोग के बाद बदले हालात में बिहार पहला राज्य है, जहां विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। संभवतः इसी साल अक्टूबर-नवंबर में होने जा रहे ये चुनाव देश में नए तरीके से प्रचार और जनसंपर्क अभियानों को मूर्त रूप देंगे, जिसमें हर

मतदाता तक पहुंचना है, लेकिन पहले जैसे नहीं, बल्कि वर्चुअल रैलियों, सोशल

मीडिया प्लेटफार्मस, ऑनलाइन तकनीक के जरिए। संभव है कि बुजुर्गों के साथ कोरोना संक्रमितों के लिए भी मतदान के अलग तरह के इंतजाम करने पड़ें। ऐसे में राजनीतिक दलों के लिए भी चुनौतियां बढ़ेंगी, विशेषकर नीतीश कुमार के लिए, जो चौथी

बार एनडीए के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। ये तो उन्हें भी पता है कि तमाम कसौटियों से अलग मतदाता कोरोना से जंग में उनकी सफलता का आंकलन जरूर करेंगे। कोरोना से जीत के आंकड़े नीतीश रखेंगे, तो इंतजामों को अपर्याप्त, कमजोर और देर से करने के आरोप महागठबंधन की ओर से लगेंगे ही।

नीतीश चार महीने पहले ही एनडीए से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं, जबकि लालू यादव के बेटे तेजस्वी चाहते हैं कि महागठबंधन आरजेडी के नेतृत्व में मुकाबले में उतरे। उन्होंने एनडीए से चिराग पासवान (एलजेपी प्रमुख) की नाराजगी की खबरों पर उन्हें महागठबंधन में आने के संकेत भी कर दिए हैं। चिराग कहते हैं कि उनकी पार्टी का गठबंधन भाजपा से है, न कि जेडीयू से। इस पर जेडीयू के तेवर हैं कि फिर तो भाजपा के कोटे से ही एलजेपी को मैदान में आना चाहिए। जानकार इसे पासवान द्वारा दबाव की राजनीति करार देते हैं।

फिलहाल तो महागठबंधन में भागीदार कांग्रेस तेजस्वी से नाराज है कि वे बिहार से दो महीने से बाहर हैं, जबकि इधर सुगबुगाहट तेज है कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का विलय जेडीयू में हो सकता है। खुश तो अन्य छोटे भागीदार पूर्व कैबिनेट मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी और मुकेश सहानी की वीआईपी भी नहीं हैं। ऐसे में महागठबंधन की सफलता का खाका कैसे खींचा जा सकेगा? ये हालात तब हैं, जब कई राजनीतिक पंडित बिहार को महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा के रास्ते पर जाता हुआ देख रहे हैं, जहां एनडीए की राह आसान थी, लेकिन चुनाव बाद हालात बदल गए थे। बमशिकल हरियाणा में

आसान नहीं राह



सातवीं बार मुख्यमंत्री बनने का सपना

नीतीश सातवीं बार मुख्यमंत्री बनने का सपना लेकर चुनावी तैयारियों में व्यस्त हो चले हैं। बिहार में बतौर मुख्यमंत्री उनका राजनीतिक सफर तीन मार्च 2000 को शुरू हुआ, लेकिन पर्याप्त बहुमत न होने से सात दिन में ही कुर्सी चली गई। दूसरा मौका 24 नवंबर 2005 को मिला और भाजपा के साथ गठबंधन में सरकार पूरे पांच साल चली। तीसरा कार्यकाल 26 नवंबर 2010 से शुरू हुआ, लेकिन कार्यकाल के पूरा होने के पहले ही 2014 के लोकसभा चुनाव में हुई करारी हार का जिम्मा लेते हुए उन्होंने 19 मई को इस्तीफा देकर जीतनराम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया। इससे पहले जून 2013 में ही जेडीयू और भाजपा के रास्ते अलग हो चुके थे। नीतीश का मुख्य विपक्ष आरजेडी की दोस्ती रास आ चुकी थी। नीतीश ने करीब 10 महीने बाद जब मांझी से मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली करने को कहा, तो वह मुकर गए। इस पर पार्टी ने मांझी को बाहर का रास्ता दिखाया और 22 फरवरी 2014 को नीतीश चौथी बार मुख्यमंत्री बने। 2015 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने आरजेडी और कांग्रेस के साथ महागठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा और 42.9 प्रतिशत वोट के साथ 178 सीटें जीतीं। नीतीश पांचवीं बार मुख्यमंत्री बने तो लालू यादव के पुत्र तेजस्वी उपमुख्यमंत्री और तेजप्रताप को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। हालांकि खींचतान के चलते ये गठबंधन टिक नहीं सका। नीतीश एक बार फिर एनडीए के पाले में चले गए। उन्होंने अपनी छठी पारी 27 जुलाई 2017 को शुरू की।

नए साथी की मदद से सत्ता बच सकी थी। बिहार में आरजेडी की हालत भी कमोबेश उन तीन राज्यों के मुख्य विपक्षी पार्टी जैसी ही है। आरजेडी के स्टार प्रचारक लालू यादव जेल में हैं, पार्टी नेताओं के पलायन से पीड़ित है और तेजस्वी के पास नीतीश-मोदी से सीधी टक्कर लेने जैसा न करिश्माई व्यक्तित्व है, न अनुभव।

महागठबंधन 2019 के लोकसभा चुनाव में 40 में से मात्र एक सीट ही जीत सकी थी, ऐसे में वह दावों से परे जाकर बहुत बड़े सपने देखने की स्थिति में नहीं है। आरजेडी के लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन की वजह थी कि तब मोदी फैक्टर चरम पर था। मोदी को बतौर प्रधानमंत्री देखने के लिए

देश भर में 17 प्रतिशत लोगों ने वोट किया था, जो बिहार में करीब 35 प्रतिशत था। दूसरी वजह थी कि महागठबंधन में आरजेडी ने कमजोर साथियों को अधिक सीटें देकर खुद 19 पर आजमाइश की। नतीजा ये रहा कि छोटे साथी दल भी हार गए, आरजेडी के हाथ भी खाली रह गए।

अब बात नीतीश कुमार की करें, तो लगभग 15 वर्षों से बिहार की कमान उनके हाथों में है। 15 साल बड़ी अवधि होती है एंटी-इनकंबेंसी से उभरने के लिए, क्योंकि एक ही नेतृत्व से लोग सुस्ती महसूस करते हैं, मन उबने लगता है, नवाचारों की कमी दिखती है। ऐसे में जानकार आंकलन कर रहे हैं कि महागठबंधन की रणनीति कारगर तरीके से धरातल पर आ सकी, तो एनडीए को खासी मुश्किल हो सकती है। परिणाम महाराष्ट्र या हरियाणा जैसे हो सकते हैं। नीतीश कुमार जंगलराज मिटाने और बिहारी अस्मिता के मुद्दे पर 2005 से जीतते आ रहे हैं, जो शायद अब मद्धिम पड़ चुका है। अब कुछ नया लेकर आना था, तो नीतीश भाजपा और मोदी की तर्ज पर उलटे सवाल कर रहे हैं कि आरजेडी ने 15 वर्षों में क्या किया? इधर नीतीश के समर्थकों का एक धड़ा है, जिसकी आंखें यही सवाल लेकर जेडीयू को देख रही हैं। वो पूछना चाहते हैं कि नीतीश की छवि पलटूरा क्यो बनी? क्यो उन्हें सत्ता के भूखे और अवसरवादी के रूप में देखा जाने लगा है? इस 5 साल के शासन में एक-तिहाई वह आरजेडी, तो शेष भाजपा के साथ क्यो रहे? उन्होंने आरजेडी और लालू का इस्तेमाल किया, फिर भाजपा के साथ हो लिए और अब उसी आरजेडी पर हमला कर रहे हैं।

● विनोद बक्सरी

भारत और नेपाल के रिश्तों में अनचाही कड़वाहट आ चुकी है। बीते दशक में रिश्ते इतने खराब हो गए कि नेपाल की भारत के पड़ोसी देश चीन से नजदीकियां बन गईं और नेपाल में भारत विरोधी राष्ट्रवाद ने जन्म ले लिया। यही सबसे अधिक चिंता का सबब है जिससे दोनों देशों के आपसी संबंध हर दिन खराब हो रहे हैं और प्रगाढ़ता का कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा है। अब रिश्ते दोस्ती की परिभाषा से निकलकर दुश्मनी की राह की ओर बढ़ रहे हैं। नेपाल न सिर्फ भारत को आंखें दिखा रहा है, बल्कि कई मौकों पर उसके अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने की हिदायत भी दे चुका है। क्या इसे भारत की विदेश नीति की बड़ी असफलता के तौर पर देखा जाए या फिर चीन के नेपाल पर बढ़ते प्रभाव के रूप में परिभाषित किया जाए, यह चर्चा का विषय जरूर हो सकता है। इस बीच विशेषज्ञों का दावा है कि भारत ने हालात नहीं संभाले तो सामरिक दृष्टि से बड़े नुकसान उठाने पड़ सकते हैं।

लगातार और तेजी से बिगड़ रहे भारत-नेपाल संबंधों को जब खंगाला गया तो कई ऐसे तथ्य सामने आए जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। भारत की ओर से अपने सामरिक महत्व के लिए कई कदम ऐसे उठाए गए हैं, जिनसे नेपाल का भरोसा भारत के प्रति कम हुआ है। इसके चलते वहां पिछले कुछ समय से चल रहे राष्ट्रवाद में भारत विरोधी मूवमेंट शामिल हो गया है। सवाल उठता है कि अखिर कौन से वो तथ्य हैं जिनकी वजह से लगातार बिगड़ते हालात जा रहे हैं। इस कड़ी में पहला कारण है भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले शपथ ग्रहण के तुरंत बाद ही नेपाल में मधेशी आंदोलन खड़ा हो जाना। नेपाल में मधेशियों की संख्या सवा करोड़ से अधिक है और इनकी बोली मैथिली है। ये हिंदी और नेपाली भी बोलते हैं। भारत के साथ इनका हजारों साल पुराना रोटी-बेटी का संबंध है। लेकिन इनमें से 56 लाख लोगों को अब तक नेपाल की नागरिकता नहीं मिल पाई है। जिन्हें नागरिकता मिली भी है, उन्हें ना तो सरकारी नौकरी में स्थान मिलता है और ना ही संपत्ति में। कुछ सालों पहले नेपाल में अधिकारों की मांग को लेकर मधेशी आंदोलन शुरू हुआ।

नेपाल में पहाड़ी इलाकों में 7-8 हजार की आबादी पर एक सांसद है लेकिन तराई में सत्तर से एक लाख की आबादी पर एक सांसद। इसी दौरान नेपाली संसद में नेपाल को संघीय देश बनाने और सात राज्यों में बांटने को लेकर एक मसौदा पेश किया गया। इस प्रस्ताव को मधेशी विरोधी बताते हुए मधेशियों ने नेपाल में एक अलग मधेशी राज्य की मांग को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया। पुलिस और मधेशियों के बीच



आखिर क्यों बिगड़े रिश्ते ?

क्या भारत नेपाल संबंधों में सुधार आ पाएगा ?

2015 के बाद से लगातार भारत और नेपाल के संबंधों में आ रही गिरावट में क्या कोई सुधार आ पाएगा? क्या भारत के लिए नेपाल भी पाकिस्तान की तरह आने वाले समय में कोई दुश्मन देश बन जाएगा? क्या भारत और नेपाल जल्दी ही अपने सीमा विवादों को समाप्त कर लेंगे? ऐसे ही कई सवाल इस समय मुंह उठाए खड़े हैं। जानकारों का मानना है कि भारत के लिए नेपाल से अच्छे रिश्ते होने कई कारणों से बहुत ही महत्वपूर्ण है इसलिए भारत नेपाल के प्रति फूक-फूक कर कदम बढ़ा रहा है। इसमें एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि चीन कभी नहीं चाहेगा कि भारत और नेपाल के रिश्ते अच्छे हों क्योंकि कालापानी और लिपुलेख जैसे विवादित स्थानों पर तीनों देशों की सीमाएं मिलती हैं। ऐसे में नेपाल को व्यापारिक केंद्र बनाने के साथ-साथ चीन इन स्थानों को भारत के खिलाफ सामरिक क्षेत्र भी बनाना चाहता है।

टकराव हुए, कई लोगों की जान गई। इसी दौरान चक्काबंदी हो गई। नेपाल की अर्थव्यवस्था को तीन महीने जबर्दस्त नुकसान हुआ। देश में तेल सहित अन्य सामानों की भारी कमी हो गई। नेपाल सरकार ने इस पूरे आंदोलन का ठीकरा भारत पर फोड़ दिया जिस पर भारत ने नाराजगी जताई। घटनाक्रम के दौरान नेपाल सरकार ने कहा कि भारत नेपाल के अंदरूनी मामलों में दखल दे रहा है, जिसके उसको परिणाम भुगतने पड़ेंगे।

भारत और नेपाल के बीच कड़वाहट की

दूसरी वजह है चीन की 'वन बेल्ट वन रोड' योजना में नेपाल का शामिल होना। चीन अपने कारोबार को भारत सहित अन्य पड़ोसी देशों में फैलाने की योजनाओं पर काम कर रहा था। उसने वन बेल्ट वन रोड योजना शुरू की। इसमें भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान के बीच एक कारोबारी सड़क और रेलमार्ग प्रस्तावित था। भारत ने अपने आपको चीन की इस योजना से अलग रखा लेकिन पाकिस्तान के बाद नेपाल इस योजना में शामिल हो गया। भारत की ओर से कूटनीतिक प्रयास किए गए कि नेपाल इस योजना का हिस्सा न बने, लेकिन बात बनी नहीं। इस योजना के बाद चीन का नेपाल के आर्थिक गलियारे में प्रवेश हो गया और उसकी भारत के प्रति नेपाल की निर्भरता भी कम होती गई।

भारत को इस कॉरिडोर से इसलिए भी आपत्ति थी कि यह पाकिस्तानी कब्जे वाली पीओके की सीमा से होकर गुजरना था। नेपाल पर भारत का प्रभाव दशकों से रहा है। दोनों देशों के बीच खुली सीमा है और छोटे-बड़े भाई जैसे रिश्ते हैं, साथ ही बेशुमार व्यापार है, एक धर्म है और रीति रिवाज भी एक जैसे हैं। दोनों देशों के बीच बिगड़ते संबंधों को लेकर जब बात होती है तो चीन का जिन्न जरूरी रूप से होता है। चीन ने हाल के वर्षों में नेपाल में भारी निवेश किया है। नेपाल में कई प्रोजेक्ट्स पर चीन काम कर रहा है जिनमें बुनियादी ढांचों सी जुड़ी परियोजनाएं ज्यादा हैं। चीन यहां एयरपोर्ट, रोड, हॉस्पिटल, कॉलेज, मॉल्स इत्यादि बना रहा है, साथ ही एक रेलवे लाइन पर भी काम कर रहा है जो लगभग पूरी हो चुकी है।

● ऋतेन्द्र माथुर

अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव नजदीक है। सियासत अपने पूरे शबाब पर पहुंच चुकी है। मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अपने उलूल-जुलूल बयानों के चलते पूरे कार्यकाल के दौरान सुर्खियों में छाए रहे हैं। अब चुनाव प्रचार के दौरान भी डोनाल्ड ट्रम्प की अकड़ और घमंड साफतौर पर देखने को मिल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को टक्कर देने के लिए सामने जो बिडेन हैं। सर्वे में वे डोनाल्ड ट्रम्प को पछाड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं

जिससे ट्रम्प आगबबूला हो बैठे हैं। एक तरफ जहां जो बिडेन राष्ट्रपति ट्रम्प को कोरोना वायरस की रोकथाम में लापरवाही का जिम्मेदार बता रहे हैं

और ट्रम्प की नीतियों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं तो दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रम्प तीखी बयानबाजी से जो बिडेन पर व्यक्तिगत हमला कर रहे हैं। ट्रम्प ने हालिया प्रेस कांफ्रेंस में बिडेन पर हमला बोलते हुए कहा कि जो बिडेन दिमागी तौर पर थके हुए हैं, वह इस लायक नहीं हैं कि अमेरिका की कमान संभाल सकें।

अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव नवंबर में होने हैं। कोरोनावायरस महामारी के चलते रैलियों पर रोक लगी हुई है। चुनाव प्रचार मीडिया, सोशल माडिया के माध्यम से ही हो रहा है। डोनाल्ड ट्रम्प अपनी जीत के लिए पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। जबकि उनके खिलाफ बिडेन कड़ी टक्कर देने को तैयार हैं। बिडेन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को लगातार नाकाम राष्ट्रपति के तौर पर दिखा देने में लगे हुए हैं। जबकि डोनाल्ड ट्रम्प खुद को सबसे बेहतर राष्ट्रपति बता रहे हैं। जब पत्रकारों ने सर्वे में जो बिडेन को मिल रही बढ़त के बारे में पूछा तो डोनाल्ड ट्रम्प आगबबूला हो बैठे और कहा कि यह सारे सर्वे फर्जी हैं, हमने खुद सर्वे करा रखा है और उसमें हम बड़ी जीत दर्ज करने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रम्प ने इसी के आगे ये भी कह दिया कि आप सब जिस तरह से मुझसे सवाल पूछ रहे हैं वैसे सवाल कभी जो बिडेन से पूछिए, वह जवाब में मम्मी-मम्मी चिल्लाने लगेंगे और घर भाग जाएंगे।

अमेरिकी राष्ट्रपति का यह अति-उत्साह बतलाता है कि वह अपनी जीत पक्की मान रहे हैं और अपने खिलाफ जो बिडेन को कमजोर उम्मीदवार मान रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति का यूँ तो मीडिया वालों से छत्तीस का आंकड़ा रहता है लेकिन वह मीडिया में रहकर जो बिडेन पर हमला बोलने का मौका हाथ से नहीं जाने देते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति की मानें तो उनसे बेहतर उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के लिए है ही नहीं।

चुनाव जंग में बदला



अमेरिकी चुनाव में चीन तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा

विज्ञापनों की समीक्षा करने वाले रिपब्लिकन पोल्स्टर फ्रैंक के अनुसार, अमेरिकी चुनाव में दोनों उम्मीदवारों के बीच कांटे का टक्कर होगी। राष्ट्रपति चुनाव में अर्थव्यवस्था और कोरोनावायरस से निपटने के कदमों के साथ ही चीन तीसरा सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। दोनों प्रतिद्वंद्वी चीन को लेकर कड़े तैवर दिखा रहे हैं। इसे लेकर दोनों के चुनाव प्रबंधन समिति ने कई विज्ञापन भी जारी किए हैं। ट्रम्प के चुनावी अभियान प्रबंधकों ने इस तरह के विज्ञापन निकाले हैं, जिनमें बिडेन चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की आभगत में लगे हुए हैं। वहीं, दूसरी तरफ बिडेन के चुनावी अभियान की ओर से ट्रम्प को कोरोना वायरस को हल्के में लेते हुए महामारी के बारे में पारदर्शी रहने को लेकर जिनपिंग की सराहना करते हुए दिखाया गया है। जबकि, यह स्पष्ट है कि चीन ने महामारी के बारे में दुनिया के सामने विवरण देर से साझा किए।

अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव पर पूरे विश्व की नजरें रहा करती है लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय मूल के लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार भारतीय मूल के वोटर्स को लुभाने की कोशिश में लगे रहते हैं। मौजूदा वक्त में भारतीय मूल के वोटर्स के लिए उम्मीदवारों को चुनना आसान नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि एक ओर मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प हैं जिनके संबंध भारत से अच्छे रहे हैं और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खासमखास रहे हैं। तो दूसरी ओर जो बिडेन हैं जो एच1बी1 वीजा पर लगे प्रतिबंध को हटाने की बात कर रहे हैं। जिसका फायदा अमेरिका में रह रहे भारतीय नागरिकों को होगा।

2016 के अमेरिकी चुनाव में 16 लाख भारतीय मूल के लोगों ने वोट डाला था जिसमें 84 प्रतिशत लोगों ने ट्रम्प के खिलाफ वोट डाला था लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जीत दर्ज की थी। इस वक्त ट्रम्प की स्थिति उस समय जैसी नहीं है इसलिए ट्रम्प भी भारतीय मूल के वोटर्स को अपने साथ रखना चाहते हैं। अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर राजनीति जोरों

पर है। इस बीच एक ताजा सर्वे के अनुसार रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रम्प अपने प्रतिद्वंद्वी और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बिडेन से पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर यह अंतर चुनाव तक बना रहा तो ट्रम्प को हार का भी सामना करना पड़ सकता है।

अमेरिका के क्विनियाँक यूनिवर्सिटी के एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण में राष्ट्रपति ट्रम्प प्रतिद्वंद्वी जो बिडेन से 15 अंकों से पीछे चल रहे हैं। इस सर्वेक्षण में रजिस्टर्ड वोटर्स में से 52 फीसदी लोगों ने बिडेन के समर्थन की बात कही। वहीं केवल 33 फीसदी मतदाताओं ने ही ट्रम्प को समर्थन देने का ऐलान किया। अमेरिका के चुनाव में अर्थव्यवस्था के बाद चीन भी बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एनबीसी-डब्ल्यूएसजे के सर्वेक्षण में भी जो बिडेन अपने प्रतिद्वंद्वी डोनाल्ड ट्रम्प से आगे निकलते दिखाई दे रहे हैं। इस सर्वे में बिडेन को 51 फीसदी लोगों ने अपना समर्थन दिया जबकि, ट्रम्प को 40 फीसदी लोगों का समर्थन मिला। माना जा रहा है कि अर्थव्यवस्था को लेकर वोट ट्रम्प के काम से नाराज हैं।

● कुमार विनोद

हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने एक महिला के 25वें सप्ताह की गर्भावस्था के बावजूद गर्भपात कराने की अनुमति दी है। न्यायालय ने इस निर्णय के लिए महिला के गर्भ में पल रहे जुड़वां भ्रूण में से एक की चिकित्सकीय अनियमितताओं को आधार बनाया है। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि गर्भपात का विषय चिकित्सकीय विधिक तथा नैतिक रूप से विवादास्पद रहा है। गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971 (मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रिग्नेंसी एक्ट 1971) के पारित होने के पहले भारतीय दंड संहिता की धारा 312 के तहत अपराध की श्रेणी में रहा है। प्रजनक विकल्प का प्रयोग करने के अधिकार में यह भी शामिल है कि कब गर्भ धारण किया जाए तथा गर्भावस्था को अपने पूर्ण कार्यकाल तक ले जाना है या इसे समाप्त करना है। महिलाओं के इस अधिकार को भारत के संविधान के अनुच्छेद-21 में प्राण या दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अर्थ में शामिल उनकी निजता, गरिमा, वैयक्तिक स्वायत्तता, आत्म निर्णयन तथा स्वास्थ्य के अधिकार के केंद्र में रखा गया है।

भारत में गर्भपात के मौजूदा कानूनों को उदार बनाने के लिए 1964 में एक आंदोलन शुरू किया गया। कारण यह था कि कानूनी बाधाओं के कारण असुरक्षित गर्भपात बड़े पैमाने पर हो रहे थे। इसी पृष्ठभूमि में शांति लाल साह की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। गर्भपात के औषधीय, विधिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा नैतिक आयामों की व्यापक समीक्षा के बाद इस समिति ने 1966 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। समिति ने न केवल गर्भपात को वैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की, बल्कि यह भी कहा कि सुरक्षित गर्भपात का चिकित्सकीय समापन अधिनियम बनाया जाए। स्वास्थ्य विज्ञान की प्रसिद्ध पत्रिका 'द लांसेट' के अध्ययन के अनुसार, वर्ष 2015 में भारत में 1.56 करोड़ गर्भपात हुए जिनमें से 78 प्रतिशत उन स्थानों पर हुए जहां स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं। अध्ययन में यह भी कहा गया है कि तेजी से होने वाले घरेलू एवं वैश्विक सामाजिक व आर्थिक परिवर्तनों के दौर में महिलाओं के प्रजनक



महिला अधिकारों का संरक्षण

अधिकारों के समक्ष कई बाधाएं सामने आई हैं। कदाचित्त इसी कारण से सरकार को एमटीपी कानून 1971 में संशोधन करने की प्रेरणा मिली है। कालांतर में इस विषय पर उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों ने भी प्रस्तावित संशोधन को प्रेरित किया है। न्यायालय ने सुचिता श्रीवास्तव बनाम चंडीगढ़ प्रशासन (2009) के एक मामले में यह कहा कि महिलाओं की प्रजनक स्वायत्तता **उनकी निजता का मूल अधिकार** है तथा गर्भ धारण करने या नहीं करने का निर्णय केवल उनका ही निर्णय होगा और ऐसे निर्णय में राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। यह एक स्थापित तथ्य है कि प्रजनक और यौन स्वास्थ्य के अधिकार के अर्थ में जीवन स्वतंत्रता, दैहिक सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल तथा स्वास्थ्य सेवाओं के आवंटन, उपलब्धता एवं पहुंच सुनिश्चित करने का अधिकार भी शामिल है।

प्रजनक विकल्प का अधिकार संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का ही एक आयाम है। इसमें आनुवांशिक रूप से गर्भपात के विषय पर निर्णय लेने का अधिकार भी शामिल है। कई मामलों में

न्यायालय ने 20 सप्ताह की अवधि के बाद गर्भपात कराने की अनुमति दी है। इसका मुख्य कारण चिकित्सकीय अनियमितताएं हैं जो भ्रूण और माता दोनों के लिए गंभीर जोखिम पैदा करती हैं। न्यायालय ने मुरुगन नायकर बनाम भारत संघ के एक मामले में एक दुष्कर्म पीड़िता के 32 सप्ताह के भ्रूण के गर्भपात की अनुमति प्रदान की थी। न्यायालय ने मेडिकल बोर्ड की सिफारिशों को महिलाओं के प्रजनक अधिकारों पर वरीयता दी है। इसे निश्चित रूप से प्रजनक उत्तरदायित्व का एक उदाहरण कहा जा सकता है।

सरकार द्वारा दो मार्च 2020 को संसद में प्रस्तावित गर्भ के चिकित्सकीय समापन (संशोधन) विधेयक के प्रावधानों में गर्भ निरोधक की विफलता के कारण गर्भपात कराने के संदर्भ में अविवाहित महिला तथा उसके साथी को भी उसी रूप में शामिल किया गया है जिस रूप में कोई विवाहित महिला तथा उसका पति शामिल होता है। प्रस्तावित विधेयक में गर्भपात के लिए गर्भधारण की ऊपरी सीमा को 20 से 24 सप्ताह तक बढ़ाया गया है।

● ज्योत्सना अनूप यादव

दरअसल यौन हमलों के कारण होने वाले गर्भधारण या किसी असामान्यता या गर्भधारण की देरी का पता लगने पर 20-24 सप्ताह के बाद भी गर्भपात की अनुमति के लिए न्यायालयों में महिलाओं की मांगों में वृद्धि हुई है। चिकित्सा प्रौद्योगिकी में प्रगति के कारण भ्रूण की कुछ असामान्यताएं 20 से 24 सप्ताह के गर्भ के बाद ही स्पष्ट होती हैं। ऐसी स्थिति में चिकित्सकों द्वारा 24 सप्ताह के बाद भी सुरक्षित रूप से गर्भपात कराया जा सकता है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि गर्भपात के लिए ऊपरी सीमा में वृद्धि की परिकल्पना केवल कमजोर महिलाओं के लिए की गई है, जिनमें दुष्कर्म की शिकार महिलाएं, अनाचार पीड़ित महिलाएं

नियमों की आड़ में गलत निर्णय

तथा नाबालिग बालिकाएं शामिल हैं। विधिक दृष्टिकोण के अलावा, गर्भपात और प्रजनन स्वायत्तता के अधिकार को अधिकांशतः नैतिक दृष्टिकोण से भी देखा गया है। नैतिकता के चार स्तंभ-स्वायत्तता, लाभकारिता, विद्वेषहीनता तथा न्याय हैं। इनमें से स्वायत्तता सबसे महत्वपूर्ण है। इस संकल्पना में व्यक्तिगत अधिकार, स्वायत्तता, आत्म निर्णयन तथा निजता के विधिशास्त्रीय आयाम भी शामिल हैं। लाभकारिता तथा विद्वेषहीनता के सिद्धांत चिकित्सा विज्ञान को इस रूप में निर्देशित करते हैं ताकि वह सभी व्यक्तियों को लाभान्वित कर सके। इस संदर्भ में प्रजनक स्वायत्तता तथा प्रजनक उत्तरदायित्व में संतुलन होना ही चाहिए।

श्री मद्विभगवत गीता न केवल धर्म का ज्ञान कराती है, बल्कि जीवन जीने का ढंग भी बताती है। महाभारत के युद्ध के पहले श्रीकृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद मानव के लिए प्रेरणादायी है। गीता के उपदेशों का अनुसरण कर हम न केवल खुद का बल्कि समाज का भी भला कर सकते हैं। पंडित नारायण शर्मा कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में जब पांडवों और कौरवों की सेना आमने-सामने डटी थी, तो उस समय अर्जुन दुश्मन सेना में अपने बंधु-बांधवों को देखकर अवसादग्रस्त हो जाते हैं। तब अर्जुन (पार्थ) के सारथी बने श्रीकृष्ण (वासुदेव) उन्हें उपदेश देते हैं कि पार्थ तुम दुख का त्याग कर युद्ध करो। वर्तमान में भी जीवन की कठिनाइयों से लड़ने के लिए मानव को गीता में बताए सूत्रों को अपनाना चाहिए। गीता के सूत्रों को अपनाने से व्यक्ति उन्नति पथ की ओर अग्रसर होता है।

सोच में परिवर्तन: जो ज्ञानी पुरुष ज्ञान और कर्म को सम देखता है, उसी की सोच सही है। सही नजरिया रखने वाला व्यक्ति इच्छित फल की प्राप्ति कर लेता है। इसलिए व्यक्ति को ज्ञान और कर्म में समभाव बनाए रखना चाहिए।

मन पर नियंत्रण जरूरी: मन बहुत चंचल होता है और वह सदा यहां से वहां भटकता रहता है। अशांत मन को योग और ध्यान का नियमित अभ्यास कर वश में किया जा सकता है।

क्रोध पर काबू: गीता में लिखा है कि क्रोध भ्रम पैदा करता है और भ्रम से बुद्धि विचलित होती है। जब बुद्धि का विचलन हो जाता है तो तर्क करने की क्षमता भी क्षीण हो जाती है। जब मनुष्य में तर्क करने की क्षमता नहीं रह जाती तो वह पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। इसलिए क्रोध से बचना चाहिए।

मन पर अंकुश जरूरी: मन बहुत चंचल होता है। इस पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी होता है। जो मनुष्य मन पर नियंत्रण नहीं कर पाते, ऐसे लोगों का मन उनके दुश्मन की तरह कार्य करता है और धीरे-धीरे मनुष्य गलत राह की ओर अग्रसर हो जाता है।

आत्मचिंतन है आवश्यक: मनुष्य को हर दिन आत्मचिंतन करना चाहिए। आत्मचिंतन से जो ज्ञान प्राप्त होता है उससे व्यक्ति उसके अंदर छुपे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर सकता है।

कर्म का परिणाम: भगवान श्रीकृष्ण ने गीता में कहा है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है, उसे उसी के अनुरूप परिणाम की प्राप्ति होती है। इसलिए जीवन में अच्छे कर्म करने को महत्व देना चाहिए।

विश्वास से सफलता: मनुष्य जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है, बस जरूरत होती है तो इच्छित वस्तु को प्राप्त करने लगन के साथ कार्य करने की। ऐसा करके व्यक्ति को सफलता अवश्य मिलती है।



गीता जीवन जीने की कला

ऐसे पाएं तनाव से मुक्ति: प्रकृति के विपरीत कार्य करके मनुष्य तनाव से ग्रसित हो जाता है। यही तनाव मनुष्य के विनाश का कारण बनता है। इसलिए तनाव से मुक्त रहने के लिए धर्म और कर्म का मार्ग अपनाना चाहिए।

सोच से आचरण निर्माण: मनुष्य जिस तरह सोचता है, उसी तरह का आचरण करता है। स्वयं के अंदर के विश्वास को जाग्रत कर सोच में बदलाव ला सकता है, जो उसके जीवन के लिए बेहतर होगा।

ईमानदारी से करें काम: बुद्धिमान व्यक्ति कर्म को प्रधान रखता है, वह उसके फल के बारे में कभी नहीं सोचता। किसी काम को करने का यही उत्तम और उचित साधन है। जिंदगी में हर कोई सफल होना चाहता है। लेकिन हर इंसान सफल नहीं होता क्योंकि जीत हासिल करने के लिए कुछ गुण होना आवश्यक है। यदि वे गुण हम अपने जीवन में उतार लें तो सफलता के झंडे गाड़ सकते हैं। इसके लिए कुछ बातों को गांठ बांधकर अपने मन में बिठा लेंगे तो आप हर मोड़ पर उन बातों को याद रखते हुए आगे बढ़ सकेंगे।

भगवत गीता में भी कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं, जो आज के युग में भी सार्थक हैं। माना जाता

है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए गीता में बताई गई बातों पर अमल करके जीवन की हर परेशानियों से बाहर निकला जा सकता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्रीकृष्ण ने गीता का उपदेश देते हुए कहा है कि जो व्यक्ति बिना वजह किसी पर संदेह करता है वह कभी भी खुश नहीं रह सकता है। ऐसे में बिना किसी वजह के किसी पर संदेह नहीं करना चाहिए। भगवान श्रीकृष्ण ने गीता का उपदेश देते हुए कहा है कि वासना, लालच और गुस्सा, ये तीन नरक के द्वार हैं। भगवत गीता के अनुसार, जो लोग इन चीजों से दूर रहते हैं, वे हमेशा सुखी रहते हैं।

भगवत गीता के अनुसार, जो भी जन्म लेता है, उसकी मृत्यु भी निश्चित है। ऐसे में जो चीज निश्चित है उसके लिए कभी भी शोक या पछतावा नहीं करनी चाहिए। भगवान श्रीकृष्ण ने गीता का उपदेश देते हुए कहा है कि जो लोग बुद्धिमान हैं, उन्हें समाज के लिए काम करना चाहिए और समाज की भलाई के लिए बिना स्वार्थ योगदान देना चाहिए। भगवत गीता के अनुसार, जो व्यक्ति भगवान को याद करते हुए मृत्यु को प्राप्त करता है, वह सीधा भगवान के धाम को प्राप्त करता है, अर्थात् बैकुंठ धाम जाता है।



सुबह के काम निपटाकर नाश्ता लेकर बैठी थी, एक हाथ में चाय का कप और दूसरे में टीवी का रिमोट था, टीवी ऑन करने ही जा रही थी कि तभी किसी की आवाज सुनाई दी, डोरबेल की आवाज नहीं थी, फिर भी लगा शायद सूरज वापस आ गया हो, डाइनिंग टेबल से मेन गेट की तरफ उठी ही थी, कि फिर आवाज आई- अरे आप कहीं जाओ नहीं, बाहर कोई नहीं आया, हम यही हैं, बहुत दिन से हम लोगों को आपसे बात करनी थी, मैं इधर-उधर देखने लगी कि आवाज आ कहां से रही है, घर में तो मेरे सिवा कोई है ही नहीं, बिट्टू स्कूल में है, अमित ऑफिस में, बाबूजी शुक्लाजी के यहां गए हुए हैं और सूरज को पंसारी की दुकान भेजा हुआ है। तभी मेरी नजर चाय पर रखे कप पर पड़ी- ऐसा लगा जैसे वो कप नहीं कोई छोटा सा लड़का है। वो फिर बोला- प्लीज आप यहीं बैठिए, और मेरी बात सुन लीजिए। मैं बैठ गई, मैंने कहा- हां, हां बताओ न क्या कहना है? उस कपनुमा बच्चे ने कहा- आप कुछ दिन पहले जो नई क्राकरी वाली अलमारी लाई है ना, मुझे वहां जाना है, आप रोज मुझे उसी पुरानी अलमारी में बिठा देती हो, जबकि मैं कबसे आपके साथ हूँ, और सर जी कल ही जिन नए कप-प्लेटों को लिए आपने उनको वो नई वाली अलमारी दे

दी। तभी टेबल पर रखे नमकीन के डिब्बे से आवाज आई- आप हमको हमेशा ही बस नमकीन खिला देती हो, कितने सालों से मैंने कुछ और खाया ही नहीं, और कल जब सर जी सुंदर वाले विलायती डिब्बों को लिए तो आपने तुरंत उनको महंगे वाले ड्राईफ्रूट्स दे दिए। हम लोगों के साथ ऐसा पक्षपात आप क्यों करती हैं?

मेहमानों के सामने भी आप हम लोगों को नहीं जाने देती। हम लोग सुंदर नहीं हैं ना, इसीलिए आप ऐसा करती हैं, किसी भी त्योहार में भी आप हम लोगों को पुरानी वाली अलमारी में अंदर बंद कर देती हैं। क्या हम आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। तभी उस कप में मुझे सूरज की छवि नजर आने लगी। दो साल पहले मेरी कामवाली की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, उसका एक यही बच्चा था, पति पहले ही कैंसर से मर चुका था, तो हम और अमित उसको घर ले आए थे, आज करीब दस-ग्यारह साल का था, घर के छोटे-मोटे काम में मेरी मदद कर देता है। मुझे लगा जैसे परोक्ष रूप से सूरज मुझसे कह रहा हो कि आप हमेशा ही मुझे बिट्टू भइया के पुराने कपड़े देती हैं, प्लीज इस दीवाली मुझे भी नए वाले कपड़े दे दीजिए न। मैं तो आपके बहुत सारे काम करता हूँ ना। प्लीज बताइए, आप दे देंगी ना।

- डॉ. अपर्णा त्रिपाठी

कोई पेड़ लगाता है



कोई पेड़ लगाता है
फल दूजा कोई खाता है।
उसको है मालूम मगर
वो पेड़ लगाए जाता है।

कितने पेड़ लगाए उसने
कितनों की तैयारी है।
सारे पेड़ों का विकास हो
उसकी जिम्मेदारी है।
वो अपनी ये जिम्मेदारी
पूरी तरह निभाता है।
कोई पेड़ लगाता है
फल दूजा कोई खाता है।

सर्दी-गर्मी या वर्षा हो
उसको चिंता किसकी है।
कैसे पेड़ फलें-फूलें बस
उसको चिंता इसकी है।

और इसी चिंता में डूबा
वो दिन-रात बिताता है।
कोई पेड़ लगाता है
फल दूजा कोई खाता है।

उसको मोह बहुत होता है
पेड़ों से, हर डाली से।
उसको कितना सुख मिलता है
बगिया की रखवाली से।
कोई पेड़ कटे या सूखे
वो कितना दुख पाता है।
कोई पेड़ लगाता है
फल दूजा कोई खाता है।

— डॉ. कमलेश द्विवेदी

पायल, आज अवॉर्ड फंक्शन में पति के साथ नहीं गई थी। उसने पति का साथ हर कदम पर दिया था। वह रात-दिन परिवार की जिम्मेदारी संभालने में ही लगी रही। उसने कभी उफफ तक नहीं की। पति बड़े वैज्ञानिक थे। वह अपनी नई खोज में खोए रहते थे। वह कम पढ़ी-लिखी थी, पर कभी भी उनके काम में दखल नहीं देती थी। बस उनकी जरूरतों का पूरा ख्याल रखती, बिना किसी चाह के। उसे पति की मेहनत पर पूरा भरोसा था कि वह एक ना एक दिन बड़ी खोज करेंगे। देश में उनका मान-सम्मान होगा। इसी एक विश्वास पर उसने अपनी हर इच्छा को तिलांजलि दे रखी थी। इससे ज्यादा उसका वजूद ही क्या था? वह कभी-कभी अपने



अस्तित्व

आप से यहीं सवाल करती थी और अतीत में खो जाती। पति को आज बहुत बड़े मंच पर सम्मानित किया गया था। परिवार में खुशी का माहौल था। सब एक-दूसरे को बधाई दे रहे थे। पर वह चुप थीं, हमेशा की तरह। वह परिवार में अपना स्थान, अपना अस्तित्व खोज रही थी। शाम को पति ने घर आते ही उसके गले में फूलों की माला डाल दी। पायल, आज मैंने जो कुछ हासिल किया है। वह सब तुम्हारे ही कारण है। तुमने अपना अस्तित्व खोकर, समाज में मेरा अस्तित्व स्थापित कर दिया है। पायल ने नम आंखों से पति को

गले लगा लिया। क्या आपका अस्तित्व, मेरा अस्तित्व नहीं है?

- राकेश कुमार तगाला



सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद सोशल मीडिया पर जिस तरह से स्टार किड्स पर निशाना साधा जा रहा है, उससे आलिया भट्ट काफी परेशान नजर आ रही हैं। सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स ने उन्हें भी ट्रोल किया। हाल ही में आलिया ने अपने बचपन की एक तस्वीर शेयर कर लोगों से प्यार बांटने की अपील की है।



आलिया भट्ट की तस्वीर पर सेलेब्स ने लुटाया ढुलार

आ लिया की इस बेहद खूबसूरत तस्वीर पर उनकी मम्मी सोनी राजदान के साथ कई बॉलीवुड सेलेब्स कमेंट कर अपनी प्यार दे रहे हैं। ट्रोलिंग के बाद से सोशल मीडिया पर आलिया भट्ट के पोस्ट थोड़े कम हो गए हैं, पहले आलिया सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती थीं। हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने बचपन की तस्वीर शेयर की है, जिसमें उन्होंने प्यार बांटने का संदेश दिया है। इस ब्लैक एंड व्हाइट के कैप्शन में आलिया ने लिखा- कुछ प्यार भी बाँटिए। आलिया की इस तस्वीर पर मां सोनी



राजदान के साथ, बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, ऋतिक रोशन, रिद्धिमा कपूर साहनी, बिपाशा बसु, दिया मिर्जा सहित कई लोगों ने कमेंट किया है। नेपोटिज्म पर के मामले पर बहुत से सेलेब्स उनके सपोर्ट में भी सामने आए। लेकिन आलिया ने इस मामले पर चुप्पी साधी हुई है। वर्कफ्रंट की बात करें तो ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी हॉटस्टार पर उनकी फिल्म सड़क-2 रिलीज होगी। फिल्म में आदित्य रॉय कपूर, संजय दत्त और पूजा भट्ट भी हैं। इसके साथ ही वह ब्रह्मास्त्र के लेकर भी सुर्खियों में छड़ी हुई हैं, लॉकडाउन की वजह से फिल्म की शूटिंग अटक गई। फिल्म में आलिया और रणवीर कपूर पहली बार ऑनस्क्रीन रोमांस करते हुए नजर आएंगे। उनके साथ फिल्म में अमिताभ बच्चन भी नजर आने वाले हैं।

एक्ट्रेस आयशा जुल्का चलाती हैं स्पा!

अ क्षय कुमार और आमिर खान के साथ काम कर चुकी एक्ट्रेस आयशा जुल्का अब अपना कंस्ट्रक्शन का बिजनेस और स्पा का बिजनेस चलाती हैं। वो किसी जमाने में युवाओं के दिलों पर राज करती थीं। वो कैरियर में कई हिट फिल्म देने के बाद अचानक कैमरे की इस दुनिया से गायब हो गईं। 90 के दशक की मशहूर अदाकारा ने एक दिन अचानक अपनी शादी की खबर देकर कई लोगों के दिल तोड़ दिए थे। आयशा जुल्का ने फिल्मी कैरियर की शुरुआत 1983 में फिल्म कैसे-कैसे लोग से की थी। इस फिल्म ने उन्हें बॉलीवुड में पहचान दी थी। आयशा ने साल 1991 में अपनी पहली हिट मूवी दी थी। वह एक-एक बाद हिट देती गईं और डायरेक्टर्स की पहली पसंद बनती गईं। साल 1992 में फिल्म जो जीता वही सिकंदर में उन्होंने आमिर खान के साथ काम किया। इस फिल्म ने उनके कैरियर को शिखर पर पहुँचा दिया था। इसी साल उनकी फिल्म खिलाड़ी आई फिल्म सुपर हिट साबित हुई। आयशा जुल्का ने अक्षय कुमार, आमिर खान, सलमान खान, अजय देवगन, गोविंदा आदि कई बड़े कलाकारों के साथ काम किया।



ऑस्कर मिलने के बाद किसी ने मुझे हिंदी फिल्मों में काम नहीं दिया: रेसुल

सा उंड डिजाइनर रेसुल पुकुट्टी ने कहा कि स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए ऑस्कर पुरस्कार मिलने के बाद उन्हें हिंदी फिल्म उद्योग में काम मिलना बंद हो गया। साथ ही, कुछ प्रोडक्शन हाउस ने उन्हें यह कहते हुए मना कर दिया कि उन्हें उनकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऑस्कर विजेता संगीतकार एआर रहमान ने हाल ही में कहा था कि उनके खिलाफ एक गिरीह काम कर रहा है, जिसकी वजह से उन्हें बॉलीवुड में काम मिलने में मुश्किल हो रही है। पिछले महीने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने के बाद बॉलीवुड में शुरु हुई अंदरूनी बनाम बाहरी बहस के बीच उनका यह बयान आया। रहमान के बयान को साझा करते हुए, फिल्म निर्माता शेखर कपूर ने रविवार को ट्वीट किया था कि क्या बॉलीवुड एक कलाकार से असुरक्षित हो सकता है, जिसने अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज (एएमपीएस) से मान्यता प्राप्त की है।



को रोगावायरस की वजह से एशिया कप और टी-20 वर्ल्ड कप रद्द हो चुके हैं। लेकिन, अब एक अच्छी खबर भी है। लॉकडाउन के कारण पिछले चार महीने से क्रिकेट से दूर रहे फैन्स का इंतजार खत्म होने वाला है। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) अपने सीजन-13 के

साथ लौट रहा है। आईपीएल 19 सितंबर से 8 नवंबर के बीच यूई में खेला जाएगा। टी-20 वर्ल्ड कप टलने से आईपीएल का रास्ता साफ हो गया। कई लोग कह रहे हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट पर फ्रेंचाइजी क्रिकेट या यूं कहें कि पैसे का खेल भारी पड़ गया। दरअसल, दुनिया के सबसे अमीर बोर्ड के खिलाड़ी पूरा वर्ल्ड कप खेलकर जितना कमाते उसका दो से पांच गुना वो सिर्फ एक आईपीएल मैच से कमा लेंगे। इसे ऐसे समझें, वर्ल्ड कप में एक मैच खेलने पर टीम इंडिया के खिलाड़ियों

को 5 लाख मिलते। वहीं, आईपीएल में एक मैच खेलने पर कोहली को करीब 1.2 करोड़ मिलेंगे तो रोहित को 1 करोड़। ये तो रही खिलाड़ियों की बात। अगर बीसीसीआई की बात करें तो उसकी भी सबसे ज्यादा कमाई आईपीएल पर ही टिकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, 2020-21 में बीसीसीआई को 3 हजार 730 करोड़ रुपए की कमाई होने का अनुमान था। जिसमें से ढाई हजार करोड़ रुपए की कमाई सिर्फ आईपीएल के जरिए होने की उम्मीद थी। उसके अलावा 950 करोड़ रुपए सीरीज, टूर्नामेंट से और 380 करोड़ रुपए आईसीसी से मिलने का अनुमान था। यानी कि बीसीसीआई की कमाई में 67 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा आईपीएल का है।

टीम इंडिया के कप्तान और आईपीएल में आरसीबी के कप्तान विराट कोहली आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। उन्हें इस साल भी आरसीबी ने 17 करोड़ रुपए में रिटेन किया है। आईपीएल में हर टीम लीग के 14-14 मैच तो खेलती ही है। इस हिसाब से विराट कोहली को हर मैच के लिए 1.21 करोड़ रुपए मिलेंगे। विराट के बाद रोहित शर्मा को भी मुंबई इंडियंस ने 15 करोड़ रुपए में रिटेन किया है। यानी, उन्हें भी हर मैच के लिए 1.07 करोड़ रुपए मिलते हैं। बीसीसीआई दुनिया का सबसे रईस क्रिकेट बोर्ड है और जितनी फीस भारतीय खिलाड़ियों को मिलती है, उतनी दुनिया के किसी भी क्रिकेटर्स को नहीं मिलती है। बीसीसीआई की कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में 27 खिलाड़ी हैं। इन खिलाड़ियों को ए+, ए, बी और सी ग्रेड में रखा

लौट आया आईपीएल



रेवेन्यू में 100 प्रतिशत की बढ़ोतरी

एक रिपोर्ट के मुताबिक, 2018 में बीसीसीआई ने इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड के साथ शेयर होने वाले रेवेन्यू में 100 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी थी। इससे बीसीसीआई पर करीब 25 करोड़ रुपए का खर्चा बढ़ गया था। बीसीसीआई सबसे ज्यादा 19.13 करोड़ रुपए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को देता है। आईपीएल में सबसे ज्यादा विदेशी खिलाड़ी भी ऑस्ट्रेलिया के ही खेलते हैं। इस साल 17 ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी खेल रहे हैं। नेपाल क्रिकेट बोर्ड को बीसीसीआई की तरफ से 4 लाख रुपए मिलते हैं। नेपाल का सिर्फ एक ही खिलाड़ी आईपीएल खेलता है, जिसे 20 लाख रुपए में खरीदा है। आईपीएल से पाकिस्तान के खिलाड़ियों को भी 12 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले हैं। 2008 में आईपीएल के पहले सीजन में 11 पाकिस्तानी खिलाड़ी भी खेले थे, जिन्हें 12.84 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। लेकिन, उसके बाद से आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर रोक लगा दी गई।

गया है। ए+ ग्रेड में 7 करोड़ रुपए, ए ग्रेड में 5 करोड़, बी ग्रेड में 3 करोड़ और सी ग्रेड में सालाना 1 करोड़ रुपए मिलते हैं। इनके अलावा मैच फीस अलग से मिलती है। टीम इंडिया के खिलाड़ियों को एक टेस्ट मैच खेलने के लिए 15 लाख रुपए, वनडे मैच के लिए 7 लाख रुपए और टी-20 मैच के लिए 5 लाख रुपए मिलते हैं।

अक्टूबर-नवंबर में होने वाले टी-20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को लीग के 5 मैच खेलने थे। उसके बाद अगर टीम सेमीफाइनल और फाइनल भी खेलती, तो 7 मैच ही होते। हर मैच से 5 लाख रुपए ही मिलते, तो इस हिसाब से विराट कोहली को वर्ल्ड कप से 25 लाख से 35 लाख रुपए मिलते। लेकिन, आईपीएल में हर मैच के लिए ही उन्हें इससे 4 से 5 गुना रकम मिल रही है। आईपीएल से बीसीसीआई को जितनी कमाई होती है, उतनी कमाई उसे टीम इंडिया के सालभर होने वाले टूर्नामेंट से भी नहीं होती। जब इस साल आईपीएल के रद्द होने की बात हो रही थी, तब बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली ने कहा था कि अगर आईपीएल रद्द होता है, तो इससे बोर्ड को 4 हजार करोड़ रुपए का नुकसान होगा।

बोर्ड को हर साल 3 हजार 269 करोड़ रुपए ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से मिलते हैं। स्टार ने आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स 5 साल के लिए 16,347.5 करोड़ रुपए में खरीदे हैं। एक मैच के लिए स्टार बीसीसीआई को 55 करोड़ रुपए देता है यानी हर बॉल पर 23.3 लाख रुपए। स्टार के अलावा वीवो ने भी 5 साल के लिए आईपीएल की टाइल स्पॉन्सरशिप 2 हजार 199 करोड़ रुपए में हासिल की है। यानी हर सीजन के लिए वीवो बोर्ड को 239 करोड़ रुपए देता है।

ग्लोबल एडवाइजर कंपनी डफ एंड फेलप्स ने सितंबर 2019 में आईपीएल की ब्रांड वैल्यू को लेकर एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक, आईपीएल की ब्रांड वैल्यू 2018 की तुलना में 2019 में 13.5 प्रतिशत बढ़ गई थी। 2018 में आईपीएल की ब्रांड वैल्यू 41 हजार 800 करोड़ रुपए थी, जो 2019 में बढ़कर 47 हजार 500 करोड़ रुपए हो गई थी। न सिर्फ आईपीएल, बल्कि इसमें खेलने वाली टीमों की ब्रांड वैल्यू भी लगातार बढ़ रही है। सबसे ज्यादा 809 करोड़ रुपए की ब्रांड वैल्यू मुंबई इंडियंस की है। उसके बाद चेन्नई सुपरकिंग्स है। आईपीएल न होने से सिर्फ बीसीसीआई को ही नुकसान नहीं होता, बल्कि दूसरे देशों को भी नुकसान होता। आईपीएल में 60 से ज्यादा विदेशी खिलाड़ी खेल रहे हैं। इन खिलाड़ियों को करीब 250 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। न सिर्फ खिलाड़ियों को, बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड को भी पैसा मिलता है। बीसीसीआई आईपीएल से मिलने वाले रेवेन्यू का कुछ हिस्सा अलग-अलग क्रिकेट बोर्ड के साथ शेयर करता है।

● आशीष नेमा



मोहल्ले-पड़ोस के सभी लोग कवि के इस पवित्र गुण और चरित्र से भली-भांति सुपरिचित हैं, इसलिए नमस्ते करके ऐसे दूर भागते हैं जैसे उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव दूर विकर्षित होता है। अपने ही शहर में कवि जी ने कुछ ऐसे चले पाल रखे हैं, जो आए दिन उनके घर पर कवि सम्मेलन का आयोजन कर मोहल्ले वालों की नींद खराब करते हैं। प्रायः कवि निशाचर जो होते हैं न! इसलिए उनके आयोजन रात में रतजगा करते हुए ही संपन्न होते हैं। मोहल्ले वालों को इसमें कोई रुचि नहीं है। इसलिए कवि जी उनके लिए एक ही जुमला प्रयोग करते हुए देखे जाते हैं, भैंस के आगे बीन बजाई, भैंस खड़ी पगुराय।

वे अपने को कवि कहते हैं। कहते ही नहीं अपने नाम से पहले लिखते भी हैं। जब वे कवि हैं तो

कवि जी !

भला किसकी जुर्रत है कि उन्हें कोई कवि न कहे, कवि की मान्यता न दे। अपने पूरे मोहल्ले में तो कवि जी, कवि जी का हल्ला मचा ही रहता है, पूरे शहर में भी लोग उनका असली नाम भूल गए हैं। उनका उपनाम ही उनका पता है। यदि बाहर से कोई उनका नाम लेकर उनके पास पहली बार आता है, तो उनके असली नाम से तो कोई उन्हें बता ही नहीं पाता कि श्री अशर्फी लालजी कहां निवास करते हैं। जब तक कोई कवि श्री अशर्फी लाल जी नहीं कहता, तब तक उनका नाम पता बताना ऐसा हो जाता है जैसे गधों के झुंड में अपना गधा ढूंढ पाना!

जब कोई उन्हीं जैसा हुआ तो गनीमत है कि जब तक उनके पास आने वाला इच्छा या अनिच्छा से दस बीच रचनाएं सुन नहीं लेता, तब तक वे पानी की भी नहीं पूछते। हां, यदि कोई बेशर्मी से पानी मांग भी लेता है तो पानी आने में ही चार-पांच रचनाएं सुन लेना आम बात है। कवि जी की रचनाओं को सुनने में कोई रूचि रखता हो या नहीं, इस बात से कवि जी को कोई रूचि नहीं। उन्हें तो बस अपनी कविताएं सुनानी हैं तो बस सुनानी ही हैं। बस आप वाह! वाह!! क्या बात कही है! आप तो आप ही हैं, आपने तो तुलसीदास, सूरदास को भी पीछे छोड़ दिया। आप तो आज के तुलसी हो, बिहारी हो। जैसे अनेक प्रशंसात्मक वाक्य कहते रहिए और उनकी कविताओं के अगाध सागर में गोते लगाते रहिए। बेचारा आने वाला उनकी कविता सुनकर यह भी भूल जाता है कि वह किस काम से आया था।

यदि कोई अरसिक व्यक्ति उनके पास आया तो भी उसे कविता तो सुननी ही पड़ेगी। उनकी देहरी से निकलने के बाद ऐसा आगंतुक पुनः लौटकर भी उनके दरवाजे की ओर नहीं देखता कि कहीं फिर से आवाज देकर न बुला लें और पुनः काव्यालाप न शुरू कर दें। वह फिर कभी भी कवि जी के पास नहीं आने की कसम लेकर ही उनसे पीछा छुड़ाता है।

मोहल्ले-पड़ोस के सभी लोग कवि के इस पवित्र गुण और चरित्र से भली-भांति सुपरिचित



हैं, इसलिए नमस्ते करके ऐसे दूर भागते हैं जैसे उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव दूर विकर्षित होता है। अपने ही शहर में कवि जी ने कुछ ऐसे चले पाल रखे हैं, जो आए दिन उनके घर पर कवि सम्मेलन का आयोजन कर मोहल्ले वालों की नींद खराब करते हैं। प्रायः कवि निशाचर जो होते हैं न! इसलिए उनके आयोजन रात में रतजगा करते हुए ही संपन्न होते हैं। मोहल्ले वालों को इसमें कोई रूचि नहीं है। इसलिए कवि जी उनके लिए एक ही जुमला प्रयोग करते हुए देखे जाते हैं, भैंस के आगे बीन बजाई, भैंस खड़ी पगुराय।

यह तो हुई एक कवि जी की बात। इस शहर में ऐसे अनेक कवि उपाधिधारी मानव जीवन-यापन करते हैं। जिनके अपने-अपने तखल्लुस हैं, कोई टोंटी है, कोई ढप, कोई बगला कोई हंस, कोई दादू है कोई चाचू, कोई उत्कृष्ट है, कोई प्रकृष्ट। निकृष्ट कोई नहीं है। एक से बढ़कर एक उपनाम धारी कवि और कवयित्रिया। कवयित्रियों के उपनाम भी एक से बढ़कर एक हैं, जैसे चोंची, स्माइल, तबस्सुम, खुशबू, आराध्या और बहुत से मनोहर नाम, उपनाम। इन कवियों के अपने-

अपने गुप हैं, जो प्रायः जाति आधारित हैं। इसलिए वे सब चाहे जैसी रचना करें, उनका नाम चमकना ही है। उन्हें तरह-तरह के सम्मान पत्रों से सम्मनित करना मंच का पावन अधिकार है। वे सब के सब हंस हैं, उनमें कोई भी कागा नहीं है। यदि दुर्भाग्यवश कोई अन्य जाति वाची उनमें सम्मिलित हो जाता है तो उसका स्थान किसी टिटहरी या कौवे से अधिक नहीं होता।

यह देश का सौभाग्य है कि देश में हजारों जातियां हैं, इसलिए कवि कवयित्रियां भी लाखों-करोड़ों में हैं। एक-एक गली से लारी भर कलमकार मिलना सामान्य बात है। देश में हजारों लारियां भर सकती हैं। वे अपने काव्यगत वीररस से समुद्र में लहरें पैदा कर रहे हैं, पर दुर्भाग्य कि कविताओं से गोलियां नहीं निकलतीं। धुआं भी नहीं पैदा हो पाता तो किसी दुश्मन को कैसे मार पाएंगे। हमारे मान्यवर कवि जी श्री अशर्फी लालजी भी देश के ऐसे ही हीरा हैं, जिनकी शब्दराशि से बारूद की सुगंध वातावरण में व्याप्त हो जाती है।

● डॉ. भगवत स्वरूप 'शुभम'

विश्वसनीय खबरों के लिए पढ़ते रहिए

In Pursuit of Truth

आक्ष

पाक्षिक



E-Magazine पढ़ने और PDF डाउनलोड करने के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं
www.akshnews.com

वार्षिक सदस्यता के लिए संपर्क करें, 150, जोन-1, एम.पी.नगर भोपाल
फोन: 0755-4017788, 2575777

0-17006

For Any Medical & Pathology Equipments Contact Us



Science House Medicals Pvt.Ltd.

17/1, Sector-1, Shanti Niketan, Near Chetak Bridge
Bhopal (M.P.) INDIA-462023

GST. No. : 23AAPCS9224G1Z5 Email : shbpl@rediffmail.com

PH. : +91-0755-4241102, 4257687, Fax : +91-0755-4257687

